संपादकीय जागरण

बुधवार, 4 फरवरी, 2026 : फाल्गुन कृष्ण - 3 वि. 2082

धैर्य का परिणाम सदैव सुखद होता है

बन गई बिगड़ी बात

अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को 18 प्रतिशत किए जाने की घोषणा और उसका भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से स्वागत करने से यह स्पष्ट हो गया कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को यह आभास हो गया कि भारत उनके अनुचित दबाव में झुकने वाला नहीं है। उन्होंने भारत को दबाव में लेने के लिए तमाम जतन किए, लेकिन वे इसलिए नाकाम रहे, क्योंकि भारत ने उनसे उलझने के स्थान पर संयम और दृढ़ता का परिचय दिया। 18 प्रतिशत टैरिफ का मतलब है कि भारत अमेरिका से व्यापार के मामले में अपने कई प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में होगा। ट्रंप ने भारत पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को 25 से 18 प्रतिशत तो किया ही, रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को पूरी तरह हटाया भी। उन्होंने इसी के साथ यह भी कहा कि भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और रूस से तेल आयात बंद करेगा। उनकी इस घोषणा के पहले भारतीय प्रधानमंत्री की वेनेजुएला की राष्ट्रपति से बात हुई थी। शायद इसके बाद ही अमेरिका से व्यापार समझौते को लेकर बिगड़ी बात बनी। यदि भारत को उचित मूल्य पर वेनेजुएला से तेल मिलता है तो इसमें हर्ज नहीं। आखिर वह पहले भी उसके साथ-साथ ईरान से तेल खरीदता ही था।

भारत के लिए यह संभव नहीं था कि वह रूस से तेल खरीद का विकल्प मिले बिना उससे तेल लेना बंद कर देता। देखना है कि भारत को उतना तेल वेनेजुएला से मिल पाता है या नहीं, जितना वह रूस से लेता था? इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी सामने आना शेष है कि क्या भारत को अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ शून्य करना होगा और क्या अमेरिका से 500 अरब डालर की खरीद करनी होगी, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं। वास्तव में कई सवालों के जवाब तभी सामने आएंगे, जब व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, लेकिन इतना तो है ही कि अमेरिका से व्यापार का जो दरवाजा बंद सा हो गया था, वह खुल गया और भारत के तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब देश में कारोबारी माहौल सुधरेगा। शेयर बाजार ने इसके संकेत देने भी शुरू कर दिए हैं। चूंकि ट्रंप बढ़-चढ़कर दावा करते रहते हैं, इसलिए यह मानकर चला जाना चाहिए कि अमेरिका से व्यापार समझौता ठीक वैसा नहीं होगा, जैसा वे कह रहे हैं। इसका संकेत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस कथन से मिलता है कि भारत अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर व्यापार समझौता करने जा रहा है। अच्छा हो कि इस समझौते को अंतिम रूप देते समय अमेरिका को यह संदेश दे दिया जाए कि उसने पिछले छह माह में भारत से जैसा व्यवहार किया, उसके चलते उस पर भरोसा डिगा है।

उचित कदम

दिल्ली में गैर नियोजित यानी अनधिकृत रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट को लेकर सर्वे कराने संबंधी दिल्ली सरकार का कदम सर्वथा उचित है। यमुना को स्वच्छ करने के लिए इन औद्योगिक केंद्रों से निकलने वाले अपशिष्ट की मात्रा और प्रकृति का पता लगाना बेहद आवश्यक है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) को इसके लिए नियुक्त करते हुए सरकार ने यह भी पता करने को कहा है कि यहां से निकलने वाले अपशिष्ट के उपचार के लिए पर्याप्त क्षमता के उपचार संयंत्र हैं भी या नहीं।

> दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही इकाइयों में वायु प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए

राजधानी में नियोजित तरीके से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने के बावजूद 27 औद्योगिक क्षेत्र अनधिकृत तौर पर बन जाना निराशाजनक है । इन औद्योगिक क्षेत्रों में तमाम नियम कायदों को धता बताते हुए इकाइयां चलाई जा रही हैं, जिनसे निकलने वाला अधिकतर अपशिष्ट बिना उपचारित किए यमुना में गिरकर उसे प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में अपशिष्ट के उपचार की उचित व्यवस्था की ही जानी चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही इकाइयां वायु प्रदूषण संबंधी नियम कानूनों का पालन भी करें, ताकि यमुना को स्वच्छ करने के साथ ही इनसे होने वाले वायु प्रदूषण पर भी रोक लगे।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आइसीसी को श्रीलंका में भारत के खिलाफ न खेलने के फैसले के कारण पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए?

आज का सवाल

क्या ट्रंप टैरिफ घटने से भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना आसान होगा?

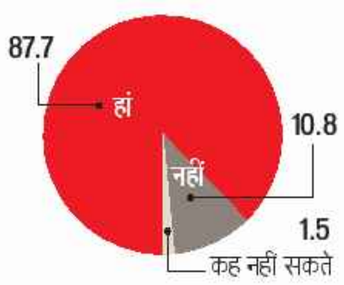

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अमेरिका के साथ एक नई शुरुआत

डा. मनिष दभाडे

ट्रंप द्वारा टैरिफ को 50 से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय मात्र एक आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि मोदी की विदेश नीति की दृढ़ता की पुष्टि भी है

पहले यूरोपीय संघ के साथ बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर और उसके कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका के साथ एक तरह के व्यापार युद्ध में संघर्षविराम की स्थिति निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। उनके लिए नए साल की इससे बेहतर शुरुआत शायद ही हो सकती थी। खास तौर से तब जब पिछला साल कूटनीतिक तनाव, आपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध की आशंका और अमेरिका के साथ खटपट के नाम रहा। इस संदर्भ में अमेरिका के साथ बिगड़ी हुई बात का बनना बहुत कुछ कहता है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत के टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय मात्र एक आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि यह मोदी की विदेश नीति की महत्वाकांक्षा और दृढ़ता की पुष्टि भी है। जब तमाम विश्लेषक यह मान बैठे थे कि ट्रंप 2.0 के दौर में भारत को लगातार दबाव और अपमान झेलना पड़ेगा, उसी दौरान मोदी ने धैर्य, रणनीति और आत्मविश्वास के साथ स्थिति को पलट दिया। यह समझौता दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है।

देखा जाए तो मोदी ने वह कर दिखाया जो तमाम वैश्विक नेता नहीं कर सके। मोदी ने ट्रंप की कुख्यात 'द आर्ट आफ द डील' रणनीति को समझा और उसे भारत के हित में साध लिया। ट्रंप की सौदेबाजी बेहद आक्रामक, दबाव बनाने वाली और अतिरंजित दावों पर आधारित रही है। कनाडा, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी भी उनकी इस शैली के सामने अक्सर रक्षात्मक स्थिति में दिखे। स्वयं भारत ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक सीमित व्यापार समझौते की कोशिश में विफल रहा था, लेकिन इस बार मोदी ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही आत्मसमर्पण किया। उन्होंने ट्रंप को वह राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की गुंजाइश दी, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति व्यग्र थे। जबकि वास्तविक लाभ भारत के खाते में गया। यह मोदी की कूटनीतिक परिपक्वता और आत्मविश्वास का प्रमाण है।

टैरिफ कटौती के बीच ट्रंप ने एकतरफा दावे भी किए। जैसे भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर देगा। भारत अमेरिकी उत्पादों की 500 अरब डालर तक की खरीद करेगा और अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं शून्य कर देगा। ये दावे जितने नाटकीय हैं, उतने ही अव्यावहारिक भी प्रतीत होते हैं। भारत का अमेरिका से कुल वार्षिक

अवनीश राजपूत

आयात करीब 50 अरब डालर से भी कम है। 500 अरब डालर का आंकड़ा नीति से अधिक राजनीतिक नारेबाजी जैसा अधिक है। कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत का पूर्ण उदारीकरण घरेलू राजनीति और सामाजिक स्थिरता के लिहाज से वैसे भी असंभव है। मोदी का इन बिंदुओं पर मौन रहना दर्शाता है कि भारत इस समझौते को एक दिशात्मक संकेत के रूप में देख रहा है, न कि अंतिम और बाध्यकारी समझौते के रूप में। अपने स्वरूप में यह घटनाक्रम किसी ठोस समझौते से अधिक एक राजनीतिक ब्रेकथ्रू है। यह ट्रंप प्रशासन की उसी प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसमें पहले बड़े एलान किए जाते हैं और बाद में विवरण तय होते हैं। अतीत में यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के साथ भी ऐसे 'फ्रेमवर्क समझौतों की घोषणा हुई, जिनका क्रियान्वयन जटिल और लंबा साबित हुआ। भारत-अमेरिका समझौता भी इसी श्रेणी में आता है। इसमें तनाव घटाने, व्यापार बहाली और रणनीतिक खाई को पाटने जैसे लक्ष्य तो स्पष्ट हैं, लेकिन विवरण अभी शेष हैं। कभी-कभी कूटनीति में दिशा तय करना ही सबसे कठिन कार्य होता है। अमेरिका के दबाव में झुकने के बजाय भारत ने पिछले एक वर्ष में अपने विकल्प भी बढ़ाए। रूस के साथ ऊर्जा सहयोग, चीन के साथ सीमित राजनीतिक संवाद और सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। इस क्रम में यदि वाशिंगटन भारत के साथ व्यापारिक टकराव जारी रखता तो अमेरिकी कंपनियां दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार से बाहर हो जातीं। यही वह बिंदु है, जिसने अमेरिका को अड़ियल रुख से पीटे हटने को विवश किया। इसमें यूरोपीय संघ के साथ समझौते ने निर्णायक भूमिका निभाई। अमेरिकी रुख में परिवर्तन भारत के लिए भी बड़ी राहत है, क्योंकि उसके 50 प्रतिशत टैरिफ ने भारत को एक बड़े बाजार में सीमित कर दिया था। अमेरिकी टैरिफ का 18 प्रतिशत पर आना न केवल भारतीय निर्यातकों के लिए राहत है, बल्कि यह भारत को फिर से एशियाई प्रतिस्पर्धियों की पंक्ति में खड़ा करता है। इसके चलते वस्त्र, परिधान, रत्न और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को संजीवनी मिलेगी। चीन से बाहर निकल रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भारत फिर से एक व्यावहारिक विकल्प बन सकता है। उच्च टैरिफ के चलते जो अवसर भारत के हाथ से फिसल रहे थे, वे फिर से मुट्ठी में आ सकते हैं। अमेरिका के साथ बढ़ती निकटता चीन को भी यह संदेश देगी कि भारत के पास रणनीतिक विकल्प हैं। हालांकि मोदी की विदेश नीति का मूल तत्व अब भी रणनीतिक स्वायत्तता है। यह समझौता उस स्वायत्तता को त्यागने का नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने का साधन है।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौता एक नई शुरुआत है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं। इसके सामने अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। अवसर इसलिए कि यदि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो भारत-अमेरिका संबंध वास्तव में वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। चुनौतियां इसलिए कि विवरणों में मतभेद, घरेलू दबाव और ट्रंप की अप्रत्याशित राजनीति इस प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है। इसके बावजूद मोदी को श्रेय देना आवश्यक है। उन्होंने दिखाया कि भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। यह समझौता मोदी के उस दीर्घकालिक सोच का प्रतीक है, जिसमें भारत को एक आत्मविश्वासी, विकल्पों से भरपूर और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया जाना है। भारत अब किसी भी सौदे में शर्तें तय करने के लिहाज से कहीं बेहतर स्थिति में है।

(लेखक जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर एवं 'द इंडियन फ्यूचर्स' के संस्थापक हैं)
response@jagran.com

आखिर कब निकाले जाएंगे घुसपैठिए

राजीव सचान

यह ठीक नहीं कि केवल चुनावों के समय घुसपैठियों की चर्चा की जाए और फिर कुछ न किया जाए

नकली आधार के साथ पकड़े गए घुसपैठिए ● फाइल

जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उभरा था। उसके पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी घुसपैठियों को बड़ा खतरा बताया गया था। चूंकि असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए एक बार फिर घुसपैठियों की चर्चा हो रही है। पिछले दिनों बंगाल गए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बन जाए तो घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकाला जाएगा। इसके पहले उन्होंने असम में कहा था कि यदि इस राज्य में तीसरी बार भाजपा सरकार बन जाए तो घुसपैठियों को निकालने में देर नहीं होगी। इसका अर्थ है कि असम में पिछले लगभग दस वर्षों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने का काम नहीं किया जा सका। हर किसी को पूछना चाहिए आखिर क्यों? यह ठीक नहीं कि केवल चुनाव के समय घुसपैठियों की चर्चा की जाए और फिर कुछ न किया जाए। इससे तो घुसपैठिए और उन्हें घुसाने वाले सतर्क ही होते होंगे।

बांग्लादेशी घुसपैठियों से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में असम है। बांग्लादेशी असम के अलावा मेघालय और त्रिपुरा के रास्ते से भी घुससैठ करते हैं। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाला घुसपैठिया मेघालय के रास्ते ही मुंबई आया था। बांग्लादेशी घुसपैठिए सीमावर्ती राज्यों में घुसकर इसलिए दूसरे राज्यों में जाने में सफल रहते हैं, क्योंकि वे कोई न कोई फर्जी पहचान पत्र हासिल कर लेते हैं। इसके बाद उनका काम आसान हो जाता है। पूर्वोत्तर और बंगाल में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली तक में बस गए हैं। यदा-कदा कुछ राज्य सरकारें उनकी पहचान करने का अभियान चलाती हैं, लेकिन अभी तक कोई अभियान प्रभावी नहीं सिद्ध हो सका है। आपरेशन सिंदूर के दौरान गुजरात में हजारों बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। यह स्वाभाविक ही है कि इस अभियान के समय तमाम बांग्लादेशी अन्य राज्यों में खिसक गए होंगे। जो कहानी बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, वही रोहिंग्याओं की भी है। रोहिंग्या भी पूर्वोत्तर और बंगाल के रास्ते घुसपैठ करने के बाद जिस तरह दिल्ली, हैदराबाद और जम्मू तक में अपने ठिकाने बनाने में सफल हैं, उससे यह साफ है कि उन्हें भारत में लाने और बसाने का काम सुनियोजित तरीके से हो रहा है। इस काम में लिप्त लोग घुसपैठियों को फर्जी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का भी काम करते हैं। ऐसा काम करने वाले बंगाल में खूब सक्रिय हैं।

निःसंदेह घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यह भी सही है कि यदि राज्य सरकारें इस काम में केंद्र का सहयोग नहीं करतीं तो घुसपैठियों की पहचान आसान नहीं। बंगाल सरकार का यह कहना तो ठीक है कि यदि घुसपैठ हो रही है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लेकिन केंद्र के इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि राज्य प्रशासन की ओर से घुसपैठियों को लेकर कभी कोई शिकायत क्यों नहीं की जाती? तथ्य यह है कि बंगाल के किसी भी थाने से कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलती कि बांग्लादेश से किसी ने अवैध तरीके से प्रवेश किया है। शिकायत इसलिए भी नहीं मिलती, क्योंकि स्थानीय नेता घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। एक समय ममता बनर्जी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाती थीं, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद से वे घुसपैठियों को चिह्नित करने की किसी भी पहल का विरोध करती हैं। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआइआर के विरोध की एक बड़ी वजह यही आशंका है कि कहीं इससे घुसपैठियों की पहचान न हो जाए। बंगाल में एसआइआर की प्रक्रिया शुरू होते ही सैकड़ों बांग्लादेशी अपने देश लौटने लगे थे। कुछ समय बाद उनके लौटने का सिलसिला थम गया। कोई भी समझ सकता है कि यह इसीलिए थमा, क्योंकि उन्हें यह भरोसा हो गया होगा कि इस कवायद से उनकी पहचान नहीं होने वाली। हैरानी नहीं कि उनके संरक्षक नेताओं ने ही उन्हें यह भरोसा दिलाया हो कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। जो भी हो, इससे इन्कार नहीं कि भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। असम और बंगाल में तो उनकी इतनी संख्या हो गई है कि उन्होंने न केवल आबादी के संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ दिया है, बल्कि वे कई क्षेत्रों में चुनाव परिणाम प्रभावित करने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि वे छल-कपट से मतदाता बन गए हैं।

घुसपैठिए केवल देश के संसाधनों पर बोझ ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी हैं। अब यह खतरा और अधिक गंभीर हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे और इसका भरोसा नहीं कि वहां की नई सरकार की भारत से संबंध सुधारने में दिलचस्पी होगी। इन दिनों पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना हितैषी दिखाने के लिए न केवल हरसंभव जतन कर रहा है, बल्कि उसे भारत के खिलाफ उकसा भी रहा है। इन स्थितियों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान कर उन्हें निकालने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया ही जाना चाहिए। जब नागरिकता कानून में संशोधन किया गया था, तब यह कहा गया था कि उसे लागू करने के बाद राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अर्थात एनआरसी का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसे किसी अभियान की कोई चर्चा नहीं। हर किसी को पूछना चाहिए आखिर क्यों?

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

सुदृढ़ संगति

चरित्र कोई स्थिर शिला नहीं, जिसे एक बार गढ़ दिया जाए और वह युगों तक वैसा ही बना रहे। वह तो एक निरंतर प्रवाहमान चेतना है, जो संवेदनाओं, निर्णयों, स्व-अनुशासन और संगति से निर्मित होती है। इसीलिए यदि अपना चरित्र सुदृढ़ रखना है, तो प्रश्न केवल आत्मानुशासन का नहीं, संगति का भी है। सुदृढ़ व्यक्तित्व कोई उपदेशक नहीं होता। वह अपनी उपस्थिति से ही ऐसा नैतिक ताप उत्पन्न करता है कि शब्द अनावश्यक हो जाते हैं और जीवन स्वयं अर्थवान लगने लगता है। ऐसी संगति में व्यक्ति अपने भीतर की शिथिलताओं को पहचानता है। ऐसी शिथिलताएं जो अकेले में तर्क बनकर हमें छलती रहती हैं। सुदृढ़ व्यक्तित्व के सान्निध्य में आत्मप्रवंचना टिक नहीं पाती। वहां अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो जाता है-मैं कौन हूं और जैसा हूं, क्या वही होना मेरा अंतिम विकल्प है?

चुनाव को वरीयता देने वाला व्यक्ति समाज से पलायन करने वाला नहीं, बल्कि समाज के भीतर रहकर भी अपने आंतरिक सुदृढ़ स्वातंत्र्य को अक्षुण्ण रखने की आकांक्षा वाला व्यक्ति है। सुदृढ़ संगति एक तपश्चर्या है। उसकी दृष्टि में हमारी निर्बलताएं तुरंत उजागर हो जाती है। यही असहजता हमारे चरित्र का व्याकरण रचती है।

दुर्बल संगति में चरित्र शिथिल हो जाता है। वहां मात्र फिसलन है। हालांकि सुदृढ़ व्यक्तित्व के पास कोई घोषणापत्र नहीं, अपितु एक जिया हुआ सत्य होता है। उसके निकट रहकर हम सीखते हैं कि नैतिकता उपदेश नहीं, अपितु स्वयं को परिष्कृत करने का निरंतर हठ है। इस प्रकार धीरे-धीरे, अनायास ही हमारी चेतना भी उसी कठोर, किंतु पारदर्शी अनुशासन की ओर उन्मुख होने लगती है। चरित्र की रक्षा बाह्य आडंबरों से नहीं, आंतरिक साहचर्य से होती है और यह साहचर्य तभी फलित होता है, जब हम अपने से अधिक दृढ़, अधिक सजग और अधिक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के सान्निध्य का साहस करते हैं।

त्रिवंकल तोमर सिंह

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

विवादों के घेरे में समानता के नियम

'समानता की अनदेखी करने वाले नियम' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. ब्रजेश कुमार तिवारी ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए 'प्रमोशन आफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस-2026' का सटीक विश्लेषण करते हुए सही कहा है कि समता का वास्तविक अर्थ बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ न्याय करना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के चार स्तंभों पर टिका हुआ है। इनमें से किसी भी स्तंभ को कमजोर करने का अर्थ भारतीय संविधान की अनदेखी करना है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के आधार पर होने वाले उत्पीड़न की समस्या के समाधान हेतु जो नए नियम निर्धारित किए गए हैं, वे भारतीय संविधान के मूल तत्व 'समानता' और 'न्याय' दोनों की अनदेखी करने वाले हैं। कदाचित इसीलिए यूजीसी के असंगत नियमों को लेकर भारतीय समाज के एक वर्ग में उत्तेजना पैदा हो रही है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में यदा-कदा छात्रों के बीच वाद-विवाद, झगड़ा-फसाद अथवा किसी बात को लेकर शिक्षकों या विद्यार्थियों का उत्पीड़न होना स्वाभाविक है। ऐसे में विवादित पक्षों को भेदभाव रहित निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा रहती है। यूजीसी की नई नियमावली में इसी मूल बात की अनदेखी की गई है, जिसके व्यापक विरोध के बीच जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसने यूजीसी की असंगत नियमावली पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से इस संबंध में जबाव मांगा है। चूंकि मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है तो यूजीसी नियमों को लेकर उत्तेजित होने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को भी संयमित रहकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार को भी 'समानता' और 'न्याय' के संविधानसम्मत सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हुए यूजीसी को आवश्यक दिशानिर्देश देने चाहिए, ताकि भारतीय समाज में सद्भाव बना रहे।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उप्र)

विश्वसनीय ब्रांड बनना जरूरी

ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने भारत के लिए आयात शुल्क घटाकर 18 प्रतशित करने की घोषणा की है, जिससे व्यापारिक संबंधों में नरमी और निर्यातकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'मेड इन इंडिया' की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का आह्वान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका की नई टैरिफ नीतियों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित कई देशों पर शुल्क लगाए, जिससे भारतीय निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र पर मिश्रित प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऊंचे टैरिफ के बावजूद नवंबर में भारत का निर्यात 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ा, जो बाजार विविधीकरण की रणनीति का संकेत देता है। यह स्पष्ट संकेत है कि केवल सस्ते उत्पादन से नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता, तकनीक और मजबूत घरेलू बाजार के सहारे ही भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकता है। 'मेड इन इंडिया' को विश्वसनीय ब्रांड बनाकर भारत इन चुनौतियों को शक्ति में बदल सकता है।

विभूति बुपक्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली

पाकिस्तान क्रिकेट का डेथ वारंट

सात फरवरी से भारत और श्रीलंका में टी-20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। जब आइसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसमें सबसे हाई लेवल का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो भारत व पाकिस्तान का मैच कोई मैच नहीं एक युद्ध बन गया हो। दोनों तरफ के खिलाड़ी एक-दूसरे को हराने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देते हैं। भारत व पाकिस्तान के मैच का इंतजार सिर्फ भारत व पाकिस्तान की आम जनता ही नहीं बल्कि पूरी दुनियां करती है। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच होने से सिर्फ खेल स्तर का मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि आइसीसी और ब्राडकास्टर को अच्छी-खासी कमाई भी होती है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी धूर्तता राजनीतिक के साथ खेल (क्रिकेट) में भी दिखाना शुरू कर दी है और भारत के साथ 15 फरवरी को होने वाला अपना मैच ना खेलने का निर्णय लिया है। उसका यह फैसला कहीं न कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है क्योंकि इस फैसले के बाद पाकिस्तान परआइसीसी के तरफ से कड़े फैसलों का जो असर होगा, वह पाकिस्तान क्रिकेट की आर्थिक रूप से कमर तोड़ कर रख देगा। पाकिस्तान भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए शायद अपना बचपना छोड़कर वापस भारत के साथ खेलने के बारे में सोचे, नहीं हो पाकिस्तान क्रिकेट अपनी तबाही के लिए तैयार रहे।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

पोस्ट

पश्चिमी मीडिया संस्थान एपस्टीन फाइल्स पर डाक्युमेंट्री क्यों नहीं बना रहे हैं? निर्भया के समय तो वे दौड़े-दौड़े भारत आए थे। भावना अरोड़ा@BhaavnaArora

मेरे लिए विश्व कप का अर्थ वनडे विश्व कप ही है। हर दो साल में होने वाले टी-20 प्रारूप को चार साल में होने वाले विश्व कप जैसा दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए उसका मूल नाम वर्ल्ड टी-20 ही सही रहेगा। संजय मांजरेकर@sanjaymanjrekar

एकाएक भारतीय मैन्यूफैक्चरिंग के लिए बहुत अच्छे दिन दिखने लगे हैं। यूरोपीय संघ के साथ बड़ा व्यापार समझौता हुआ ही था कि अमेरिका ने टैरिफ घटाकर भारतीय उत्पादों को आकर्षक बना दिया है। बजट में भी उद्योगों के अनुकूल कई घोषणाएं हैं। सरकार ने सुधारों का सिलसिला जारी रखने का संकल्प भी जताया है। विक्रम चंद्रा@vikramchandra

भारत ने नोबेल पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम की कभी पैरवी नहीं की, लेकिन फिर भी उसके लिए टैरिफ की दरें पाकिस्तान से कम हो गई हैं। असल में ट्रंप ने अपनी चापलूसी कराने के अलावा पाकिस्तान को दिया ही क्या है? जावेद हसन@javedhassan

जनपथ

झुकती है दुनिया सदा झुका सकें यदि आप,
देखो ताऊ ट्रंप की लिये हैसियत नाप।
लिये हैसियत नाप अकड़ दिखती अब ढीली,
अब उनका व्यवहार हुआ ज्यों माचिस सीली!
सही फार्मुला एक बढ़ाओ अपनी शक्ती,
शक्तिवान को देख हमेशा दुनिया झुकती!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 201

कांग्रेस ने अपने संविधान के विपरीत गठित किए जाति आधारित प्रकोष्ठ

धनंजय प्रताप सिंह ● नईदुनिया

- दिग्विजय सिंह के दलित एजेंडे ने दिया जातिवाद को बढ़ावा
- जीतू पटवारी ने कहा-ये सभी व्यवसाय आधारित प्रकोष्ठ

ये प्रकोष्ठ पहले से बने हुए थे, उन्हीं को पुनर्जीवित किया गया है। संविधान से हटकर संगठन कोई काम नहीं करता है। ये सभी व्यवसाय आधारित प्रकोष्ठ हैं। कारोबार संबंधी समस्याएं स्वयं सुलझा लें इसलिए इनका गठन किया गया है। इसमें सभी धर्मों के लोग हैं। - **जीतू पटवारी,** मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने संविधान के विपरीत काम कर रही है। पार्टी के अपने संविधान के अनुसार, सांगठनिक ढांचे में जाति आधारित इकाइयों के गठन का प्रविधान नहीं है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में संगठन ने सात जाति आधारित प्रकोष्ठ गठित किए हैं। हालांकि, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इसे व्यवसाय संबंधित प्रकोष्ठ बता रहे हैं जबकि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं का मानना है कि यह निर्णय पार्टी के धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। यह चुनावी लाभ के लिए जातिगत राजनीति का हिस्सा है। बता दें कि यूजीसी के समता नियमों के कारण जाति विवाद पर चर्चा ने फिर जोर पकड़ लिया है। हालांकि, इन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब तक कांग्रेस में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आदिवासी विभाग होते हैं लेकिन इस बार प्रदेश कांग्रेस ने समाज समन्वय प्रकोष्ठ के अंतर्गत सात अलग-अलग समाजों के लिए समन्वयक नियुक्त किए हैं। इनमें बंगाली समाज के समन्वयक मिथुन विश्वास, बंजारा समाज समन्वयक मांगीलाल नायक,तैलिक-साहू- राठौर समाज समन्वयक हितेष साहू, सर्व विश्वकर्मा समाज कल्याण समन्वयक रमेश चंद्र विश्वकर्मा, स्वर्ण कला समन्वयक राम मनोहर सोनी, कोली-कौरी समाज समन्वयक पूनम वर्मा व रजक समाज का समन्वयक संजय मालवीय को नियुक्त किया है।

जाति-धर्म की राजनीति करने वाले दलों पर रोक का प्रविधान नहीं : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजनीतिक दलों की जातीय रैली के विरुद्ध दाखिल जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया है कि मौजूदा कानूनों के तहत किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को केवल इस आधार पर चुनाव लड़ने से पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता कि वह जाति या धर्म के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि यह विषय विधायिका का है कि वह इस संबंध में कानून बनाए। चुनाव आयोग भी किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण इस आधार पर समाप्त नहीं कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से वर्ष 2013 में दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8-ए ही एकमात्र प्रविधान है, जिसके तहत चुनावी कदाचार के मामलों में अयोग्य ठहराया जा सकता, वह भी तब जब संबंधित व्यक्ति को दोषसिद्ध करार दिया जा चुका हो।

मोमोज के बदले छात्र से गहने चोरी कराने वालों में महिला भी थी, जेल गई

- मुख्य आरोपित की मां ने ही सराफा के यहां बेचे थे किशोर से हड़पे गहने
- देवरिया के किशोर ने घर से 85 लाख रुपये के आभूषण चुराकर दे दिए थे

जागरण संवाददाता, देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सातवीं कक्षा के छात्र को मोमोज खिलाने के बदले घर से 85 लाख रुपये के आभूषण चुराने के लिए बाध्य करने वालों में महिला भी शामिल थी। पूछताछ के बाद पुष्टि होने पर रामपुर कारखाना पुलिस ने मंगलवार को लीलावती देवी और राकेश कुमार को जेल भेज दिया। घर में चोरी करने वाले किशोर को बाल सुधार गृह भेजा गया है। गिरफ्तार महिला के बताने पर पुलिस ने लगभग ढाई लाख रुपये के गहने बरामद कर लिए हैं। मुख्य आरोपित और शेष गहनों की तलाश चल रही है। रामपुर कारखाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 25 जनवरी को उनके नाबालिग पुत्र ने घरवालों को बिना बताए लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण रामपुर कारखाना कस्बे के रहने वाले दीपक कुमार, राकेश कुमार और पिंटू को दे दिए। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आभूषण हड़पने में दीपक कुमार की मुख्य भूमिका थी। उसकी मां लीलावती ने देवरिया सेंट्रल चौकी के समीप स्थित सराफा दुकान पर आभूषण बेचे थे।

पुलिस ने मंगलवार को डुमरी तिराहे के पास राकेश कुमार और लीलावती को गिरफ्तार कर लिया। सराफा की दुकान से कई आभूषण बरामद कर लिए। दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पीड़ित व्यक्ति के नाबालिग पुत्र को बाल सुधार गृह भेजा गया है। थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपित दीपक फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है।

एक नजर में

सेलिना जेटली के भाई के लिए ला-फर्म को करें अधिकृत : हाई कोर्ट

नई दिल्ली: एक साल से अधिक समय से यूनाइडेट अरब अमीरात (यूएई) में हिरासत में रखे गए फिल्म अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत जेटली का प्रतिनिधित्व करने के लिए दुबई की एक ला-फर्म को अधिकृत करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि अगर विदेश मंत्रालय के पास ऐसे प्राधिकृत न करने का कोई कारण है, तो 10 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में इसे रिकार्ड पर पेश किया जाए। अदालत ने कहा कि ला-फर्म अभिनेत्री के भाई को मुफ्त सेवाएं देने को तैयार है और उन्हें भी इस फर्म द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। (जासं)

कुलदीप सेंगर की अपील याचिका पर 11 से होगी प्रतिदिन सुनवाई

नई दिल्ली: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भाजपा से निलंबित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 11 फरवरी से प्रतिदिन सुनवाई करेगा। मंगलवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने इस निर्देश के साथ मामले को 11 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को 10 साल की सजा की सजा सुनाई थी और वह सात साल से ज्यादा समय से जेल में है। (जासं)

मुंबई एयरपोर्ट पर विमानों के विंगटिप्स टकराए

सभी यात्री सुरक्षित, विमानों को किया ग्राउंड

मुंबई हवाईअड्डे के टैक्सीवे पर इंडिगो व एअर इंडिया के विमानों के टकराते पंख ● प्रेट्र

मुंबई, प्रेट्र: मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम बड़ी लापरवाही सामने आई जब रनवे के पास टैक्सीवे पर एअर इंडिया और इंडिगो के दो विमानों के पंख (विंगटिप्स) टकरा गए। हालांकि, सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद दोनों विमानों को ग्राउंड कर दिया गया है यानी इन दोनों विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया है।

जब एअर इंडिया का विमान टैक्सीवे पर उड़ान भरने के लिए इंतजार कर रहा था, तभी इंडिगो का विमान हवाईअड्डे पर लैंडिंग के बाद विमान खड़ा होने जा रहा था। जिस जगह पर विंग्स टकराए वहां जहां समानांतर रनवे हैं। दोनों विमान एयरबस ए320 थे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि विमानन नियामक डीजीसीए की टीम घटना स्थल पर है और इस मामले की जांच करेगी। एअर इंडिया प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई से कोयंबटूर के लिए उड़ान एआइ 2732 में देरी हुई, क्योंकि सेवा का संचालन करने वाला विमान टैक्सीवे पर उड़ान भरने के लिए इंतजार करते समय दूसरे एयरलाइन के विमान से टकरा गया था। दोनों विमानों के विंगटिप्स के टकराने से एअर इंडिया के विंगटिप को नुकसान हुआ।

इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि हैदराबाद से मुंबई के लिए उड़ान 6ई791 का विंगटिप टैक्सी करते समय दूसरे एयरलाइन के विमान के संपर्क में आया। सभी यात्री सुरक्षित हैं और पार्किंग के बाद यात्री विमान से उतर गए हैं। प्रोटोकाल के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और मामले की जांच की जा रही है।

यह घटना मंगलवार को शाम लगभग 7:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर हुई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जबकि एआइ 2732 सी1 से एम4 की ओर उड़ान भरने के लिए टैक्सी कर रहा था और इंडिगो की आगमन उड़ान बी1 में शामिल होने के लिए टैक्सी कर रही थी, दोनों विमानों के दाएं विंगटिप्स आपस में टकरा गए।

लंदन-बेंगलुरु उड़ान वाले विमान की फ्यूल स्विच में नहीं मिली गड़बड़ी : डीजीसीए

- विमानन नियामक ने कहा, इंजन पैरामीटर, काशन व अन्य संबंधित सिस्टम दुरुस्त पाए गए
- एअर इंडिया ने फिर शुरू की ड्रीमलाइनर बेड़े के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: रविवार को लंदन से बेंगलुरु आ रहे एयर इंडिया के बोइंग 787 'ड्रीमलाइनर' विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। विमानन नियामक डीजीसीए ने प्रभावित विमान की अपनी निगरानी में जांच के बाद ये दावा किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी डीजीसीए की जांच रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए एक बयान में स्पष्ट किया कि जांच के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। वहीं, एअर इंडिया ने एक बार फिर अपने पूरे ड्रीमलाइनर बेड़े के फ्यूल कंट्रोल स्विचों का एहतियाती निरीक्षण शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, गड़बड़ी की शिकायत वाली स्विचों को मूल कंपनी (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरर) को भेजकर बदला जाएगा।

बताया जाता है कि रविवार को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान (एआइ 132) भरने के पहले विमान के बाएं इंजन का फ्यूल कंट्रोल स्विच स्वतः 'कटआफ' मोड में चला गया। पायलटों के मुताबिक फ्यूल स्विच को दो बार 'रन' मोड में लाया गया, लेकिन वह स्वतः 'कटआफ' मोड में लौट आता था। तीसरे प्रयास में स्विच 'रन' मोड में लाक हुआ। बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद इस मामले की रिपोर्ट की गई और पायलटों ने इसे 'लाग बुक' में जोड़ा। जांच के बाद, विमानन नियामक डीजीसीए ने बताया कि विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में किसी तरह की खराबी नहीं पाई गई है और न ही इंजन के सक्रिय रहने या किसी अन्य समय के दौरान इससे जुड़े पैरामीटर, काशन, वार्निंग या अन्य संबंधित सिस्टम में ही कोई शिकायत मिली है।

प्रेट्र के अनुसार, एअर इंडिया के सीन्यिर वाइस प्रेसिडेंट, फ्लाइट आपरेशंस, मनीष उप्पल ने सभी पायलटों को ई-मेल के जरिये इस बाबत सूचित कर दिया है और इंजीनियरिंग टीम ने बोइंग से इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आग्रह किया है। बोइंग से आधिकारिक जवाब मिलने तक सामान्य परिचालन सुनिश्चित करने के लिए फ्यूल कंट्रोल स्विच लैच की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार, एअर इंडिया ने गड़बड़ी वाली स्विच को इसे बनानेवाली मूल कंपनी के पास भेजने का फैसला किया है। बताया जाता है कि स्विच माड्यूल विमान के आपरेशन में रहने के दौरान केवल 3440 घंटे ही प्रयोग में रहा है, जिसे 2024 में विमान में स्थापित किया गया था। इस स्विच माड्यूल का कुल जीवनकाल 20 हजार घंटे माना जाता है।

क्या है फ्यूल कंट्रोल स्विच

फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के काकपिट में थ्रस्ट लीवर के पास होते हैं। ये इंजन में ईंधन की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। इनका मुख्य काम इंजन में ईंधन की आपूर्ति को शुरू करना या बंद करना है। फ्यूल कंट्रोल स्विच सिग्रा से लैस होते हैं और इनमें डिटेंट (एक तरह का लाक) होता है, जो इन्हें अपनी पोजीशन में स्थिर रखता है। हर इंजन के लिए अलग-अलग फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है।

कोर्ट ने अपराध के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल

विधि संवाददाता, जागरण ● प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराध के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हमीरपुर निवासी फहीमुद्दीन व दो अन्य को अंतरिम राहत देते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थनंदन की खंडपीठ ने सवाल उठाया कि क्या अपराधी के आवास को राज्य सरकार को विध्वंस करने का अधिकार है अथवा उसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? अपराध के बाद तुरंत विध्वंस करना क्या कार्यपालक विवेक का विकृत प्रयोग है? और विध्वंस की 'उचित आशंका' ही लोगों के पास अदालत जाने का आधार हो सकती है। क्या इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है? राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए और याचीगण को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाएगा। प्रकरण में अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी।

मुकदमे से जुड़े तथ्य ये हैं कि भरुआ सुमेरपुर में वार्ड 11 धोकचंद निवासी याचीगण के रिश्तेदार अफान के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5(1) के तहत सुमेरपुर थाने में केस दर्ज है। भीड़ ने उनका मकान घेर लिया था। तीसरी याची जैबुन निशा के नाम पंजीकृत इंडियन लाज प्रतिवादियों ने सील कर दिया है। याची (क्रमांक दो) मोइनुद्दीन के नाम आरा मशीन जिलाधिकारी के आदेश से 11 फरवरी 2025 को सील की गई है। याचीगण आपस में क्रमशः पुत्र, पिता और माता हैं। अभियुक्त अफान रिश्ते में फहीमुद्दीन का चचेरा भाई तथा अन्य दोनों का भतीजा है। याचीगण ने आशंका जताई है कि उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने याचिका पर यह कहते हुए प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि यह प्री-मेच्योर है। याचीगण को केवल नोटिस जारी किया गया है, जिसका उन्हें जवाब देना है। आवास और लाज को सील नहीं किया गया है। साथ ही यह तथ्य छिपाया है कि आरा मशीन को प्रतिबंधित लकड़ी के कारण सील कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस अदालत ने ऐसे कई मामलों को देखा है, जहां अपराध के बाद तुरंत विध्वंस का नोटिस जारी किया जाता है और फिर विध्वंस किया जाता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट

- बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक संबंधी आदेश का दिया हवाला, पूछे सवाल
- उप्र सरकार ने कहा-कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाएगा

खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के सीएम कुकी नेता किपगेन डिप्टी सीएम

इंफाल, प्रेट्र : मणिपुर में लगभग एक साल बाद लगा राष्ट्रपति शासन हटने और राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता वाई. खेमचंद सिंह नए मुख्यमंत्री होंगे। कुकी समुदाय की पूर्व मंत्री नेमचा किपगेन उपमुख्यमंत्री होंगी। खेमचंद को मंगलवार को भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के विधायक दल का नेता चुना गया। खेमचंद बुधवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं।

गौरतलब है कि राज्य में 2023 में सुलगी जातीय हिंसा के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने पिछले साल नौ फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्य में 13 फरवरी, 2025 से राष्ट्रपति शासन है। 60 सदस्यीय विधानसभा निलंबित है। विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। इंफाल घाटी में रहने वाले मैतेयी और आसपास की पहाड़ियों में रहने वाले कुकी लोगों के बीच हुई जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए।

भाजपा विधायक दल ने राज्य भाजपा मुख्यालय में आयोजित बैठक में खेमचंद को अपना नेता चुना। इस बैठक में भाजपा के 37 विधायकों में से 35, पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुघ, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी संबित पात्रा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ए. शारदा देवी सहित अन्य लोगों की मौजूदगी रही। बीमार होने के कारण भाजपा के दो विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। किपगेन को भी नई सरकार में उपमुख्यमंत्री चुना गया।

इसके बाद मणिपुर भवन में एक और बैठक हुई, जिसमें मणिपुर में राजग के घटक दलों के विधायक - नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के छह, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के पांच और तीन निर्दलीय - और भाजपा के विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में खेमचंद को राजग विधायक दल का नेता और किपगेन को उपनेता चुना गया। सूत्रों के अनुसार, एक नगा विधायक को दूसरा उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने का प्रस्ताव है, लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राजग के सदस्य और निर्दलीय विधायक सपाम निशिकांत सिंह ने कहा कि खेमचंद सिंह के मणिपुर के तीनों प्रमुख समुदायों - मैतेयी, कुकी और नगा - के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और इसलिए वे राजग विधायक दल के नेता के लिए पसंद थे। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह व विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रता सिंह दोनों बैठकों में उपस्थित थे। इस समय मणिपुर में भाजपा के 37 विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के 32 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। जदयू ने छह सीटें जीती थीं, जिनमें से पांच विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए।

खेमचंद को चुना गया भाजपा और राजग विधायक दल का नेता, आज पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा

वाई. खेमचंद सिंह (बाएं) को मणिपुर भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करते मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ● एएनआइ

जातीय हिंसा के बाद कुकी समुदाय के राहत शिविर जाने वाले पहले विधायक हैं खेमचंद

62 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी खेमचंद भाजपा उम्मीदवार के रूप में सिंगजामेई निर्वाचन क्षेत्र से 2017 और 2022 में मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने पिछले वर्ष आठ दिसंबर को वह कुकी समुदाय के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत शिविरों का दौरा किया था। ऐसा करने वाले वह मैतेयी समुदाय के पहले विधायक हैं। वह 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे।

दबंगई से बस्ती में दहशत, 50 घरों पर लगाए 'मकान बेचना है' के पोस्टर

जागरण संवाददाता, आगरा : रिश्तेदारी में रह रहे मुस्लिम परिवार की दबंगई से परेशान 50 परिवारों को पुलिस की मदद नहीं मिली तो उन्होंने बड़ा फैसला लिया। दरवाजों पर 'मकान बेचना है' के पोस्टर चस्पा कर दिए। खबर लगते ही पुलिस अधिकारी हरकत में आए। एसीपी ने बस्ती वालों को थाने बुलाकर सुना। आनन-फानन में आरोपितों पर कार्रवाई करते हुए एक को जेल भेज दिया। पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिलाकर मामला शांत करवा दिया। इसके बाद पोस्टरों को हटा लिया गया है।

आगरा के भगवाननगर में इंजीनियर, डाक्टर और व्यापारियों के सौ से अधिक परिवार रहते हैं। 2021 में मोहल्ले के ही लक्ष्मी नारायण शर्मा और श्रीभगवान अग्रवाल पर जानलेवा हमला करने के मुकदमे में दो भाई आठ महीने जेल में रहे थे। सोमवार को गोविंद प्रसाद गर्ग के बेटे की हल्दी की रस्म का आयोजन था। घर के बाहर खड़ी कार हटाने के लिए कहने पर शहजाद के बेटे सनी, शम्शाद व नौशाद ने गोविंद प्रसाद गर्ग पर हमला कर दिया। आरोपितों ने घर में घुसकर स्वजन, रिश्तेदारों के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। मंगलवार को आरोपितों को इसकी जानकारी मिली तो वे धमकाने लगे। इसके विरोध में मोहल्ले के लोग एकजुट हो गए और घरों के बाहर 'मकान बेचना हैं' के पोस्टर लगा दिए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आरोपित शराब पीकर हंगामा करते हैं। घरों के बाहर मांस के टुकड़े फेंकते हैं। विरोध पर हमला कर देते हैं।

आगरा : भगवाननगर में घर के बाहर लगे पोस्टर ● जागरण

...आखिर पुलिस गोली न मारे, तो क्या गोली खाए : योगी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मंच बेशक यूपी फार्मा कान्क्लेव का था, लेकिन संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पर प्रश्न उठाने वालों को अपने अंदाज में जवाब देते हुए पूछ लिया कि 'क्या पुलिस गोली खाने के लिए है। हमने भी तो पुलिस को हथियार दिया है।' उनके इस बयान का फार्मा उद्यमियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। सीएम योगी ने निवेशकों को भरोसा दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर कोई कानून को आंख दिखाता है तो कानून उसे अपने दायरे में लाकर अपने तरीके से समझाता है। मंगलवार को होटल ताज में आयोजित हेल्थ फार्मा कान्क्लेव 1.0 में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम ने कहा कि यूपी को फार्मा हब बनाना है। बजट सत्र के दौरान लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के फार्मा इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा होगी। प्रदेशभर में फार्मा पार्क बनाए जाएंगे। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर की फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने यूपी में निवेश के लिए दस हजार करोड़ के एमओयू पर सहमति बनाई।

योगी के सामने भावुक हुए मैनकाइंड के चेयरमैन, कहा-डर से छोड़ा था यूपी

उत्तर प्रदेश फार्मा कान्क्लेव 1.0 के मंच से मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन रमेश जुनेजा अपने पलायन का दर्द सामने बैठे मुख्यमंत्री योगी को सुनाते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरठ में घर बहुत याद आता है। अब यूपी ऐसी स्थिति में पहुंचा है, जहां डर नहीं रहा। लौटने का मन करता है। यह सुनकर मुख्यमंत्री ने उन्हें संकेतों में आश्वस्त किया कि प्रदेश बदल चुका है।

सांसद पप्पू यादव समेत तीन के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश

जासं, पटना : पटना में एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत ने मंगलवार को सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत तीन आरोपितों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया है। धोखाधड़ी से मकान किराया पर लेने और धमकी देने के मामले में यह आदेश जारी किया गया।

इस मामले में अन्य आरोपित शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद हैं। अदालत में आरोपितों की लगातार अनुपस्थिति के कारण यह आदेश जारी किया गया है। इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने सात फरवरी, 2026 की अगली स्थिति निर्धारित की है। मामला वर्ष 1995 का है। आरोप के अनुसार शैलेंद्र प्रसाद ने शिकायतकर्ता का मकान किराये पर लिया। बाद में पता चला कि वह मकान पप्पू यादव ने धोखाधड़ी पूर्वक कार्यालय चलाने के लिए लिया था। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

राखीगढ़ी में मिट्टी की परतें खोल रहीं 'स्मार्ट सिटी' के राज

सुनील नाज ● जागरण

टीला नंबर-2 पर मिले प्राचीन नदी और जलीय जीवों के अवशेष, दुनिया की नजरें अब मेगा सिटी के बाहरी स्वरूप पर, तीन साल चलेगी खोदाई

राखीगढ़ी के टीला नंबर दो पर खोदाई करते हुए छात्र ● जागरण

नारनौंद: हरियाणा के हिसार जिले की गोद में बसा राखीगढ़ी महज एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के उस गौरवशाली अतीत का जीवंत दर्पण है, जिसने दुनिया को पहली बार शहरी सभ्यता का सलीका सिखाया था। जब विश्व के अधिकांश हिस्से कंदराओं और जंगलों में भटक रहे थे, तब हमारे पूर्वज राखीगढ़ी की गलियों में पक्की ईंटों के मकानों और सुव्यवस्थित नालियों के बीच एक 'स्मार्ट सिटी' का आनंद ले रहे थे। आज हजारों साल बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के फावड़े और ब्रश उस 'मेगा सिटी' के उन अनसुलझे रहस्यों को तराश रहे हैं, जिन्हें जानने के लिए पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं।

22 जनवरी से शुरू हुआ खोदाई का यह चौथा चरण अगले तीन वर्षों तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य हड़प्पा कालीन शहरों के बाहरी स्वरूप और उनकी सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया के सामने लाना है।

नदी की धारा और जलीय जीवन के प्रमाण : खोदाई के प्रारंभिक चरण में टीला नंबर-2 ने पुरातत्वविदों को चौंका दिया है। यहां कुछ ही दूरी पर कच्ची ईंटों की दीवारें और पानी बहने के स्पष्ट निशान मिले हैं। मिट्टी की परतों से छोटे-छोटे शंखनुमा अवशेष, मछली और कछुए की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

पुरातत्वविदों का मानना है कि जलीय जीवों के अवशेष इस बात का संकेत हैं कि यहां से कोई बड़ी नदी या नहर बहती थी। संभवतः नदी के सूखने पर ये जीव वहीं दब गए होंगे। इन हड्डियों की जांच से यह भी पता चलेगा कि क्या उस समय के लोग इन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे।

दृषद्वती और सरस्वती का संगम

ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार, राखीगढ़ी सरस्वती की सहायक नदी दृषद्वती के किनारे बसा था। खोदाई स्थल पर सरस्वती नदी होने के प्रमाण भी मिले हैं। इस खोदाई कार्य में केवल मशीनें नहीं, बल्कि युवा जोश भी शामिल है। टीला नंबर एक, दो और तीन पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और हिमाचल विवि के छात्र दफन राजों की परतें खोलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

राखीगढ़ी : एक नजर में

खोदाई का समय: तीन साल का लंबा प्रोजेक्ट।

प्रमुख टीले : कुल सात टीलों में टीला 1, 2 और 3 पर काम चल रहा।

नगर स्वरूप: पक्की और कच्ची ईंटों की दीवारें, व्यवस्थित जल निकासी।

सांस्कृतिक महत्व: सरस्वती-दृषद्वती सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र।

विवाह पूर्व संबंधों से जन्मी संतान के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पति की

- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का विवाह विच्छेद प्रकरण में फैसला
- मुख्य न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 125 का दिया हवाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विवाह पूर्व संबंध से जन्मी संतान के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पति की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत विवाह के पूर्व संबंधों के कारण जन्मी संतान पिता से भरण-पोषण पाने का अधिकार रखती है।

यह मामला बेमेतरा जिले के एक युवक से संबंधित है, जिसकी शादी अप्रैल 2016 में हुई थी। शादी के बाद गौना की रस्म मई 2016 में हुई, जिसके बाद पत्नी अपने ससुराल आई। गौना के केवल पांच महीने बाद ही अक्टूबर 2016 में पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। पति ने आरोप लगाया कि गौना से पहले उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बने थे, इसलिए वह बच्चा उसका नहीं है। इसी विवाद के चलते पति ने फैमिली कोर्ट में विवाह विच्छेद का मामला दायर किया। फैमिली कोर्ट ने पति को इस आधार पर विवाह विच्छेद की अनुमति दी कि वह संतान के भरण-पोषण के लिए पत्नी को हर महीने एक हजार रुपये देगा। फैमिली कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में पति ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने तलाक की डिक्री पारित करते हुए बच्चे को उसकी जैविक संतान नहीं माना है। याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 में दिए गए प्रविधान के अनुसार, अजैविक संतान भी अपने पिता से भरण-पोषण पाने का अधिकार रखती है।

चिंतन

यूएस से ट्रेड डील रोजगार के नए मौके पैदा करेगी

भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुई ट्रेड डील को मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक निर्णायक और दूरगामी कदम है। पिछले एक वर्ष से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर जो असमंजस और अनिश्चितता बनी हुई थी, उसका सीधा असर भारत के निर्यात, निवेश और रोजगार सृजन पर पड़ रहा था। उसका असर व्यापारियों और युवाओं के रोजगार अवसरों पर साफ दिखाई दे रहा था। इस समझौते ने उस माहौल को काफी हद तक समाप्त करने का संकेत दिया है और व्यापारियों, उद्योग जगत तथा युवाओं में नई उम्मीद जगाई है। भले ही सौदे की पूरी शर्तें अभी सामने आनी बाकी हों, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह डील भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संभावनाओं के द्वार खोलती है। इसे मौजूदा वैश्विक आर्थिक हालात में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ बातचीत में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना यह समझौता किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना भारत की मजबूत कूटनीतिक स्थिति को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अपनी शर्तों पर बातचीत करने वाला देश बन चुका है। इस डील से 'मेड इन इंडिया' नई गति मिलने की उम्मीद है। जब निर्यात बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से उत्पादन बढ़ेगा और इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। कपड़ा, चमड़ा, हीरा-जवाहरात, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और इंजीनियरिंग सेक्टर जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। इन सेक्टरों में लाखों लोगों को काम मिलता है और यही कारण है कि इस समझौते को रोजगार सृजन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही, लोगों के हाथों में अधिक पैसा आएगा, जिससे 'ईज ऑफ लिविंग' को भी मजबूती मिलेगी। ट्रेड डील का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र को इससे अलग रखकर अपने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा की है। यह दिखाता है कि सरकार ने वैश्विक दबावों के बावजूद घरेलू प्राथमिकताओं को नजरअंदाज नहीं किया। भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद में कुछ कमी और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश यह दर्शाती है कि भारत वैश्विक संतुलन को साधते हुए आगे बढ़ रहा है। हालांकि वेनेजुएला से तेल खरीदना तकनीकी और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस डील का असर बाजारों पर भी दिखाई दिया है। रुपये और सेंसेक्स की तेज उछाल इस बात का संकेत है कि निवेशकों ने इस समझौते का स्वागत किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का यह कहना कि इस डील में किसी के हितों से समझौता नहीं किया गया, सरकार के आत्मविश्वास को दर्शाता है। उनका यह भी कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों की रक्षा की है, इस समझौते के संतुलित स्वरूप को रेखांकित करता है। यह डील भारत के 140 करोड़ नागरिकों, गांवों में रहने वाले गरीबों, किसानों, मछुआरों, युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ सकती है। कुल मिलाकर, भारत-अमेरिका ट्रेड डील भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। निर्यात बढ़ेगा, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। यदि इस समझौते का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया, तो यह भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

संसद
कांतिलाल मांडोत

सदन की मर्यादा बनाम सियासी सनसनी

संसद में संदेह, कयास और 'कहा जाता है' जैसे शब्दों के आधार पर देश की सुरक्षा नीति पर बहस नहीं की जा सकती। यह न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करने वाला भी है। जनता अब केवल आरोप नहीं, प्रमाण भी चाहती है। सोशल मीडिया और सूचना के इस दौर में आधे सच ज्यादा देर तक टिकते नहीं। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन नियमों के भीतर रहकर। सरकार का काम जवाब देना है, लेकिन तथ्य और मर्यादा के साथ। जब दोनों में से कोई एक भी इस संतुलन को तोड़ता है, तो नुकसान लोकतंत्र का होता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है उसकी जिम्मेदारी।

लोकसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां शब्द केवल अभिव्यक्ति नहीं होते, बल्कि राष्ट्रीय भरोसे, संस्थागत मर्यादा और संवैधानिक जिम्मेदारी के प्रतीक भी होते हैं। ऐसे में अगर इस मंच पर ऐसे संदर्भ लाए जाएं, जिनका न तो आधिकारिक अस्तित्व हो और न ही सार्वजनिक सत्यापन, तो स्वाभाविक है कि सवाल केवल कथन पर नहीं, कथन करने वाले की मंशा पर भी उठते हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब के हवाले से डोकलाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान इसी श्रेणी में आता है, जिसने संसद में हंगामा खड़ा कर दिया और देश के सामने एक गंभीर प्रश्न रख दिया। क्या राजनीतिक लाभ के लिए सदन की नियम-परंपरा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों को दांव पर लगाया जा सकता है?

राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान जिस मैगजीन लेख का हवाला दिया, वह स्वयं एक अप्रकाशित मेमॉयर पर आधारित बताया गया। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, वह प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो इस तर्क को खारिज करना मुश्किल हो जाता है। संसदीय परंपरा साफ कहती है कि सदन में वही तथ्य उद्धृत किए जा सकते हैं, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध, प्रकाशित और सत्यापन योग्य हों। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसी नियम की याद दिलाई। इसके बावजूद, नियमों की अवहेलना कर बार-बार वही संदर्भ दोहराया गया, जिससे बहस का स्तर मुद्दे से हटकर टकराव तक पहुंच गया। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी, ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ऐसे बयान दिए हों, जिन्हें बाद में या तो आधा-अधूरा बताया गया या तथ्यहीन। डोकलाम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बोलते समय अतिरिक्त सावधानी अपेक्षित होती है, क्योंकि यहां केवल सरकार की आलोचना नहीं होती, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सेना की रणनीति, क्षमता और निर्णयों पर भी सवाल खड़े होते हैं। स्वयं स्पीकर ने यह टिप्पणी की कि राष्ट्रीय हित के विषय पर सेना की आलोचना उचित नहीं है। यह टिप्पणी किसी दल विशेष के पक्ष में नहीं, बल्कि संस्था की रक्षा में दी गई चेतावनी थी। राहुल गांधी का यह कहना कि "किताब को प्रकाशित नहीं करने दिया गया'' भी बिना किसी ठोस प्रमाण के एक गंभीर आरोप है। अगर ऐसा है, तो सवाल उठता है कि कांग्रेस के पास इसके समर्थन में आधिकारिक दस्तावेज, लेखक का सार्वजनिक बयान या प्रकाशक की पुष्टि क्यों नहीं है? संसद में संदेह, कयास और 'कहा जाता है' जैसे शब्दों के आधार पर देश की सुरक्षा नीति पर बहस नहीं की जा सकती। यह न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करने वाला भी है। कांग्रेस अक्सर यह आरोप लगाती रही है कि सरकार असहज सवालों से डरती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में डर नहीं, बल्कि प्रक्रिया और नियमों पर जोर दिखा। अगर राहुल गांधी किसी प्रकाशित लेख या आधिकारिक बयान का हवाला देते, तो सरकार के पास उसका जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। समस्या सवाल में नहीं, सवाल पूछने के तरीके में है। संसद बहस का मंच है, अफवाहों का नहीं। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना कि "मैगजीन तो कुछ भी लिख सकती है" केवल एक राजनीतिक तंज नहीं, बल्कि तथ्यात्मक चेतावनी भी है।

कांग्रेस की रणनीति पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि वह सदन के भीतर और बाहर लगातार ऐसे मुद्दे उठाना चाहती है, जिनसे सरकार को राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मोर्चे पर घेरा जा सके। लेकिन जब ऐसे प्रयास ठोस तथ्यों के बजाय अपुष्ट संदर्भों पर आधारित हों, तो वे खुद कांग्रेस की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाते हैं। जनता अब केवल आरोप नहीं, प्रमाण भी चाहती है। सोशल मीडिया और सूचना के इस दौर में आधे सच ज्यादा देर तक टिकते नहीं।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने स्वयं सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा है कि डोकलाम में चीनी टैंक भारतीय सीमा के 100 मीटर तक भीतर आ गए थे, जैसा दावा किया गया। अगर ऐसा कोई गंभीर तथ्य होता, तो वह किसी न किसी आधिकारिक माध्यम से सामने आता। सेना और सरकार के बीच संवाद कोई छिपी हुई प्रक्रिया नहीं है, खासकर जब बात सीमा सुरक्षा की हो। ऐसे में अप्रकाशित किताब के हवाले से सनसनी फैलाना न तो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका है और न ही परिपक्व राजनीति की पहचान।

सदन की कार्यवाही का बार-बार स्थगित होना भी किसी के हित में नहीं है। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन नियमों के भीतर रहकर। सरकार का काम जवाब देना है, लेकिन तथ्य और मर्यादा के साथ। जब दोनों में से कोई एक भी इस संतुलन को तोड़ता है, तो नुकसान लोकतंत्र का होता है। इस पूरे घटनाक्रम में सरकार ने नियमों का हवाला दिया, जबकि कांग्रेस ने भावनात्मक और आरोपात्मक राजनीति को तरजीह दी। यही अंतर आज की राजनीति की दिशा तय कर रहा है।

अंततः, यह बहस किसी एक किताब या एक बयान तक सीमित नहीं है। यह इस बात की परीक्षा है कि हम संसद को किस रूप में देखना चाहते हैं। एक गंभीर नीति-निर्माण मंच या राजनीतिक सुर्खियों का अखाड़ा। कांग्रेस और राहुल गांधी को आत्ममंथन करना होगा कि क्या बार-बार बेबुनियाद आरोप लगाकर वे वास्तव में राष्ट्रीय हित की सेवा कर रहे हैं, या केवल तात्कालिक राजनीतिक लाभ की तलाश में हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है उसकी जिम्मेदारी। बिना प्रमाण के आरोप न केवल सरकार को, बल्कि पूरे देश को कमजोर करते हैं। इसलिए जरूरी है कि संसद में आमजन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार उठाया जाए। संसद केवल खाली हंगामा करने की जगह न बनें। क्योंकि सदन का जितना समय बार्बाद होगा आमजन का भी उताना ही नुकसान होगा। विपक्ष का कर्तव्य है कि व स्वस्थ और आमजन के मुद्दों पर बहस करे। न कि सदन को अखाड़ा बनाकर छोड़ दे। संसद लोगों के लिए योजनाएं और कानून बनाने के लिए है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकारहैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

नीति और सत्ता
अम्बरीष प्रजापति

न्यायिक दहलीज पर दम तोड़ते कानून

बीते कुछ समय से देश की शासन व्यवस्था में एक अजीबोगरीब दोहराव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार जब भी कोई महत्वाकांक्षी नियमावली या कानून पेश करती है, तो वह लागू होने से पहले ही उच्चतम न्यायालय के अवरोधों में फंस जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हालिया समानता संबंधी दिशानिर्देशों पर लगी रोक इसी सिलसिले की एक ताजा मिसाल है। चाहे वह सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत 'सत्यता जांच इकाई' का विवाद हो, डेटा सुरक्षा कानून की संवैधानिक चुनौतियां हों या प्रसारण विधेयक पर बढ़ता विरोध-यह सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहाँ बुनियादी मसला अदालती दखल का नहीं है, बल्कि उस कार्यप्रणाली का है जिसके तहत ये नियम गढ़े जा रहे हैं। जब बारीकी से तैयार किए गए कानून न्यायिक कसौटी पर बार-बार विफल होने लगें, तो यह नीति-निर्धारकों की दूरदर्शिता और उनकी संवैधानिक समझ पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

सुधार या नियोजित भ्रम की रणनीति?

यूजीसी के प्रकरण को ही लें। 'यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन' को जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र ऐसे तमाम आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त कर शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक समरसता, समता भाव स्थापित करने के लिए लाया गया और इसे शिक्षा जगत में सुधार के तौर पर प्रचारित किया गया, लेकिन इसकी अंतर्धारा ने सामाजिक समरसता के बजाय 'जातीय ध्रुवीकरण' को अधिक हवा दी। 'समानता' की शब्दावली का उपयोग करते हुए जिस तरह से पारंपरिक श्रेणियों और पहचानों को पुनर्जीवित किया गया, उसने स्पष्ट कर दिया कि यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है। कई विश्लेषकों का मानना है कि नियमों में जानबूझकर छोड़ी गई अस्पष्टता किसी सुधार का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक बिसात है। आज की राजनीति नब्बे के दशक के सीधे टकराव वाली राजनीति से अलग है। अब जाति को मिटाने का संकल्प कहीं ओझल हो गया है; इसके उलट उसे 'पावर गेम' के एक नए सांचे में ढाला जा रहा है। जाति अब सामाजिक चेतना का विषय न रहकर सत्ता के प्रचार-प्रसार, वोट बैंक साधने का माध्यम बन गया है।

जवाबदेही से बचता सत्ता का शीर्ष

विडंबना देखिए कि जब भी कोई कानून अदालत में अटकता है, तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग बड़ी चतुराई से आलोचना से बच निकलते हैं। दोष कभी समितियों पर मढ़ा जाता है, कभी मंत्रियों पर, तो कभी विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। यह वही पुराना मॉडल है- 'सफलता का श्रेय ऊपर, विफलता की जिम्मेदारी नीचे'। इस पूरी प्रक्रिया में असली 'निर्णय-केंद्र' हमेशा अदृश्य बना रहता है।

हिंदुत्व और सामाजिक समरसता का क्षरण

हिंदुत्व का विचार, जो मूलतः सांस्कृतिक एकात्मता और भेदभाव रहित समाज की बात करता था, इस 'पहचान वाली राजनीति' के कारण हाशिए पर जाता दिख रहा है। जब सामाजिक न्याय को लोक-कल्याण के बजाय मार्केटिंग के औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो समाज जुड़ने के बजाय बंट जाता है। यह न तो हिंदुत्व की जीत है और न ही सामाजिक न्याय की; यह केवल सत्ता को स्थिर रखने का एक खेल है।

सुझावः इस संवैधानिक और सामाजिक उलझन से निकलने के लिए सरकार को केवल कागजी बदलाव नहीं, बल्कि बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है। एआई आधारित सुरक्षा निगरानी केंद्रः सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में 'एआई सुरक्षा निगरानी केंद्र' स्थापित किए जाएं। ये केंद्र आधुनिक तकनीक के जरिए किसी भी वर्ग, समुदाय के छात्र छात्राओं, अधिकारी-कर्मचारी तथा शिक्षकों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव की शिकायतों का निष्पक्ष विश्लेषण हो सकेगा, जिससे मानवीय पूर्वाग्रह और जातीय द्वेष की गुंजाइश खत्म हो सकेगी और जो वास्तविक दोषी होगा उस पर कारवाई हो सकेगी। सरकार शैक्षणिक संस्थानो में जातिगत भेदभव मुक्त परिसर बनाकर जो समता मूलक भाव पैदा करना चाहती है। इस तरह समता मूलक, समरसता युक्त कैंपस बन सकेंगे।

निष्कर्षः लोकतंत्र केवल बहुमत के आंकड़ों से नहीं, बल्कि संवैधानिक विवेक और सामाजिक संवेदनशीलता से चलता है। जब नीति-निर्माण में बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की कमी होती है, तो कानून अदालतों में अटकते हैं और जनता सड़कों पर उतरती है। भारत एक भावप्रधान राष्ट्र है, जहाँ भावनाओं का दोहन करना आसान है, लेकिन अब समय 'बुद्धि' से सोचने का है। चूंकि आज के दौर में 'कंटेंट' ही किंग है, इसलिए यह जरूरी है कि झूठे नैरेटिव्स के जाल में फंसने के बजाय सच जानने का प्रयास करें। क्योंकि किसी भी भ्रम का अंत केवल तार्किक चर्चा से ही संभव है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकारहैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सुख की चाह के लिए तप की साधना ज़रूरी है

संकलित
दर्शन

तप संकल्प की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। जिसे सत्य संकल्प द्वारा सुख की चाह है, उसे तप की साधना अवश्य करनी चाहिए। संकल्प के दृढ़ एवं सत्य न होने का सबसे बड़ा कारण तप की कमी होता है। जो व्यक्ति अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा तप नहीं करता, वह अपने संकल्पों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तप से हमें अपने मन और तन, दोनों को पक्का बनाना होता है। जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा पानी डालने पर गल जाता है। वह अग्नि में बिना तपे कभी जल नहीं ला सकता। इसी प्रकार जब तक मनुष्य अपने जीवन को तप द्वारा पक्का नहीं बनाता, तब तक वह कभी भी अपने संकल्पों की सिद्धि को धारण नहीं कर सकता। तप से जीवन की समस्त अशुद्धियां दूर होती हैं। अशुद्धियों के दूर होने से शरीर और इंद्रियों को विशेष सिद्धि मिलती। तभी कहा जाता है कि तप से सभी कुछ साध्य है। वेदों में भी तप की महिमा और आवश्यकता का अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। कल्याण की कामना करने वाले ऋषिगण भी प्रथम तप और दीक्षा का ही अनुष्ठान करते हैं। श्रीमद्भागवत कथा के द्वितीय स्कंध में श्री भगवान ब्रह्मजी से कहते हैं कि 'मैं इस दृश्यमान अखिल प्रपंच को तप द्वारा रचता हूं और पुनः तप द्वारा ही ग्रसित कर लेता हूं। मैं तप द्वारा ही इस विश्व का भरण-पोषण करता हूं और मेरा अत्यंत तेजस्वी पराक्रम तप ही है। तप द्वारा वह तेज और वह शक्ति प्राप्त की जा सकती है, जो किसी भी संकल्प की प्रतिपूर्ति का आधार बनती है।'

अपनी गठरी टटोलें

संकलित
प्रेरणा

दो आदमी यात्रा पर निकले! दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का गंतव्य एक था तो दोनों यात्रा में साथ हो चले। सात दिन बाद दोनों के अलग होने का समय आया तो एक ने कहा- भाई साहब! एक सप्ताह तक हम दोनों साथ रहे क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा- नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। पहला यात्री बोला- महोदय मैं एक नामी ठग हूँ परन्तु आप तो महाठग हैं। आप मेरे भी गुरू निकले। दूसरा यात्री बोला- कैसे? पहला यात्री- कुछ पाने की आशा में मैंने निरंतर सात दिन तक आपकी तलाशी ली, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतने दिन साथ रहने के बाद मुझे यह पता है आप बहुत धनी व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है? बिल्कुल खाली हाथ हैं! दूसरा यात्री- मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी-सी रजत मुद्राएं भी हैं। पहला यात्री बोला- तो फिर इतने प्रयत्न के बावजूद वह मुझे मिले क्यों नहीं? दूसरा यात्री- मैं जब भी बाहर जाता, वह हीरा और मुद्राएं तुम्हारी पोटली में रख देता था और तुम सात दिन तक मेरी झोली टटोलते रहे। अपनी पोटली सँभालने की जरूरत ही नहीं समझी। तो फिर तुम्हें कुछ मिलता कहां से! ईश्वर नित नई खुशियां हमारी झोली में डालते हैं परन्तु हमें अपनी गठरी पर निगाह डालने की फुर्सत ही नहीं है, यही सबकी मूलभूत समस्या है। जिस दिन से इंसान दूसरे की ताकझाक बंद कर देगा उस क्षण सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अपनी गठरी टटोलें! जीवन में सबसे बड़ा गूढ मंत्र है स्वयं को टटोले और जीवन-पथ पर आगे बढ़े सफलताएं आप की प्रतीक्षा में है।

अंतर्मन

आज की पाती

रक्षा पर जोर रोजगार भाव विभोर

बजट को 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ यानी 15.2 प्रतिशत की वृद्धि करके देश की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। मिडिल क्लास के लिए न तो आयकर में कोई नई छूट का प्रावधान रखा गया और न ही गरीब मजदूरों के हित अथवा महंगाई से राहत के लिए कोई ऐसा कदम उठाया गया, जिससे उन्हें सुकून मिल सके। देश के उत्थान में युवकों का सबसे बड़ा योगदान होता है, किंतु बेरोजगारी कम करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे उन्हें बेहतर नौकरी या रोजगार मिल सके। सरकार को बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के विषय में भी प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर इस बार का बजट किसी भी वर्ग को बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं कर पाया है। – *संतोष अग्रवाल, भाटापारा*

ट्रेंड

मोदी मेरे अच्छे दोस्त

पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वे अपने देश में एक मजबूत और सम्मानित नेता हैं। हम दोनों ऐसे लोग हैं जो काम करके दिखाते हैं। यह बात ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती। हमारी डील से दोनों देशों का विकास होगा।
-**डोनाल्ड ट्रंप,** राष्ट्रपति अमेरिका

राहुल देश को गुमराह कर रहे

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। अमेरिकी के साथ ट्रेड डील से देश को फायदा होगा। देश-विदेश में इसकी तारीफ हो रही है। कृषि-डेयरी क्षेत्र को संरक्षित रखा जाएगा। हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर्स के पार्ट्स बनाने वाले, टेक्सटाइल, मरीन गुड, ज्वेलर सेक्टर को बहुत सारे मौके मिलेंगे। -**पीयूष गोयल,** केंद्रीय मंत्री

इमेज तोड़ रहे मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई वे अब यह इमेज तोड़ रहे हैं। अमेरिका में अडानी पर केस है, यह असल में मोदी पर केस है। वो मोदी जी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। -**राहुल गांधी,** नेता विपक्ष

एसआईआर से लोग पीड़ित

पश्चिम बंगाल में कई वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। प्रभावित लोगों को न तो ठीक से सूचना दी जा रही है और न ही उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिल रहा है। एसआईआर प्रक्रिया से लोग पीड़ित हैं। -**ममता बनर्जी,** सीएम, प. बंगाल

करंट अफेयर

कक्षाओं में चैटजीपीटी, अब छात्रों के सीखने का आकलन कैसे

दुनिया के हर क्षेत्र के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेनएआई) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और छात्र तथा शिक्षक पढ़ाई, सीखने और मूल्यांकन में चैटबॉट्स को शामिल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं, बल्कि शिक्षा की मूल प्रकृति को प्रभावित करने वाला है। कनाडा के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 28 शिक्षकों पर आधारित एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि शिक्षा एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे समय में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है कि जब एल्गोरिदम मानव संज्ञान को सहारा दे सकते हैं या उसका अनुकरण कर सकते हैं, तब आकलन किस बात का होना चाहिए। एआई और अकादमिक ईमानदारी पर पिछले 15 वर्षों के शोध की समीक्षा से पता चला कि एआई शिक्षा के लिए दोधारी तलवार है। एक ओर, उन्नत टेक्स्ट जनरेटर और अनुवादक मानव-जैसा लेखन कर सकते हैं, जिससे नकल को पकड़ना और उसका पता लगाना ही कठिन हो गया है। साथ ही, ये उपकरण कभी-कभी गलत जानकारी देते हैं या सामाजिक पूर्वाग्रह भी दोहरा सकते हैं। दूसरी ओर, एआई सीखने को अधिक समावेशी बना सकता है, विशेषकर दिव्यांग छात्रों या अतिरिक्त भाषा सीख रहे छात्रों के लिए।

ऑफ बीट

अब उम्र तय करने में जीन की भूमिका पहले से अधिक

शोध के अनुसार, आज के दौर में जीवनकाल में जीन का योगदान पहले की तुलना में कहीं अधिक दिखाई देता है। इसके पीछे कारण यह नहीं है कि जीन अचानक ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं, बल्कि यह है कि बीते एक शताब्दी में मृत्यु के कारणों में बड़ा बदलाव आया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एक सदी पहले बड़ी संख्या में लोग दुर्घटनाओं, संक्रमणों और अन्य बाहरी कारणों से मर जाते थे। वैज्ञानिक इन्हें 'बाह्य कारण' कहते हैं। इसके विपरीत, आज विकसित देशों में अधिकांश मौतें 'आंतरिक कारणों' से होती हैं, जैसे उम्र बढ़ने से जुड़ी बीमारियां- हृदय रोग, डिमेंशिया और अन्य रोग। अधिक स्पष्ट तस्वीर के लिए शोध दल ने स्कैंडिनेवियाई देशों में जुड़वां बच्चों के बड़े समूहों का अध्ययन किया। इसमें दुर्घटनाओं और संक्रमणों से हुई मौतों को अलग कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिका में अलग-अलग पले-बढ़े जुड़वां बच्चों और सौ साल से अधिक उम्र तक जीने वाले लोगों के भाई-बहनों का भी विश्लेषण किया गया। जब बाहरी कारणों से होने वाली मौतों को अलग कर देखा गया, तो जीवनकाल में जीन का अनुमानित योगदान 20–25 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 50–55 प्रतिशत तक पहुंच गया।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

खबर संक्षेप

अदाणी पोर्ट के लाभ में 21 फीसदी का इजाफा

नई दिल्ली। अदाणी पोर्ट एंड स्पेशल इकॉनमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) का वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,043 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को तीसरी तिमाही के अपने वित्तीय परिणामों की जानकारी दी। पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 2,518 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।सालाना आधार पर 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए कंपनी का राजस्व 7,964 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,705 करोड़ रुपये हो गया।

एनएमडीसी का लाभ 8% घटकर 1,747 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। एनएमडीसी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर लगभग आठ प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,747.01 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने मंगलवार को तीसरी तिमाही के अपने वित्तीय परिणामों की जानकारी दी। एनएमडीसी लिमिटेड ने पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 1,896.66 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

सीबीआईसी चेयरमैन ने कहा, बैगेज नियमों में ढील दी गई

सीमा शुल्क में सुधार से लोगों का जीवन होगा सुगम, उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन

एजेंसी ▸▸ नई दिल्ली

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा है कि आम बजट में अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने, 'बैगेज' नियमों में ढील जैसे उपायों का मकसद लोगों के जीवन को सुगम बनाना है।

सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाया गया

चतुर्वेदी ने कहा कि इसके साथ ही सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाकर विनिर्माण को गति देने, घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। चतुर्वेदी ने कहा, ''अप्रत्यक्ष कर पर छूट और रियायतें सोच-समझकर दी गई हैं। हमने वहां कदम उठाया है जहां इसकी आवश्यकता थी।

ढील देने का मकसद लोगों के जीवन को सुगम बनाना

बाहर से 75 हजार तक शुल्क मुक्त सामान ला सकते हैं

उल्लेखनीय है कि 2026-27 के आम बजट में कैंसर के इलाज में काम आने वाली 17 दवाओं पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है। इसके अलावा, सात और दुर्लभ बीमारियों के लिए शुल्क मुक्त दवाएं और खाने का सामान मंगाने की अनुमति दी गयी है। इसके साथ 'बैगेज' नियमों के तहत बाहर से 75,000 रुपये का शुल्क मुक्त सामान लाने की अनुमति दी गयी है जबकि पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी।

सामान लाने शुल्क मुक्त सीमा 7,50,000 तक की गई

चतुर्वेदी ने कहा, ''इसके अलावा हमने 'ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस' के तहत भारतीय मूल के लागों को तीन साल बाद वापस स्वदेश लौटने पर निर्धारित सूची के अनुसार सामान लाने के लिए शुल्क मुक्त सीमा 7,50,000 तक कर दी है। जो लोग कुछ कम समय के लिए रहे हैं, उनके लिए शुल्क छूट सीमा कुछ कम है।''

मोनाजाइट में छूट दी गई

चेयरमैन ने कहा, ''इसी तरह ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने लिए कदम उठाये गये हैं। इसके तहत परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में उपयोग होने वाले आयातित कलपुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण में इस्तेमाल लिथियम आयन सेल में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर भी छूट दी गयी है। इसके साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्थायी चुंबक में उपयोग होने वाले मोनाजाइट में छूट दी गयी है।

छाते के आयात को हतोत्साहित किया गया

चतुर्वेदी ने कहा, ''इसी प्रकार, छोटे उद्योगों को ध्यान में रखकर छातों और उसके उत्पाद आयात को हतोत्साहित करने के लिए कदम उठाया गया है। अब छाते पर 20 प्रतिशत या प्रति इकाई 60 रुपये, जो भी ज्यादा हो, शुल्क लगेगा। इसके साथ छातों में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर भी शुल्क लगाया गया है।''

शुल्क मुक्त आयात की सीमा बढ़ाई गई

चेयरमैन ने कहा, ''निर्यात की बात करें, तो चमड़ा निर्यात का बड़ा क्षेत्र है। इसको देखते हुए जूते बनाने में जो भी कच्चे माल आते हैं उसके विनिर्माण के लिए हमने शुल्क मुक्त रियायत दी है। इसी प्रकार, समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए हमने शुल्क मुक्त आयात की सीमा बढ़ायी है।''

पतंजलि अनुसंधान संस्थान एवं वेलनेस में 'योगा ओलंपियाड ओरिएंटेशन' एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ

हरिद्वार। पतंजलि अनुसंधान संस्थान एवं वेलनेस, हरिद्वार में 'योगा ओलंपियाड ओरिएंटेशन एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम' का नौ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का पतंजलि अनुसंधान संस्थान एवं वेलनेस में संपन्न हुआ। 22 से 30 जनवरी तक चला प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। यह कार्यक्रम योगदर्शन, मनोविज्ञान एवं आध्यात्मिकता पर आधारित था, जो आंतरिक शांति एवं आध्यात्मिक चिंतन की दिशा प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग सिक्किम सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, समानता एवं योग के व्यापक प्रसार को बढ़ावा देना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ मेडिटेशन, शंख वादन और हवन पूजन से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि योग प्राचीन भारत की एक समग्र शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक साधना है। योग का उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है, जिससे आत्म-साक्षात्कार, मानसिक शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है, तनाव कम होता है तथा अनुशासित जीवनशैली अपनाने में सहायता मिलती है। इस अवसर पर योगऋषि स्वामी रामदेव ने कहा कि नेचुरोपैथी अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा एक औषधि-रहित उपचार पद्धति है, जो शरीर की स्वाभाविक उपचार क्षमता को सक्रिय करती है। इसमें संतुलित आहार, जड़ी-बूटियाँ, जल एवं मिट्टी चिकित्सा, योग, प्राणायाम, उपवास, सूर्य चिकित्सा एवं एक्यूपंक्चर के माध्यम से रोगों के मूल कारणों का उपचार किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा एक प्रभावी पूरक उपचार पद्धति है, लेकिन गंभीर रोगों में अनुभवी चिकित्सक की सलाह अत्यंत आवश्यक होती है। साथ ही उन्होंने पतंजलि एवं सिक्किम सरकार के संयुक्त प्रयासों की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। पतंजलि वेलनेस के संदर्भ में डॉ. विनिता ने बताया कि आयुर्वेद एवं प्राकृतिक जीवनशैली अपनाकर ही शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। उपचार की विधि रोग की प्रकृति, रोगी की स्थिति एवं विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वेदप्रिया आर्या ने पतंजलि की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉ. विशाल, सौरभ निर्मोही, डॉ. दीपिका, डॉ. विनिता सहित अन्य पतंजलि वैज्ञानिकों की सक्रिय सहभागिता रही।

न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर दो नए प्लेटफॉर्मों का हुआ निर्माण

मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कटिहार मंडल के अधीन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर दो नए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाए हैं। यह यात्री-केंद्रित पहल स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा अपग्रेड है और इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाना, आसानी से चढ़ने और उतरने को सुनिश्चित करना, ऑपरेशनल दक्षता में सुधार करना और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे नेटवर्क के इस महत्वपूर्ण जंक्शन पर लंबी दूरी की बढ़ती ट्रेन सेवाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधन करना है। इसके अलावा, संशोधित नंबरिंग सिस्टम के अनुसार, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के मुख्य द्वार के साइड से बने नए

प्लेटफॉर्मों को प्लेटफॉर्म संख्या 1 और प्लेटफॉर्म संख्या 2 नाम दिया गया है। मौजूदा प्लेटफॉर्म को सिस्टमैटिक तरीके से प्लेटफॉर्म संख्या 8 तक पुनः क्रमांकित किया गया है। पुराने प्लेटफॉर्म को इस तरह से रीलाइन किया गया है: मौजूदा पीएफ-1A को पीएफ-3, पीएफ-1 को पीएफ- 4, पीएफ-2 को पीएफ -5, पीएफ-3 को पीएफ-6, पीएफ-4 को पीएफ-7 और पीएफ-5 को पीएफ-8 नाम दिया गया है। इस बदलाव का मकसद एकरूपता लाना, परिचालन भ्रम को कम करना और ट्रेनों की आवाजाही को अधिक सुचारू बनाना है। यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुलभ बनाने और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के संशोधित प्लेटफॉर्मों के लिए लंबी दूरी की कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को नामित किया गया है।

स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड ने भारत के नए रिटेल निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए स्टॉकफिन 2.0 लॉन्च किया

नई दिल्ली। स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड, जो कि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और सेबी-पंजीकृत कॉरपोरेट स्टॉक ब्रोकर है, ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने निवेश ऐप स्टॉकफिन 2.0 के लॉन्च की घोषणा की। इस ऐप का अनावरण श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन, माननीय संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री राहुल भावे, एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेड; श्री अतुल सक्सेना, एमडी एवं सीईओ, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; और श्री प्रभात कुमार दुबे, एमडी एवं सीईओ, स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड भी उपस्थित थे। स्टॉकफिन 2.0 एक नई पीढ़ी का निवेश ऐप है, जिसे भारत भर के निवेशकों को सरल, सुरक्षित और सहज निवेश अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उत्तर रेलवे, आईआरएफसी व एनबीसीसी ने हाथ मिलाया

नई दिल्ली। भारतीय खेल बुनियादी ढांचे के मानकों को ऊपर उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आज उत्तर रेलवे खेल संघ (एनआरएसए), भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) और एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर समारोह शाम 4:30 बजे महाप्रबंधक के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुआ, जो 6 करोड़ से अधिक मूल्य की इस उच्च-प्रभाव वाली परियोजना की शुरुआत का प्रतीक है। यह साझेदारी राजधानी में एथलेटिक उत्कृष्टता के ऐतिहासिक केंद्र, प्रतिष्ठित करनैल सिंह स्टेडियम को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। इस एमओयू के तहत मुख्य सुधारों में शामिल हैं: प्रोफेशनल फ्लडलाॅट्स की स्थापना: स्टेडियम में रात के समय प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी मैचों के आयोजन को सक्षम बनाना। क्लाइमेट-कंट्रोल बैडमिंटन हॉल: बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए साल भर उच्च-प्रदर्शन प्रशिक्षण की स्थिति सुनिश्चित करने हेतु पूरी सुविधा को वातानुकूलित करना। समारोह में अशोक कुमार वर्मा, महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, मनोज कुमार दुबे, सीएमडी एवं सीईओ, आईआरएफसी, सुनील कुमार पांडे, सीईओ, एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड, राजीव कुमार, अध्यक्ष, एनआरएसए ने शिरकत की। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और प्रसिद्ध कोच जयदेव बिष्ट सहित प्रतिष्ठित खेल हस्तियों के साथ-साथ आईआरएफसी, एनबीसीसी और एनआरएसए के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मोबाइल, चिप सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शुल्क से मुक्त बने हुए

वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का आकर्षण बना रहेगा: आइसीईए

एजेंसी ▸▸ नई दिल्ली

मोबाइल उद्योग के निकाय आइसीईए ने मंगलवार को कहा कि भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर तय की गई 18 प्रतिशत की शुल्क दर एक वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में भारत के आकर्षण को बनाए रखेगी।

भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय सामानों पर जवाबी शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।

आइसीईए के चेयरमैन पंकज महेंदू ने एक बयान में कहा, ''यह भारत के लिए एक सकारात्मक परिणाम है। इस शुल्क दर के साथ भारत प्रमुख विनिर्माण प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और एक वैश्विक विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में अपना आकर्षण बरकरार रखे हुए है।''

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि हम सौदे के विस्तृत विवरण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह दिशा स्पष्ट रूप से विनिर्माण को बढ़ाने और अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में गहराई से जुड़ने की भारत की रणनीति का समर्थन करती है।

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 19 फीसदी बढ़ा

सूत्रों के अनुसार मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शुल्क से मुक्त बने हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग 19 प्रतिशत बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपये हो गया और निर्यात 37.5 प्रतिशत बढ़कर 3.3 लाख करोड़ रुपये रहा।

टेस्ला की भारत में बिक्री बढ़ाने ईएमआई की घोषणा

नई दिल्ली। दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनी टेस्ला ने भारत में बिक्री को तेज करने के लिए मासिक किस्त योजना (ईएमआई) समेत कई पहल शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की। टेस्ला इंडिया ने बयान में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जाने वाले ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल वाहनों की अदला-बदली पर तीन लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक, ग्राहक अब टेस्ला के मॉडल वाई को 49,000 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाली किस्त (ईएमआई) पर खरीद सकते हैं। इसके लिए केवल छह लाख रुपये का शुरुआती भुगतान करना होगा। टेस्ला इंडिया ने सितंबर, 2025 में इस मॉडल की आपूर्ति शुरू की थी। वाहन डीलरों के निकाय फाडा की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, टेस्ला ने पिछले वर्ष भारत में 225 इकाइयों की बिक्री की।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्प्ले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

राशिफल

मेष संगीत में रुचि बढ़ेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। व्यर्थ के वाद-विवाद से बचने का प्रयास करें।

वृष खर्चों की अधिकता रहेगी। कला एवं संगीत में रुचि हो सकती है। सन्तान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी सम्पत्ति से आय के साधन बन सकते हैं।

मिथुन शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। पठन-पाठन में रुचि बढ़ सकती है। परिवार में आपसी वाद-विवाद की स्थितियां बन सकती हैं।

कर्क क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश प्रवास हो सकता है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा।

सिंह कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। नौकरी के लिए साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा।

कन्या कार्यभार में वृद्धि होगी। बौद्धिक कार्यों से धन प्राप्त होगा। वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ेगा। क्रोध के अतिरेक से बचें। बातचीत में संतुलन बनाकर रखें।

तुला लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। रहन-सहन कष्टमय रहेगा।

वृश्चिक संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। खर्च भी बढ़ेंगे।

धनु स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कला एवं संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है।

मकर आलस्य की अधिकता हो सकती है। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ेगी।

कुंभ क्रोध से बचें। नौकरी के लिए साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। बातचीत में संयत रहें। पठन-पाठन में रुचि रहेगी।

मीन किसी रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। कारोबारी कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

विश्व कैंसर दिवस

जीसीआरआई भारत का भरोसेमंद कैंसर उपचार केंद्र बनकर उभरा

गांधीनगर। गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट , अहमदाबाद ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि वह न केवल गुजरात का प्रमुख कैंसर संस्थान है, बल्कि कैंसर उपचार, अनुसंधान, रोकथाम और प्रारंभिक पहचान के क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र के रूप में भी विकसित हो चुका है। जीसीआरआई के सुदृढ़ीकरण और विस्तार की नींव वर्षों पहले पड़ी थी, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य की स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया था। उसी निरंतर नीति दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में यह संस्थान अब कैंसर उपचार के लिए एक विश्वसनीय राष्ट्रीय रेफरल केंद्र बनकर उभरा है।विश्व कैंसर दिवस 2026 के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में जीसीआरआई में 26,810 से अधिक नए कैंसर मरीज पंजीकृत हुए, जिनमें से 9,140 से अधिक मरीज भारत के विभिन्न अन्य राज्यों से आए।

आरबीआई की तीन दिन की मौद्रिक समीक्षा बैठक आज से

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक बुधवार से शुरू होगी। यह बैठक उस समय हो रही है जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर केंद्रित केंद्रीय बजट पेश किया गया है, महंगाई कम है और हाल ही में लंबे समय से प्रतीक्षित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से बाहरी अस्थिरता समाप्त हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई पिछले साल फरवरी से अब तक रेपो दर में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती कर चुका है और फिलहाल न तो वृद्धि और न ही महंगाई को लेकर कोई बड़ी चिंता है, ऐसे में ब्याज दरों में स्थिरता बनाए रखी जा सकती है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऋण को और सस्ता करने के लिए एक और दर कटौती संभव है। आरबीआई गवर्नर संजय

मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का फैसला शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, /"एमपीसी के रेपो दर पर कायम रहने की संभावना है और यह दर-कटौती चक्र का अंत भी हो सकता है।/" इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि एजेंसी के अनुसार इस समय विराम उचित हैताकि जनवरी, 2026 की खुदरा महंगाई (सीपीआई) और वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त 2025-26 तक के जीडीपी आंकड़ों का आकलन किया जा सके।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना
(ई–टेंडरिंग द्वारा)

कार्य का नाम तथा स्थान	S&T वर्क इन कनेक्शन विद अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट ई.एम.यू. कार शेड गाजियाबाद पोस्ट मर्जर ऑफ शेड्स डिपार्चर लाइन इंटू 4th मैन लाइन बिटवीन दादरी एंड चिपयाना बुजुर्ग।
कार्य की अनुमानित लागत (रू)	Rs. 96,13,894.54/-
धरोहर राशि (रू)	Rs. 1,92,300.00/-
कार्यालय का पता	वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता–C, तृतीय तल, संकेत एवं दूरसंचार ब्रांच, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली–110055
निविदा प्रपत्र जमा करने तथा निविदा खुलने का दिनांक तथा समय।	निविदा प्रपत्र अपलोड करने का समय 03.02.2026 / निविदा खुलने का दिनांक 24.02.2026 15:00 बजे तक
वेब साइट एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहां से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	उत्तर रेलवे की वेब साइट www.ireps.gov.in पर देखें या देखे नोटिस बोर्ड, तृतीय तल, संकेत एवं दूरसंचार ब्रांच, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली–110055

निविदा संख्या: 558-Sig-16-M-TENDER–1471 दिनांक: 03.02.2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 374/26

शब्द पहेली - 6128

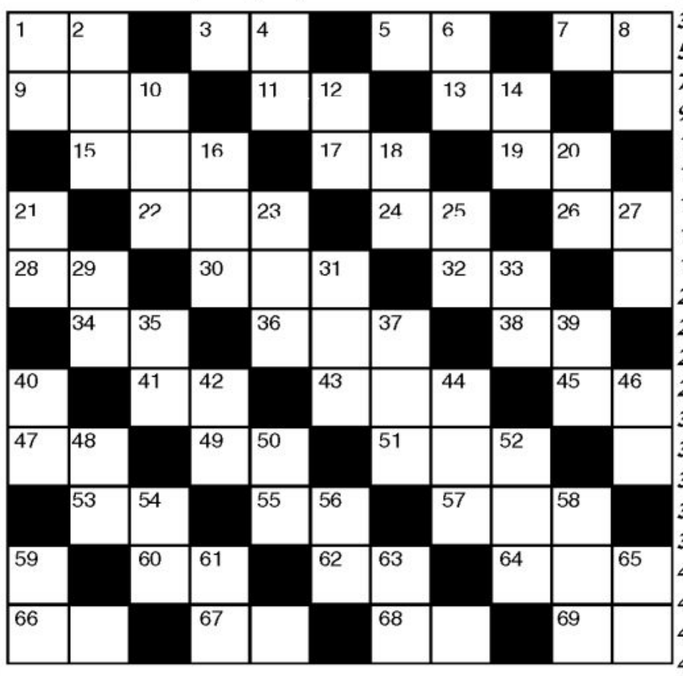

बाएँ से दाए
1. उम्मीद, आशा-2
3. जी, चित्त-2
5. भस्म, खाक-2
7. जाल, फंदा-2
9. चिंतन, सोचना-3
11. ठाठ-बाट-2
13. क्रिकेट में बनते हैं-2
15. एक राशि-3
17. काया, बदन-2
19. एक विदेशी शराब-2
22. बोलने का तरीका-3
24. शालीन, सभ्य-2
26. बल, ताकत-2
28. भैंस जैसा एक पशु-2
30. पुत्री की पुत्री-3
32. कोर्ट में प्रस्तुत दावा-2
34. मोटा आटा-2
36. जुड़वा-3
38. आनंदित-2
41. नौकर, गुलाम-2
43. बूंद-3
45. लक्ष्मी, विष्णुप्रिया -2
47. जंगल, कानन-2
49. मेहंदी -2
51. दृष्टि, निगाह-3
53. बुरी आदत -2
55. बुढ़ापा -2
57. नमस्कार, प्रणाम -3
60. खुमार, सरूर -2
62. भीगा हुआ -2
64. पक्षाघात-3
66. चुनौती-2
67. ऋण, उधार -2
68. भूमि, जमीन-2
69. चस्का, बुरी आदत-2

ऊपर से नीचे
1. फलों का राजा-2
2. साजन, बलमा-3
4. खुमार-2
6. खच्चर, गधा-2
8. वहम, संदेह-2
10. अनुकृति-3
12. झुका हुआ-2
14. आदमी-2
16. वास करना-3
18. आकाश-2
20. घमंड-2
21. बदन-2
23. जातिवाद-3
25. पिघले पत्थर-2
27. रोग, -2
29. हाथ, टैक्स-2
31. लवण-3
33. ताकत-2
35. वचन-2
37. प्रयत्न-3
39. स्थिति -2
40. नवीन-2
42. सच्चा-2
44. राजा-3
46. हार-2
48. टींटी-2
50. गुमान-2
52. पासों का खेल-3
54. काया-2
56. रात्रि-2
58. हुबहू-3
59. समय-2
61. सब्जी-2
63. गाड़ी-2
65. गैस-2

शब्द पहेली- 6127 का हल

■	स	र	ग	ना	■	आ	म	रा	य	■
फि	■	न	ज	ला	■	फि	क	र	■	त
त	ल	■	ल	य	■	स	र	■	ला	ल
र	ह	ना	■	क	हा	र	■	ज	ल	बा
त	र	सा	ना	■	ति	■	ज	ल	च	र
■	■	■	र	ह	म	दि	ल	■	■	■
ब	ग	दा	द	■	ता	■	न	ज	रा	ना
र	म	ल	■	स	ई	स	■	प	ह	रा
ग	ला	■	स	दा	■	ल	स	■	त	य
द	■	ग	ली	चा	■	वा	न	र	■	ण
■	का	श्त	का	र	■	र	म	जा	न	■

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

समझौते की ओर

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बहुप्रतीक्षित रूपरेखा अंतिम रूप लेती दिखने लगी है, तो यह स्वागतयोग्य है। बुनियादी खुशी तो यही है कि भारत पर लगने वाला अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत पर आ जाएगा, इससे दोनों देशों के बीच निश्चित ही व्यापार बढ़ेगा। अपनी घोषणा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका अब भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को तुरंत घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। हालांकि, उन्होंने यह दावा करते हुए भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं कि भारत अब अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य करने पर सहमत हो गया है। अपने मिजाज के मुताबिक, एक कदम आगे बढ़कर ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया है कि भारत अब 500 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और अन्य उत्पादों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने कुछ और भी दावे किए हैं, जिनकी वजह से स्वाभाविक ही भारतीय राजनीति में सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। समझौता अभी विस्तार में सामने नहीं आया है, पर केंद्र सरकार पर हमले शुरू हो गए हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समझौते के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी करे।

वैसे, यह नई बात नहीं है कि भारत के प्रति जिस अधिकार भाव से डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, उससे शंकाओं और सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज ट्रंप उस भारत की तारीफ कर रहे हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था को उन्होंने बीते दिनों मृत ठहरा दिया था। कई बार अधपकी बातों पर भी वह समय से पहले ही टिप्पणी कर देते हैं, जिससे दूसरे देशों के लिए आंतरिक तनाव की स्थिति बन जाती है। गौर करने की बात है, ट्रंप द्वारा की गई घोषणा के बाद भारत सरकार के बयानों में टैरिफ में कटौती की पुष्टि की गई है, समझौते का स्वागत किया गया है, पर ट्रंप द्वारा किए गए कई व्यापक दावों के समर्थन से परहेज किया गया है। यह जरूरी नहीं कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा या 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद व सेवा शून्य टैरिफ पर आयात करेगा। इसमें कोई दोराय नहीं कि समझौते पर प्रारंभिक सहमति बन गई है, पर समझौते के विभिन्न बिंदुओं पर भारत सरकार की ओर से पूरी स्पष्टता के लिए हमें कुछ इंतजार करना चाहिए। पूरी स्पष्टता होने तक विपक्ष को अवश्य राजनीति का मौका मिलेगा। भारत सरकार की विदेश नीति के कमोबेश समर्थक रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवालों पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह अमेरिका से हुए समझौते का पूरा विवरण संसद या देश के सामने रखे।

ट्रेड टैरिफ के विवादित मोर्चे पर अमेरिका की तुलना में भारतीय रवैया ज्यादा संतुलित रहा है और यही संतुलन भारत सरकार को आगे भी जारी रखना चाहिए।

यह गौर करने की बात है कि अमेरिका से होने वाला समझौता किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हित पर अटक रहा था। क्या इस मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बात बन गई है? अगर भारत ने समझौता किया है, तो उसका आकार-प्रकार क्या है? समझौता हर हाल में भारत के हित में होना चाहिए। संदेह नहीं, अमेरिका से होने वाले रोजमर्रा के व्यापार से भारत को ज्यादा फायदा होता आया है और इसी फायदे पर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी के बाद आपसी रिश्तों में तल्खी बढ़ी थी। यह तल्खी ऑपरेशन सिंदूर के बाद और रूसी तेल की वजह से चरम पर पहुंच गई। बेशक, ट्रंप के अति मुखर अमेरिका से तुलना करें, तो भारत का रवैया बहुत संतुलित रहा है। यह संतुलन बने रहना चाहिए। अब अमेरिका से नया समझौता भले हो जाए, पर भारत को अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले

04 फरवरी, 1951

दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय

संयुक्त राष्ट्रीय राजनीतिक समिति तथा महासभा ने इस बीच चीन को आक्रान्ता घोषित कर एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किया है, जिससे सुदूरपूर्व की अशान्ति और भी व्यापक तथा उग्र हो सकती है। भारत ने स्थिति को और न बिगड़ने देने का पूरा प्रयत्न किया किन्तु वह कृतकानर्य हुआ।

राजनीतिक समिति में अमरीकी प्रस्ताव जिस पर कि लेबनान ने एक मामूली संशोधन रखा था, स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 44 तथा विपक्ष में 7 मत आये तथा 9 अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने वाले देश बर्मा, बाइलो रूस, चेकेस्लोवाकिया, भारत, पोलैंड, यूक्राइन तथा सोवियत रूस थे। अमरीकी प्रस्ताव को स्वीकार करने के पूर्व राजनीतिक समिति ने 12 अरब-एशियाई देशों का बहु प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसमें युद्ध-विराम पर विचार करने के लिए चीन सहित सात राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव पर मत लिये जाने के पूर्व भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री बेनेगल नरसिंह राव ने 60 राष्ट्रों की समिति से अपील की थी कि इस प्रस्ताव को ठुकराने के पूर्व शांतिपूर्वक यह विचार कर लेना चाहिये कि इस कार्य के क्या परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा इसका अर्थ होगाः 'जल्दी युद्ध-विराम नहीं हो सकेगा, सुदूरपूर्व की प्रत्येक समस्या उलझी हुई रहेगी, सफल समझौते के लिए अनुकूल वातावरण न रह सकेगा तथा सुदूरपूर्व में तनातनी स्थायी हो जायेगी।' श्री राव ने समिति को सूचित कर दिया था कि चीन की सरकार प्रस्तावित सप्त राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रथम बैठक में ही युद्ध-विराम पर विचार करने को तैयार है किन्तु श्री राव की पुरजोर अपील व्यर्थ गई।

राजनीतिक समिति के निर्णय को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी स्वीकार कर लिया। चीन को आक्रान्ता देश घोषित करने के पक्ष में 44 तथा विपक्ष में 7 मत आये और 9 देश तटस्थ रहे। मतदान के पूर्व श्री राव ने कहा, 'यदि बारह राष्ट्रों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता, तो कोरिया में संभवतः एक सप्ताह के भीतर युद्ध-विराम हो गया होता और विभिन्न गलतफहमियों को मिटाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम सामने आता।' उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रस्ताव से न तो लड़ाई बन्द होगी और न दूसरी समस्याओं के हल की कोई आशा ही उत्पन्न हो सकती है।

अमेरिका से कितना लाभ ले पाएगा भारत

दोनों देशों की इस व्यापारिक सहमति की उम्र निजी रिश्तों से ज्यादा इस बात पर निर्भर करेगी कि रणनीतिक संबंधों को यह आर्थिक राष्ट्रवाद से कितना जोड़ पाती है?

यहां स्कैन करें

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

भारत और अमेरिका के बीच 2 फरवरी, 2026 को हुए प्रारंभिक व्यापार समझौते की घोषणा दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक अहम बदलाव दिखाती है। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने से यह समझौता हमारे निर्यातकों पर तात्कालिक दबाव कम करता है, साथ ही लेन-देन के उस तर्क को भी रेखांकित करता है, जो दूसरे देशों के साथ अमेरिका की आर्थिक नीतियों को नियंत्रित कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद घोषित व्यवस्था, टैरिफ में मिली राहत को रूस से तेल आयात को धीरे-धीरे कम करने और ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि व कोयला आदि क्षेत्रों में अमेरिका से अधिक खरीद के वादे से जोड़ती है। भारतीय अधिकारियों ने हालांकि इस समझौते को 'ऐतिहासिक' व 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने वाला बताया है, लेकिन यह करार एक साल की कठिन बातचीत के बाद सामने आया है। इसमें लगे वक्त से अलग-अलग प्राथमिकताओं वाली दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की गहरी चुनौतियां भी स्पष्ट होती हैं। वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताओं के बीच यह एक तरफ व्यावहारिक भू-राजनीतिक पैंतरेबाजी को उजागर करता है, तो दूसरी ओर ऊर्जा सुरक्षा के मामले में हमारी कमजोरियों और अमेरिका की टैरिफ कूटनीति की सीमाओं को भी रेखांकित करता है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार-वार्ता भारतीय टैरिफ सिस्टम, खासकर खेती व बौद्धिक संपदा से जुड़ी इसकी बड़ी बाधाओं को लेकर अमेरिकी शिकायतों की पृष्ठभूमि में हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को 'टैरिफ किंग' बताया, जिसका नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे दोनों तरफ टैरिफ बढ़े। अगस्त 2025 में यह 50 फीसदी शुल्क के रूप में सामने आया। रूस से रियायती दर पर तेल आयात के विरुद्ध जो अतिरिक्त शुल्क अमेरिका ने लगाया, वह भारत की ऊर्जा चिंताओं के प्रति अमेरिकी रुख में एक बड़ा बदलाव था। भारतीय निर्यातकों, खासकर वस्त्र, रसायन व दवा क्षेत्र के कारोबारियों पर काफी ज्यादा असर पड़ा। नतीजतन, अमेरिका के साथ नई दिल्ली का 'ट्रेड सरप्लस' तेजी से कम हो गया।

अप्रैल 2025 में जो ट्रेड सरप्लस 3.17 बिलियन डॉलर था, वह घटकर नवंबर तक 1.73 बिलियन डॉलर रह गया। भारत के लिए, चुनौती कई तरह की थी : सस्ती ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखना और मॉस्को से अलग होने के अमेरिकी दबाव से निपटना। गौर कीजिए, 2025 में भारत के कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा 40 प्रतिशत से ज्यादा था। इस दबाव ने रणनीतिक स्वायत्तता के पुराने सिद्धांत की सीमाओं को सामने ला दिया। इस सिद्धांत के तहत भारत ने बड़ी ताकतों की होड़ के बीच अपना रुख लचीला बनाए रखा, मगर अब बिखरी हुई विश्व-व्यवस्था में उसके इस रुख के लिए गुंजाइश कम होती जा रही है।

भू-राजनीतिक चुनौतियों ने व्यापार-वार्ता के माहौल को और मुश्किल बना दिया। दरअसल, पहलगाम में 2025 के आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष-विराम कराने के राष्ट्रपति ट्रंप के दावों ने नई दिल्ली को काफी दुखी किया, जिससे इस समझौते की घरेलू राजनीतिक कीमत बढ़ी। 'ऑपरेशन सिंदूर' को रोके जाने और इस्लामाबाद के साथ वाशिंगटन के नए रिश्ते ने अमेरिका को लेकर भारत की सशंकित सोच को और पक्का कर दिया। ठीक इसी समय, यूरोपीय संघ के साथ भारत के समानांतर कारोबारी रिश्ते ने व्यापार-वार्ता में उसकी ताकत को मजबूत किया, इससे हिंद-प्रशांत में चीन से पिछड़ने को लेकर अमेरिका की चिंताएं बढ़ रही थीं।

बहरहाल, साल भर चली इस बातचीत में राजनीतिक नेतृत्व के स्तर की कूटनीति के साथ-साथ बेहद श्रमसाध्य तकनीकी सौदेबाजी भी शामिल रही। हालांकि, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते के मकसद से दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई, पर इसकी प्रगति एक समान नहीं रही। छह दौर की औपचारिक बातचीत हुई और कई अनौपचारिक संपर्क हुए। इस बीच टैरिफ बढ़ने व भू-राजनीतिक कारणों से रुकावटें भी आईं, मगर दोनों पक्षों के प्रभावशाली सलाहकारों की मदद से पिछले दरवाजे की कूटनीति ने इस वार्ता-प्रक्रिया को जिंदा रखा।

इसमें दोराय नहीं कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कमियों को दूर करने में बेहद खामोशी से अहम भूमिका निभाई है। तनावपूर्ण मोड़ों पर व्यापार-वार्ता को आसान बनाने के लिए उन्होंने अपने असर का अच्छा इस्तेमाल किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के शामिल होने से यह सुनिश्चित हुआ कि व्यापार-वार्ता रक्षा, दुर्लभ खनिज और आपूर्ति श्रृंखला को शामिल करते हुए एक बड़ी रणनीतिक बातचीत का हिस्सा बनी रहेगी।

यह कामयाबी एक चिर-परिचित लेन-देन पर टिकी थी। रूस से तेल आयात में धीरे-धीरे कमी लाने और अमेरिकी कारोबारियों को प्राथमिकता देने की इच्छा दिखाकर भारत अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं से करीब से जुड़ने को सहमत हुआ है। बदले में, वाशिंगटन ने टैरिफ में राहत दी है, जिससे हमारे निर्यात को प्रतिस्पर्द्धी देशों के मुकाबले अतिरिक्त योग्यता वापस मिल गई है। फिर भी, इस समझौते की कुछ बातें गौरतलब हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का 500 बिलियन डॉलर की संभावित भारतीय खरीद का दावा जहां उम्मीद जगाता है, वहीं कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्र में समझौते की बातें बहुत साफ नहीं हुई हैं।

यह समझौता आर्थिक राष्ट्रवाद और रणनीतिक जरूरतों के बीच एक मुश्किल रास्ता है, जिससे भारतीय निर्यात और अमेरिका के कृषि राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर भी, अभी यह शुरुआती स्तर पर है, आईपी विवादों और श्रम मानक जैसी चुनौतियों के बीच एक पूरा मुक्त व्यापार समझौता अभी लंबित है। भारत के लिहाज से यह बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा के दौर में अमेरिका के साथ गहरे संबंधों की ओर एक व्यावहारिक बदलाव का संकेत है, पर यह सफलता ऊर्जा स्वायत्तता की कीमत पर हासिल हुई है। अमेरिका के लिए यह दबाव की कूटनीति के जरिये 'अमेरिका फर्स्ट' का उदाहरण है। हालांकि, इसमें एक जोखिम भी है। जैसे, तेल प्रतिबंध तनाव को फिर से बढ़ा सकते हैं।

जैसे-जैसे विश्व-व्यापार बंटेगा, इस समझौते की स्थिरता भारत-अमेरिकी रणनीतिक संबंधों की मजबूती भी परखेगी। इस व्यापारिक सहमति की उम्र निजी रिश्तों से ज्यादा दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को आर्थिक राष्ट्रवाद से जोड़ने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

एआई वीडियो के सहारे आर्थिक मजबूती तलाशते नौजवान

यहां स्कैन करें

किंशुक पाठक | एसोसिएट प्रोफेसर, पंजाब केंद्रीय विवि

इक्कीसवीं सदी डिजिटल क्रांति और विकास का युग है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रत्येक क्षेत्र पर अपना गहन प्रभाव डाल रही है। युवा जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व की सबसे बड़ी आबादी बसती है, परंतु अवसरों की अनुपलब्धता के कारण बेरोजगारी एक विकट चुनौती बनी हुई है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर अक्तूबर 2025 में 14.9 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। ऐसे में, डिजिटल क्रांति के इस युग में एआई वीडियो आत्मनिर्भर बनने के लिए एक क्रांतिकारी संसाधन के रूप में उभर रहा है। एआई वीडियो न केवल 'कंटेंट क्रिएशन' को सहज बनाते हैं, बल्कि वीडियो निर्माण उद्यमिता का भी माध्यम बन रहा है और यह ऑनलाइन कमाई के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। भारत जैसे युवा प्रधान विशाल राष्ट्र में जहां डिजिटल कंटेंट की दरकार दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और यू-ट्यूब जैसे मंच पर 46 करोड़ से भी अधिक यूजर्स हैं, एआई वीडियो हमारे नौजवानों को इस वैश्विक बाजार में प्रवेश करने का उचित अवसर प्रदान कर रहा है।

एआई वीडियो का बाजार साल 2030 तक 9.3 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। युवा इससे एनिमेटेड कहानियां गढ़ सकते हैं।

एआई वीडियो की शुरुआत साल 2010 के दशक में हुई, जब डिजिटल बाजार में डीप लर्निंग मॉडल, जैसे जीएएन (जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स) विकसित हुए। डिजिटल साक्षरता और वैश्विक स्तर पर चुनौती से संभलने के लिए भारत ने इंटेल द्वारा 'एआई फॉर यूथ' कार्यक्रम के माध्यम से एक लाख युवाओं में एआई कौशल विकसित करने का लक्ष्य रखा था। यह कार्यक्रम मूल रूप से स्कूली छात्रों (कक्षा 8 से 12 तक) को लक्षित करके बनाया गया है, जहां 'युवाई' कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को एआई की आधारभूत संरचना से अवगत कराया जाता है। एआई से संबंधित अर्थशास्त्री बताते हैं कि एआई वीडियो का संपादन बाजार साल 2030 तक 9.3 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। युवा इससे एनिमेटेड कहानियां, शैक्षणिक सामग्रियां आदि बना सकते हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कक्षा 10 के एक छात्र ने 'एआई वेबसाइट बिल्डर' का उपयोग करके दो महीने में लगभग 1.5 लाख रुपये कमाये। इसी प्रकार, हाल ही में लोकप्रिय हुआ *बंदर अपना दोस्त* यू-ट्यूब चैनल एआई वीडियो के माध्यम से आज 35 करोड़ रुपये तक सालाना कमा रहा है। एआई उद्यमिता को आर्थिक सशक्तीकरण के रूप में विश्व पटल पर बढ़ावा दे रही हैं 16 वर्षीय प्रांजली अवस्थी। इन्होंने 'डेल्व एआई' नामक एक स्टार्टअप खड़ा किया, जो वर्तमान में 100 करोड़ रुपये का हो चुका है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'युवाई' पहल नौजवानों को एआई उद्यमी बनाने पर ही केंद्रित है। इससे ग्रामीण व शहरी, दोनों वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे। एआई पर आधारित ऑडियो-वीडियो (सिस्टम ऑन चिप यानी एसओसी) का बाजार साल 2030 तक लगभग 67.62 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस तरक्की से यकीनन हमारे युवा वर्ग की सहभागिता बढ़ेगी।

एआई वीडियो युवा वर्ग के लिए आशाजनक तो है, परंतु यह चुनौतियां भी लेकर आता है। भारत में युवाओं में एआई से संबंधित कौशल बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा उनमें बौद्धिक विषमता बढ़ेगी। इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान शिक्षा में निहित है। सरकार को एआई प्रशिक्षण की महत्ता को समझते हुए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, जैसा कि इंटेल का कार्यक्रम कर रहा है। इस प्रकार के अनेक अभियानों की जरूरत है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर हमें एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आकर राष्ट्र के आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान कर सकें। उपर्युक्त तथ्यों और संदर्भों से स्पष्ट है कि यह तकनीक न केवल कमाई के अवसर प्रदान करती है, अपितु व्यक्तिगत रचनात्मकता को भी विस्तारित करती है। यदि सरकारी नीतियों का सही दिशा में क्रियान्वयन हों, तो साल 2030 तक भारत की युवा शक्ति एआई में वैश्विक नेता बनकर विश्व का मार्गदर्शन करेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सुख की खोज और धर्म

सुख की कामना मिटती नहीं। कोई व्यक्ति सुख-दुख की सीमाओं से परे कैसे जा सकता है?

सुख की इच्छा प्रत्येक प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है, जो सुख चाहता न हो और दुख से बचना न चाहता हो। कीट-पतंगों से लेकर मनुष्य तक, सभी शांति और सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे अधिक विकसित और बुद्धिमान है।

मनुष्य और पशु के बीच मूलभूत अंतर उनके सुख की अवधारणा में निहित है। पशुओं का सुख मुख्यतः शरीर-केंद्रित होता है। यदि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल जाए और सोने के लिए सुरक्षित स्थान हो, तो वे संतुष्ट रहते हैं। बहुत कम पशु मानसिक शांति या जीवन के गहरे अर्थ को लेकर चिंतित होते हैं। इसके विपरीत मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वह जानता है कि भौतिक सुख सीमित हैं और वे स्थायी आनंद नहीं दे सकते।

जब से मानव जीवन अस्तित्व में आया है, मनुष्य शाश्वत सुख की खोज में लगा हुआ है। अनुभव ने उसे सिखाया है कि अच्छा भोजन, सुंदर वस्त्र, आरामदायक घर या भौतिक संपत्ति- इनमें से कोई भी स्थायी सुख नहीं दे सकता। जैसे, रसगुल्ला खाने पर क्षणिक आनंद मिलता है, पर निगलते ही उसका स्वाद समाप्त हो जाता है। उसी तरह सुख क्षणिक है, वस्तु सीमित है, इसलिए उससे मिलने वाला आनंद भी सीमित ही होगा।

यहां स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि स्थायी सुख का स्रोत क्या है? उत्तर सरल है- जो स्वयं असीम है, वही असीम और शाश्वत आनंद दे सकता है। सीमित वस्तु अनंत सुख कैसे दे सकती है? सांसारिक ज्ञान सीमित है। चाहे संसार में कितनी ही पुस्तकें क्यों न हों, उनमें संचित ज्ञान की सीमा तय है। इसके विपरीत ब्रह्म विद्या या सहज ज्ञान असीम है। शास्त्रों में इसको ही आध्यात्मिक विज्ञान कहा गया है।

जब तक मनुष्य उस अनंत सत्ता की ओर नहीं बढ़ता, तब तक वह स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसी खोज में मनुष्य ने धर्म की अवधारणा विकसित की। विवेकशील मनुष्य यह समझ गया कि सीमित वस्तुओं के पीछे भागना अंततः निराशा ही देगा। इसलिए बुद्धिमान लोग धर्म साधना के मार्ग को अपनाते हैं। कहा गया है, आध्यात्मिक साधना बचपन से शुरू कर देनी चाहिए।

मनुष्य और पशु में मूलभूत अंतर उनके सुख की अवधारणा में निहित है। पशुओं का सुख मुख्यतः शरीर-केंद्रित होता है। यदि उन्हें पर्याप्त भोजन व सोने के लिए सुरक्षित स्थान हो, तो वे संतुष्ट रहते हैं।

विद्वान हों या अशिक्षित, वीर हों या व्यापारी, श्रमिक हों या धनवान- सभी के लिए धर्म अनिवार्य है। मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ न धन जाता है, न पद, न संबंध। उसके साथ केवल धर्म जाता है। इसलिए मनुष्य को, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, आध्यात्मिक साधना अवश्य करनी चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और यही स्थायी सुख की सच्ची राह है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

एंड्री सिबिहा | विदेश मंत्री, यूक्रेन

सैकड़ों यूक्रेनी युवा कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि रूस ने उन्हें मार डाला। रूस युद्ध खत्म नहीं कर रहा, जबकि कुछ लोग उससे प्रतिबंध हटाने की वकालत कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां इसे 1936 के ओलंपिक जैसी शर्मनाक घटना के तौर पर देखेंगी।

पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया जाए

पाकिस्तान ने ट्वंटी-20 विश्व कप में भारत के साथ होने वाले मैच का बहिष्कार करके क्रिकेट को नूराकुश्ती का मैदान बना दिया है। यह अचरज का विषय है कि पाकिस्तान ने आयोजन में भागीदारी तो स्वीकार की, पर भारत से मुकाबले का बहिष्कार करके खेल को राजनीति से अलग रखने के अपने दावों पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा लिया। करीब एक सप्ताह की अनिश्चितता के बाद लिया गया यह फैसला स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान सरकार की प्राथमिकता खेल भावना नहीं, बल्कि घरेलू और कूटनीतिक दबाव हैं। विश्व कप जैसे वैश्विक मंच पर किसी एक मुकाबले से पीछे हटना न केवल टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्द्धा की भावना को प्रभावित करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की साख पर भी असर डालता है।

यह भी विडंबना है कि पाकिस्तान अन्य देशों के खिलाफ खेलने को तैयार है, लेकिन भारत के सामने उतरने से परहेज कर रहा है। यदि हर देश राजनीतिक मतभेद के आधार पर मैच खेलने से इनकार करने लगे, तो अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। बेहतर होता कि पाकिस्तान खेल को संवाद और सौहार्द का माध्यम मानते हुए मैदान पर उतरता। यहां दिख रहा है कि पाकिस्तान का उद्देश्य टकराव का है, इसीलिए भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर कराने का प्रयत्न करे, जैसे उसने बांग्लादेश के मामले में किया है।

अमृतलाल मारू 'रवि', टिप्पणीकार

पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी-20 विश्व कप में हिस्सेदारी को तैयार है, किंतु वह 15 फरवरी को भारत के विरुद्ध मैच का बहिष्कार करेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ खेल संबंधों की तिलांजलि देने को आतुर है।

विश्व कप का आयोजक भारत है और चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से यह बहुप्रतीक्षित मैच कोलंबो में खेला जाना था, मगर पाकिस्तान ने अंतिम समय में भारत के साथ खेलने से मना कर दिया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से इस्लामी देश पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध माहौल बना हुआ है और वे लोग डरे हुए भी हैं। भारत सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाए। भारत को पाकिस्तान से खेलने या न खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आतंकवाद के समर्थक पाकिस्तान को इससे जो आर्थिक नुकसान होगा, वह उसके लिए एक अच्छा सबक होगा। जरूरी है कि भारतीय टीम भी पाकिस्तानी टीम का बहिष्कार करे।

मोहित सोनी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

विश्व कप बहिष्कार

खेल में राजनीति को घसीटने का नतीजा

ट्वंटी-20 विश्व कप प्रतियोगिता में टीम इंडिया के साथ श्रीलंका में निर्धारित मैच न खेलने का पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे उप-महाद्वीप के क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ने वाला है। अव्वल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था कि इस बचकानी हरकत से उसे ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, दूसरा अगर वह आगे नॉकआउट मैच में भारत के सामने होगा, क्या तब भी उसका यही रुख होगा?

इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत और पाकिस्तान के कटु राजनीतिक रिश्तों ने दोनों देशों के क्रिकेट मुकाबलों को दिलचस्प बनाया। सरहदी अदावतों ने क्रिकेट को भी जंगी अंदाज में खेलने का जुनून पैदा किया। इस भावना का दोहन करने के लिए बाजार ने भी इनके मुकाबलों में खूब मिर्च-मसाले लगाए। इसके बावजूद यह खेल इस खित्ते के दो मुल्कों के प्रति, जो कभी भारत का ही हिस्सा थे, एक भीतरी एहसास का भाव रखते थे। सुनील गावस्कर, कपिलदेव, महेंद्र सिंह धौनी और विराट कोहली को चाहने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कम न थे, इसी तरह इमरान, वसीम अकरम, बाबर आजम के खेल की तारीफ खुले दिल से हिन्दुस्तानियों ने की। कई ऐसे मौके आए, जब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारतीयों ने पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश की टीम की जीत के लिए चीयर्स किए।

सवाल है कि अगर आप दूतावास नहीं बंद कर सकते, उनके साथ आर्थिक रिश्ते खत्म नहीं कर सकते, तो फिर खेलों की बलि क्यों देते हैं? एक क्रिकेटर अपने देश का 'गुडविल एंबेस्डर' होता है, फौजी नहीं। इस तरह के रवैये पर सभी देशों की सरकारों को सोचने की जरूरत है। क्रिकेट को भद्र लोगों का खेल माना जाता है, मगर अब यह देखना बेहद अफसोसनाक है कि खिलाड़ी मैदान पर एक-दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे, एक-दूसरे के अच्छे खेल की तारीफ नहीं कर रहे। भारत और पाकिस्तान मुकाबले को भारत-पाकिस्तान और बांग्लादेश के लगभग 175 करोड़ लोगों में मकबूलियत हासिल है। लोग बड़े चाव से इनके मुकाबलों को देखते हैं। ऐसे में, इस तरह, एक-दूसरे का बहिष्कार करके हम किसका नुकसान पहुंचा रहे हैं? सीधे तौर पर इससे क्रिकेट का नुकसान हो रहा है और क्रिकेटर इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के बौने राजनेताओं ने अपने देश में क्रिकेट का बंटाधार कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई समझौता न करते हुए भी यह देखना चाहिए कि उसके किसी कदम से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कोई नुकसान न पहुंचे।

रवींद्र चक्रवर्ती, टिप्पणीकार

बजट से देश की तरक्की को बहुत बल मिलेगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत के लक्ष्य पर केंद्रित है। आम आदमी, किसानों, कारोबारियों, निवेशकों का ध्यान रखा गया है। आर्थिक सुधारों पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री मानती हैं कि अमेरिका से व्यापार समझौता होने से निवेश में भी तेजी आएगी। बजट, व्यापार समझौते और मौजूदा वैश्विक माहौल से जुड़े मुद्दों पर हिन्दुस्तान के राजनीतिक संपादक मदन जैड़ा और विशेष संवाददाता अरुण चट्ठा ने उनसे विस्तृत बातचीत की है। पेश हैं उसके प्रमुख अंश...

■ अमेरिका के साथ व्यापार समझौता होने जा रहा है। आप इस समझौते को किस रूप में देखती हैं?

यह बहुत ही अच्छी खबर है। अब आयात शुल्क घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा। इससे भारतीय निर्यातकों, उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे बजट को बहुत बल मिलेगा। खास तौर पर भारत के निर्यातक सस्ती दरों पर अपने सामान अमेरिकी बाजार में बेच पाएंगे, जिससे उन्हें वहां प्रतिस्पर्धा कर अपने उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी। हम लगातार मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ (ईयू), न्यूजीलैंड, कतर समेत अन्य देशों के साथ एफटीए किए हैं। आयात शुल्क में भी कटौती हुई है, जिसका लाभ भारत को निर्यात में भी मिल रहा है।

■ आप वित्तीय वर्ष 2026-27 के आम बजट को किस तरह से देखती हैं?

अब हमारा ध्यान आर्थिक विकास को गति देने पर केंद्रित है। हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसी लक्ष्य के तहत हमने कोरोना के बाद के बजटों में उन सभी प्रावधानों को हटाने पर जोर दिया है, जो गैर-जरूरी हैं और निर्यात व कारोबार करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि हम लगातार हर बजट में कोई न कोई सुधार कर रहे हैं। हम खोज-खोज कर गैर-जरूरी प्रावधानों को खत्म कर रहे हैं। अब हमारा बजट विनिर्माण, निर्यात, रोजगार और करदाताओं को सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे भारत दुनिया में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनेगा। कारोबार करने में सुगमता लाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर इस बार के बजट में भी कई सुधार से जुड़े एलान किए गए हैं।

■ बजट में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कमेटी गठित करने का एलान हुआ है। हम किन सुधारों की उम्मीद कर सकते हैं?

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसके लिए देश के पास मजबूत और पारदर्शी बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। ऐसा सिस्टम, जो हर क्षेत्र की मदद करने में सक्षम हो। इसके लिए हमने फैसला लिया है कि पूरे बैंकिंग क्षेत्र का अध्ययन किया जाए और फिर सुधार को लेकर एक गहन रिपोर्ट तैयार हो, जिसके आधार पर विकसित भारत का एक मजबूत और पारदर्शी बैंकिंग सिस्टम तैयार हो। इसलिए कमेटी हर नजरिए से बैंकिंग क्षेत्र का अध्ययन करेगी, जिसमें एनबीएफसी भी शामिल हैं। कमेटी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी, उसी रिपोर्ट के आधार पर बदलाव किए जाएंगे।

■ आयकर विभाग में भी फेस-लेस सिस्टम लाया गया। सुधार तय उद्देश्य के अनुरूप लागू हों, यह कैसे किया जाएगा?

हर विभाग के काम की समीक्षा की जाती है, जो हर महीने होती है। जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर के कार्य की समीक्षा करने के लिए पूरा सिस्टम है। अगर कोई सुधार किया गया है, तो उसका अनुपालन अनिवार्य तौर पर हो, यह हर विभाग केंद्रीय स्तर पर सुनिश्चित करता है। सुधार का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए समीक्षाओं के माध्यम से देखा जाता है कि जो सुधार किए गए हैं, वह लागू हो रहे हैं या नहीं। इसी तरह से बाकी सुधारों पर भी नियमित नजर रखी जाती है।

■ बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ शामिल है? विपक्ष कह रहा है कि बजट में आम आदमी शामिल नहीं है?

बजट में आम आदमी का पूरा ख्याल रखा गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आम आदमी को लाभ होगा। हमने सीमा शुल्क से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं, जिसका लाभ एमएसएमई और अन्य उद्योग संचालित करने वाले आम व्यक्ति को ही मिलेगा। हमने सीमा शुल्क को कम किया है। उससे जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाया है। इसके साथ ही, पहले नियम था कि अगर कोई उद्योग विदेश से कच्चा माल आयात करता है, तो उसे छह महीने के अंदर तैयार करके निर्यात कर कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती थी। अब हमने यह अवधि बढ़ाकर एक वर्ष कर दी है, जिससे आम निर्यातक एवं कारोबारी को लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए शी-मार्ट का एलान किया गया है, जो उनके लिए बाजार उपलब्ध कराएगा। हर जिले में एक महिला हॉस्टल बनाया जाएगा, जो कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा के साथ बेहतर माहौल देगा। लड़के-लड़कियां उद्यमी बनें, इसके लिए एआई ट्रेनिंग से जुड़ी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए हर जिले में एक आईटीआई में एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर तीन से पांच जिलों में एक हब बनाया जाएगा, जहां खेती-किसानी, प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने व अन्य तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सभी का लाभ आम आदमी, युवा और महिलाओं को ही मिलेगा।

> बजट में आम आदमी का पूरा ख्याल रखा गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आम आदमी को लाभ होगा। हमने सीमा शुल्क से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं, जिसका लाभ एमएसएमई और अन्य उद्योग संचालित करने वाले आम व्यक्ति को ही मिलेगा। हमने सीमा शुल्क को कम किया है और उससे जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाया है, इससे भी रोजगार बढ़ेंगे।

■ रोजगार के लिहाज से नए बजट में क्या खास प्रावधान हैं?

देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का 40 प्रतिशत योगदान है, जो रोजगार और निर्यात क्षेत्र के लिहाज से काफी अहम है। हमने बीते तीन बजट में लगातार एमएसएमई क्षेत्रों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का काम किया है। इस बार हमने तय किया है, जो मध्यम आकार की एमएसएमई है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए ज्यादा मदद दी जाए। पहले से प्रोजेक्ट लिंक्ड स्कीम (पीएलआई) भी चल रही है, जिससे देश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक क्षेत्र के विनिर्माण में तेजी आई है। इन सभी क्षेत्रों के तेजी से बढ़ने की वजह से रोजगार के अवसर भी तेजी से पैदा हो रहे हैं। इस बजट में भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री को ऑरेंज इकोनॉमी के तौर पर विकसित करने का भी एलान किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी तरह बजट में नए जलमार्ग बनाने का एलान किया गया है। साथ ही, इन जलमार्गों के किनारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिसमें पोत-नाव की मरम्मत से प्रशिक्षण देने तक का काम किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

■ बजट में उच्च मूल्य कृषि उत्पादों के लिए बड़ा एलान किया गया है। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है?

एक समय था कि जब भारत नारियल का निर्यात करता था, लेकिन अब हम आयात के कगार पर खड़े हैं। जबकि हमारे पास इतना बड़ा समुद्र तटीय क्षेत्र है, पर धीरे-धीरे नारियल का क्षेत्र कम हो रहा है। नारियल के पेड़ पुराने हो गए हैं और नए पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। समुद्री तूफान में पेड़ टूट गए हैं या खराब हो गए हैं, तो किसान उनकी जगह नए पेड़ नहीं लगा रहे हैं। इसी तरह से कोको, काजू और चंदन जैसे उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों की पैदावार भी भारत में तेजी घट रही है, क्योंकि कुछ कृषि उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया काफी खराब व जटिल है। उनके प्रसंस्करण में समय अधिक लगता है और श्रमिकों के हाथ खराब हो जाते हैं। ऐसे में, बजट के माध्यम से हमने उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने और प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने का एलान किया है, ताकि किसानों को उत्पादन बढ़ाने व नए पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

> बाजार की बात करें, तो अनेक निवेशक लाभ लेकर बाहर निकले हैं, वापस नहीं आए हैं। अब समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे बड़े फंड मैनेजरों से बात करेंगे कि वह भारतीय बाजार में निवेश करें। मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता आगे बढ़ने से भी अब निवेशक लौटेंगे।

■ ऐसा माना जा रहा है कि एआई के आने से नौकरियां घटेंगी। वित्त मंत्री के तौर पर आप इसे कैसे देखती हैं?

मेरा मानना है कि एआई के जरिए नए अवसर पैदा होंगे। निजी क्षेत्र से जुड़े कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए, तो अब एआई रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद कर रही है। एआई की मदद से कारोबारियों को कच्चा माल और बाजार खोजने में मदद मिल रही है। इसी तरह से एआई के चलते कृषि, पर्यटन, तकनीक, विनिर्माण, उद्योग और कारोबार में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसलिए सरकार ने बजट में एआई प्रशिक्षण को लेकर बड़ा प्रावधान किया है, जिससे भारत के युवा एआई का प्रशिक्षण लेकर जीवन में आगे बढ़ सकें। एआई भारत में तेजी से अवसर पैदा कर रहा है।

■ सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव है? रुपया कमजोर है। बाजार में गिरावट आ रही है। आप इसे कैसे देखती हैं?

वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव है, जिसका असर भारत में भी कीमतों पर दिख रहा है। बाकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमतों को देखा जाए, तो अब समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। मौजूदा समय में भारत के पास विदेश मुद्रा का भंडार 700 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। बाजार की बात करें, तो अनेक निवेशक लाभ लेकर बाहर निकले हैं, वापस नहीं आए हैं। अब समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे बड़े फंड मैनेजरों से बात करेंगे कि वह भारतीय बाजार में निवेश करें। मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता आगे बढ़ने से भी अब निवेशक लौटेंगे।

■ रक्षा बजट में रिकार्ड एक लाख करोड़ से भी अधिक की वृद्धि हुई है, जो ऑपरेशन सिंदूर के आलोक में स्वाभाविक है, पर बजट भाषण में इसका जिक्र नहीं है?

जहां तक बजट भाषण की बात है, तो हर राज्य, हर क्षेत्र और हर वर्ग चाहता है कि उसका जिक्र हो। जिसका जिक्र नहीं होता है, तो वह नाराज हो जाता है। दूसरी ओर, जब हम बजट में सबको समाहित करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि बजट भाषण लंबा हो गया। हर आवंटन को बजट में शामिल नहीं किया जा सकता।

■ चाबहार पोर्ट के लिए आवंटन नहीं हुआ है, इस पर कई अटकलें चल रही हैं?

चाबहार जैसी परियोजना के लिए जरूरत के हिसाब से आवंटन किया जाता है। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, जब इसमें आवंटन नहीं हुआ। अन्य कोई कारण नहीं है।

■ आपने मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (निम्हंस) की स्थापना का एलान किया है। क्या यह उत्तर प्रदेश में खुल सकता है?

जगह अभी तय नहीं है। इसे हम चैलेंज मोड में स्थापित करेंगे। राज्यों से प्रस्ताव लिए जाएंगे और सबसे अच्छे प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी इसी तरह चैलेंज मोड में खोले जाएंगे।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : आज विश्वास भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। कारोबार में लाभ में वृद्धि होगी।

वृष : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा।

मिथुन : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। माता की सेहत में सुधार होगा। परंतु भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार में सुधार होगा।

कर्क : मन परेशान रहेगा। परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। कारोबार में बदलाव हो सकता है।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। कारोबार में सुधार होगा। किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। परिवार से दूर भी हो सकते हैं।

कन्या : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। आय में कमी व खर्च अधिक की स्थिति होगी।

तुला : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू हो सकता है। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है।

वृश्चिक : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। परंतु मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी कारोबार की शुरुआत हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

मकर : धैर्यशीलता में कमी रहेगी। आत्मसंयत रहें। कारोबार में बदलाव हो सकता है। परिवार व किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। लाभ के अवसर मिलेंगे।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि होगी। वाहन के रख-रखाव और वस्त्रों पर खर्च बढ़ सकते हैं।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। परंतु मन परेशान भी हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का सान्निध्य मिल सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

04 फरवरी, बुधवार, **शक संवत्:** 15 माघ (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 22 माघ मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 15 शब्बान, 1447, **विक्रमी संवत्:** फाल्गुन कृष्ण तृतीया तिथि रात्रि 12.10 मिनट तक पश्चात चतुर्थी तिथि, अतिगंड योग रात्रि 01.05 मिनट तक, वणिज करण। चंद्रमा सिंह राशि में रात्रि 4.20 मिनट तक उपरांत कन्या राशि में।

सूर्य उत्तरायण। शिशिर ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.26 मिनट से रात्रि 12.10 मिनट तक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है। कुछ समय पहले थोड़ा मरम्मत कार्य हुआ था, उसके बाद से ग्राहकी बंद सी है। कृपया उपाय बताएं। -रीना कुमारी, लखनऊ

- आपने अपनी दुकान में वायव्य कोण में एक बेसमेंट बनाया है, जिसके कारण आपके शोरूम में लगभग बीच में गड्ढा हो गया है, जिसकी वजह से आपका काम बंद सा हो गया है, और ग्राहक भी आपसे विमुख हो गए हैं। आप इस बेसमेंट को बंद करवा दीजिए।
- साथ ही अपने शोरूम में दक्षिण पश्चिम दिशा में एक पीतल के बर्तन में चने की दाल एवं हल्दी रखें। दुकान के अंदर उत्तर दिशा में हरे रंग का पिरामिड रखें।

वर्ग पहेली : 8230

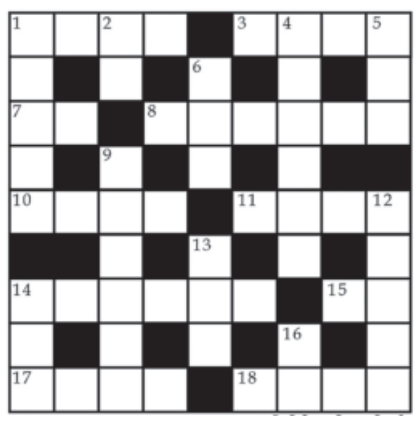

बाएं से दाएं
1. किसी व्यापारी का अभिकर्ता; बिक्री प्रबंधक; वितरणकर्ता (4)
3. ज्ञान; होश-हवास (4)
7. तंतु; डोरा; तागा; सूत्र (2)
8. बहुत थकाना; प्राण ले लेना; मारना (2,4)
10. एकविध; एक जैसे रस वाला सदा एक सा रहने वाला; सदृश्य (4)
11. आयाचित करना; किसी के माध्यम से कुछ मंगाना; किसी को मांगने के लिए प्रेरित करना (4)
14. किसी को कुछ समय के लिए धन देने के लिए कहना; उधार लेने के लिए याचना करना; ऋण लेने के लिए आवेदन देना; कर्ज मांगना (3,3)
15. अंतःकरण; उर; चित्त; दिल (2)
17. नाम के अनुरूप; जैसा नाम (4)
18. इकहरे बदन का; क्षीणकाय; पतला (4)

ऊपर से नीचे
1. अंतर्विरोध; दो बातों का आपसी अंतर; एक अर्थालंकार जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो (5)
2. खून; रुधिर; लहू; लाल रंग (2)
4. झटका लगना; आघात पहुंचना (3,3)
5. बात मनवाने के लिए किसी के द्वार पर अड़ कर बैठना; ठहरना; पकड़ना; स्थापित करना (3)
6. सुख; चैन; आराम; शांति (3)
9. अनेक बार होना; पुनः पुनः होना (2,2,2)
12. हाव-भाव; चटक-मटक (2,3)
13. सम्मेलन; संग; नदियों का मिलन स्थल (3)
14. निकलना; प्रकट होना; प्रत्यक्ष होना; सामने आना; पद आदि में होने वाली उन्नति; समृद्धि (3)
16. दुख; पीड़ा; दया; सिद्ध पुरुष; धर्मगुरु (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8229

सुडोकू : 8212 *आसान

8		5			1	7	2	
					3			
			8	7				1
5	6		9					2
	4			5		9		
9					6		1	3
3				8	9			
			7					
	7	2	4			6		9

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8211

1	9	5	4	2	3	8	7	6
3	4	7	6	9	8	2	5	1
6	8	2	7	1	5	3	9	4
8	7	1	5	6	4	9	3	2
5	2	9	3	8	1	4	6	7
4	6	3	2	7	9	1	8	5
9	5	8	1	4	6	7	2	3
2	3	4	9	5	7	6	1	8
7	1	6	8	3	2	5	4	9

शेयर बाजार में बंपर तेजी, निवेशकों की संपत्ति में ₹12.10 लाख करोड़ का उछाल, रुपये और सोने-चांदी ने भी भरा फर्राटा

व्यापार समझौते की खबर से झूमे शेयर बाजार

उत्साहजनक

मुंबई, एजेंसी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनने की घोषणा से उत्साहित घरेलू शेयर बाजार और भारतीय रुपये में मंगलवार को जबर्दस्त उछाल दर्ज हुआ।

सेंसेक्स ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए 4,205.27 अंक यानी 5.14 प्रतिशत की छलांग लगाई वहीं निफ्टी ने भी 1,252.80 अंक यानी 4.99 प्रतिशत की तेजी के साथ अपनी पहली चार अंकीय बढ़त दर्ज की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 2,073 अंक और निफ्टी 639 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ।

इस सप्ताह दोनों देश करेंगे खुलासा: व्यापार समझौते के तहत अमेरिका भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा रूसी तेल खरीद जारी रखने पर अमेरिका ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद कहा था कि भारतीय वस्तुओं पर जवाबी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा। खबरों के मुताबिक, इसी सप्ताह दोनों देश एकसाथ इस समझौते के बारे में और खुलासा करेंगे।

निवेशकों की पूंजी एक ही कारोबारी सत्र में 12.10 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। दिग्गज कंपनियों में बढ़त के बीच मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों में भी खासी तेजी दर्ज की गई। इस चौतरफा तेजी के बीच बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 12,10,877.45 करोड़ रुपये बढ़कर 4,67,14,754.77 करोड़ रुपये (5.16 लाख करोड़ डॉलर) हो गया। गौरतलब है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को बाजार में 5400 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

5.14 फीसदी की जोरदार तेजी के साथ सेंसेक्स ने की दिन की शुरुआत

4.99 फीसदी की जोरदार तेजी के साथ निफ्टी ने दिन का खाता खोला था

विदेशी निवेश प्रवाह बढ़ने की उम्मीद बढ़ी

जानकारों ने कहा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और रुपये में मजबूती से विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) के प्रवाह की उम्मीद बढ़ी है। अमेरिकी शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से उभरते बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत हुई है और निर्यातोन्मुख क्षेत्रों के लिए परिदृश्य बेहतर हुआ है।

मझोली और छोटी कंपनियों में खास तेजी

दिग्गज कंपनियों में चौतरफा तेजी के बीच मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों ने भी इस तेजी का भरपूर फायदा उठाया। बीएसई पर सूचीबद्ध 3,304 कंपनियों के शेयर चढ़कर बंद हुए जबकि 981 शेयरों में गिरावट रही और 137 अन्य अपरिवर्तित रहे। गौरतलब है कि छोटी कंपनियों के शेयरों में बीते कई महीनों से तेज गिरावट देखी जा रही थी।

इन कंपनियों में तेज उछाल

व्यापार समझौते की खबर से वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री खाद्य निर्यात और विशेष उपयोग वाले रसायन क्षेत्रों से जुड़े शेयरों में तेज उछाल देखा गया। सेंसेक्स की कंपनियों में अदाणी पोर्ट्स में सर्वाधिक 9.12 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। बजाज फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, पावर ग्रिड, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी प्रमुख लाभ में रहीं। हालांकि, तेजी के इस दौर में टेक महिंद्रा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।

ये क्षेत्र तेजी के अगुवा रहे

क्षेत्रवार सूचकांकों में सेवा खंड ने सर्वाधिक 4.86 प्रतिशत की तेजी दिखाई जबकि रियल्टी खंड में 4.79 प्रतिशत, बिजली खंड में 4.79 प्रतिशत, उपयोगिता खंड में 3.92 प्रतिशत, पूंजीगत उत्पाद खंड में 3.71 प्रतिशत और औद्योगिक खंड में 3.44 प्रतिशत की बढ़त रही। इनके अलावा विवेकाधीन उपभोक्ता, धातु, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सेवा खंडों में भी तेजी रही।

तीन दिन बाद चांदी, सोने में तेजी

नई दिल्ली, एजेंसी। चांदी और सोने की कीमतों में तीन दिन की भारी गिरावट मंगलवार को खत्म हो गई और चांदी 24,000 रुपये बढ़कर 2.84 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि मजबूत ग्लोबल संकेतों और कमजोर अमेरिकी डॉलर के बीच सोना 5,000 रुपये, या 3.3 प्रतिशत बढ़कर 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

चांदी की कीमतें 24,000 रुपये, या 9.23 प्रतिशत बढ़कर 2,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं। सोमवार को 52,000 रुपये की गिरावट के बाद यह धातु 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

तीन दिन में 1.44 लाख टूटी थी चांदी : बीते तीन दिन में चांदी की कीमतें 1,44,500 रुपये, या लगभग 36 प्रतिशत गिरकर 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे आ गईं - जो 29 जनवरी को दर्ज किया गया इसका अब तक का सबसे ऊंचा स्तर था। एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 5,000 रुपये, या 3.3 प्रतिशत बढ़कर 1,57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जो सोमवार के बंद भाव 1,52,700 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है।

रुपया 117 पैसे मजबूत हुआ

मुंबई, एजेंसी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनने के बाद भारतीय रुपया मंगलवार को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एशियाई मुद्रा के रूप में उभरा, जिसने एक कारोबारी सत्र में 117 पैसे या 1.33 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। अंत में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.32 (अस्थायी) पर बंद हुआ।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते होने के बाद भारतीय रुपया ढाई सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और इसमें लगभग 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

घरेलू शेयर बाजार में भी लगभग 2.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी और अपेक्षित विदेशी प्रवाह ने भी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा दिया। रुपया 90.30 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 90.05 और 90.52 के दायरे में घूमने के बाद अंत में 90.32 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स			निफ्टी		
83,739	+2072.67		25,727	+639.15	
टॉप गेनर			**टॉप गेनर**		
कंपनी	बंद भाव	बदलाव%	कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
अदाणी पोर्ट्स	1530.90	9.12	अदाणी इंट.	2,206.50	10.58
बजाज फाई.	964.75	6.68	अदाणी पोर्ट	1,532.00	9.19
टॉप लूजर			**टॉप लूजर**		
टेक महिंद्रा	1715.65	-0.47	टेक महिंद्रा	1,712.70	-0.66
बीईएल	439.00	-0.02	बीईएल	438.40	-0.16

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	1,57,700	+5,000
चांदी	2,84,000	+24,000

करेंसी

डॉलर/रुपया

90.32 +1.17

‘शुल्क हटाने से जीवन होगा सुगम’

नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा है कि आम बजट में अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने, ‘बैगेज’ नियमों में ढील जैसे उपायों का मकसद लोगों के जीवन को सुगम बनाना है। चतुर्वेदी ने कहा कि इसके साथ ही सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाकर विनिर्माण को गति देने, घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

अदाणी-लियोनार्डो ने रणनीतिक साझेदारी की

नई दिल्ली। अदाणी समूह और इटली की प्रमुख कंपनी लियोनार्डो ने भारत में एक एकीकृत हेलीकॉप्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। यह विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र सैन्य मांगों को पूरा करने और हेलीकॉप्टर उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और लियोनार्डो ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में इस साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

हल्दीराम स्नैक्स में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी

नई दिल्ली। प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआई ने मंगलवार को वैश्विक निवेश फर्म एल कैटरटन के हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा, "प्रस्तावित गठजोड़ में एल-कैटरटन इंडिया फंड द्वारा हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड (टारगेट) की कुछ शेयरधारिता का अधिग्रहण शामिल है।" एल-कैटरटन इंडिया फंड, एल-कैटरटन इंडिया ट्रस्ट की एक योजना है, जो एक सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष है, जो भारत में निवेश करने का काम करता है।

आठवें वेतन आयोग के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। व्यय सचिव वी वुअलनाम ने मंगलवार को कहा कि आठवें वेतन आयोग ने अपना काम अभी शुरू किया है और यह शुरुआती चरण में है, ऐसे में बजट में फिलहाल इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि कर्ज-जीडीपी अनुपात को अपनाया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम राजकोषीय घाटा छोड़ेंगे। राजकोषीय घाटा महत्वपूर्ण है और हम इस पर नजर रखना जारी रखेंगे।

वुअलनाम ने कहा, ‘बजट में अभी आठवें वेतन आयोग को ध्यान में रखकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका कारण आठवें वेतन आयोग का अभी-अभी गठन हुआ है। सदस्य अपना काम शुरू कर रहे हैं। वे सहायता के लिए अधिकारियों को भी शामिल कर रहे हैं।

- इसके अन्य पहलुओं के बारे में कोई गणना नहीं हुई

उन्होंने कहा कि इसलिए यह बिल्कुल शुरुआती दौर है। अभी तक हमने इसके प्रभाव और अन्य पहलुओं के बारे में कोई गणना नहीं की है, जो हमें समय आने पर पता चलेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग का गठन किया। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

तकनीक क्षेत्र में 1.5 करोड़ रोजगार होंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले दो वर्षों में टेक सेक्टर में नौकरियों की संख्या 1.5 करोड़ को पार कर सकती है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार मोबाइल फोन निर्माताओं, आईटी कंपनियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के साथ अगली पीढ़ी की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई 2.0) को लेकर चर्चा कर रही है।

एक साक्षात्कार में वैष्णव ने कहा, मौजूदा मोबाइल पीएलआई योजना मार्च में समाप्त हो रही है। बजट में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार लगातार उद्योग के साथ बातचीत कर रही है। जैसे ही सहमति बनेगी, योजना को कैबिनेट में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित नए सुधारों से इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) सेक्टर में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। फिलहाल इन क्षेत्रों में एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत अब तक 46 इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें कुल 54,567 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है, जिससे करीब 51,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

टैक्स छूट फायदेमंद

उन्होंने कहा, पूंजीगत उपकरणों के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को बॉन्डेड जोन में पांच साल की टैक्स छूट जैसे कदम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बजट में सेफ हार्बर सीमा बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये करने और आईटी टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने से सॉफ्टवेयर निर्यातकों और जीसीसी को राहत मिलेगी।

निर्यात आठ गुना बढ़ा

वैष्णव ने कहा, आईएसएम 2.0 और क्लाउड डाटा सेंटर टैक्स छूट से भारत को वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेवाएं और जीसीसी से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार लगातार बढ़ रहा है। मंत्री ने बताया कि पिछले दस वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग छह गुना बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात आठ गुना बढ़ चुका है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बन गया है।

कंपोनेंट क्षेत्र मजबूत

मंत्री ने कहा कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होने से भारत अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकेगा और कई कंपोनेंट्स का वैश्विक केंद्र बनेगा। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 25 लाख लोग काम कर रहे हैं। नई योजनाओं से इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में एक नए और ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत कर चुका है।

किस्त योजना शुरू की

नई दिल्ली। टेस्ला ने भारत में बिक्री को तेज करने के लिए मासिक किस्त योजना समेत कई पहल शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की। टेस्ला इंडिया ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जाने वाले ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल वाहनों की अदला-बदली पर तीन लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1, दिल्ली छावनी

निविदा सूचना

दिनांक 20.01.2026 के निविदा सूचना के क्रम में के.वि. क्रमांक 1, दिल्ली कैंट के स्टाफ क्वार्टर के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु सीलबंद निविदाएं को आमंत्रण करने की तिथि 03.02.2026 से बढ़ाकर 10.02.2026 की जाती हैं। विवरण https://no1delhicantt.kvs.ac.in पर उपलब्ध हैं। जमा करने की अंतिम तिथि 10.02.2026 है।

निजी पीएफ ट्रस्ट को लेकर भ्रम दूर

नई दिल्ली, एजेंसी। सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ ने भविष्य निधि ट्रस्ट के लिए आयकर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में रखे गए प्रस्ताव का मंगलवार को स्वागत करते हुए कहा कि विभिन्न नियमों को एक-दूसरे के अनुरूप बनाने और तालमेल बिठाने से हितधारकों के हितों को मजबूती मिलेगी।

श्रम मंत्रालय ने कहा कि बजट में मान्यता-प्राप्त पीएफ से जुड़े आयकर ढांचे को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के वैधानिक और प्रशासनिक प्रावधानों के अनुरूप कर दिया गया है। फिलहाल निजी पीएफ ट्रस्ट को आयकर अधिनियम और ईपीएफ अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट की पात्रता में अंतर है। आयकर प्रावधानों और अधिसूचित निवेश के तरीके भी अलग हैं।

मान्यता की शर्तों में बदलाव

नए प्रावधानों के तहत आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत पीएफ की मान्यता केवल उन्हीं ट्रस्ट को मिलेगी जिन्हें ईपीएफ अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट मिली हुई है। धारा 17 के तहत नियोक्ता अपने कर्मचारियों के पीएफ खातों के प्रबंधन और मासिक ईपीएफ रिटर्न दाखिल करने से छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ ने निवेश के मोर्चे पर कहा कि निवेश मानदंड अभी मौजूदा ईपीएफ ढांचे और अधीनस्थ विधानों के तहत ही नियंत्रित रहेंगे।

फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश रद्द

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के वर्ष 2020 का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें ई-कॉमर्स विक्रेता फ्लिपकार्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की जांच के निर्देश दिए गए थे।

अदालत ने कहा कि फ्लिपकार्ट की दलील पर विचार करते हुए मामले पर फिर से फैसला करना होगा कि उसने जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया था, उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण ने निरस्त कर दिया था।

हिन्दुस्तान

हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बुद्ध मार्ग, पटना - 800001

फोन: 0612 222 3434

कारपोरेट कार्यालय: 5 वीं मंजिल, लोटस टावर, ए ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110025

फोन: 011 6656 1234; **ई-मेल:** hmvlinvestor@livehindustan.com

वेबसाइट: www.hmvl.in; **CIN:** L21090BR1918PLC000013

पोस्टल बैलट की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (**‘अधिनियम’**) की धाराएं 108 के साथ पठित धारा 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियमों 20 व 22 (**‘नियमों’**) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 (**‘सेबी एलओडीआर विनियमन’**), साथ में पठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय (‘एमसीए’) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और इस संदर्भ में जारी बाद के परिपत्रों, 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 **(समग्र रूप से ‘एमसीए परिपत्रों’ के रूप में संदर्भित),** भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक-2 (**‘सचिवीय मानक-2’**), और समय-समय पर संशोधित अनुसार अन्य लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों [उस समय हेतु प्रचलित उनका कोई भी वैधानिक परिवर्तन (नों) या पुनःव्यवस्थापन(नों)] के अनुसार एवं उनके अनुसरण में, सदस्यों को प्रसारित, पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 27 जनवरी, 2026 (‘‘नोटिस’’) में निर्धारित अनुसार निम्नलिखित कारोबार के संबंध में केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया द्वारा पोस्टल बैलट प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया जाता है।

विशेष कारोबार का विवरण

1. श्री समीर सिंह (डीआईएनः 08138465) की कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति तथा परिलब्धियों का अनुमोदन।

अधिनियम, एमसीए परिपत्रों और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी ने मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को ई-मेल के जरिए नोटिस उन सदस्यों को प्रेषित कर दिया है जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारण के मामले में)/कम्पनी के पंजीयक तथा शेयर हस्तांतरण एजेंट (भौतिक शेयरधारण के मामले में) के पास पंजीकृत है। विस्तृत प्रक्रिया/ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर अनुदेश नोटिस में निर्दिष्ट किए गए हैं।

अन्य विवरण अधोलिखित अनुसार हैं:-

1. वोटिंग अधिकारों की गणना और नोटिस भेजने के प्रयोजन हेतु कट-ऑफ तिथि, **शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026** (‘कट-ऑफ तिथि’) है। केवल वे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों की पंजिका/लाभकारी स्वामियों की सूची में शामिल होंगे। ऐसे व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं वे इस नोटिस को केवल सूचना उद्देश्य हेतु मानें।
2. ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु कम्पनी ने एजेंसी के तौर पर नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (‘एनएसडीएल’) की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग सुविधा **बुधवार, 04 फरवरी, 2026 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होकर गुरूवार, 05 मार्च, 2026 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स.) तक** खुली रहेगी। उसके बाद, ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा नियोग्य कर दिया जाएगा। यदि एक बार सदस्य द्वारा रिजोल्यूशन पर वोट डाल दिया जाता है तो वह सदस्य बाद में उसे बदलने के लिए अनुमत्य नहीं होगा/होगी।
3. **ईमेल पता को पंजीकृत करने/नवीकृत करने का तरीका:**
   - जिन सदस्यों ने डिमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर रखे हुए हैं से अनुरोध किया जाता है कि अपने डिपॉज़िटरी पर्टिसिपेंट्स के माध्यम से अपने संबंधित जमाकर्ताओं के पास अपने ईमेल पते और मोबाइल नम्बर पंजीकृत करवाएं।
   - जिन सदस्यों ने भौतिक रूप में शेयर रखे हुए हैं और कम्पनी या आर.टी.ए. के पास अपने ई-मेल पता सहित अपने के.वाई.सी. विवरणों को पंजीकृत/नवीकृत नहीं किया है, निम्नलिखित लिंक: **https://ris.kfintech.com/** से संबंधित प्रपत्रों को डाउनलोड करके ऐसे विवरणों को पंजीकृत/नवीकृत कर सकते हैं और केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड यूनिटः हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500032 को फॉर्म में अपेक्षित अनुसार उनके विवरण के साथ विधिवत भरकर आग्रह पत्र के साथ तथा ऐसे दस्तावेज संलग्न कर उसे भौतिक रूप में कर सकते हैं।
4. पोस्टल बैलट के परिणामों की घोषणा अध्यक्ष द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा **शनिवार, 07 मार्च, 2026** को या उससे पहले की जाएगी। श्री संकेत जैन, प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव की संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ वोटिंग परिणाम, कम्पनी की वेबसाइट यानी **https://www.hmvl.in** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट यानी **www.evoting.nsdl.com** पर प्रदर्शित किया जाएगा। परिणाम को स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई व एनएसई की वेबसाइटों क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी सूचित किया जाएगा।
5. ई-वोटिंग के संबंध में कोई पूछताछ/शिकायत होने पर, **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों के लिए उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चंस (FAQs) और ई-वोटिंग यूजर मेन्युअल देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, सहायक उपाध्यक्ष (एनएसडीएल) को **evoting@nsdl.com** पर आग्रह भेज सकते हैं या नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तृतीय तल, नमन चैम्बर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400051, महाराष्ट्र, भारत को लिख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते **हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड**

हस्ताक्षर/-

दिनांक: 03 फरवरी, 2026 **निखिल सेठी**

स्थान: नई दिल्ली **कम्पनी सचिव**

HT

एचटी मीडिया लिमिटेड

CIN: L22121DL2002PLC117874

पंजीकृत कार्यालय: हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

फोन: +91-11-66561355

ईमेल: investor@hindustantimes.com; **वेबसाइट:** www.htmedia.in

कारपोरेट कार्यालय: 5वां तल, लोटस टावर, ए ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली - 110025

फोन: +91-11-6656 1234

पोस्टल बैलट की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित धारा 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, (**‘अधिनियम’**), कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियमों 20 व 22 (**‘नियमों’**) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 (**‘सेबी एलओडीआर’**), साथ में पठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय (‘एमसीए’) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और इस संदर्भ में जारी बाद के परिपत्रों, नवीनतम जारी 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 **(समग्र रूप से ‘एमसीए परिपत्रों’ के रूप में संदर्भित),** भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक-2 (**‘सचिवीय मानक-2’**), और समय-समय पर संशोधित अनुसार अन्य लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों (उस समय हेतु प्रचलित उनका कोई भी वैधानिक परिवर्तन (नों) या पुनःव्यवस्थापन(नों)) के अनुसार एवं उनके अनुसरण में, सदस्यों को प्रसारित, पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 28 जनवरी, 2026 (‘‘नोटिस’’) में निर्धारित अनुसार निम्नलिखित कारोबार के संबंध में केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया द्वारा पोस्टल बैलट प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया जाता है।

विशेष कारोबार का वर्णन

कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री समीर सिंह (डीआईएनः 08138465) की नियुक्ति और परिलब्धियों का अनुमोदन।

अधिनियम, एमसीए परिपत्रों और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी ने **मंगलवार, 03 फरवरी, 2026** को ई-मेल के जरिए नोटिस उन सदस्यों को प्रेषित कर दिया है जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारण के मामले में)/कम्पनी के पंजीयक तथा शेयर हस्तांतरण एजेंट (भौतिक शेयरधारण के मामले में) के पास पंजीकृत है। विस्तृत प्रक्रिया/ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर अनुदेश नोटिस में निर्दिष्ट किए गए हैं।

अन्य विवरण अधोलिखित अनुसार हैं:-

1. वोटिंग अधिकारों की गणना और नोटिस भेजने के प्रयोजन हेतु कट-ऑफ तिथि, **शुक्रवार 30 जनवरी, 2026** (‘कट-ऑफ तिथि’) है। केवल वे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों की पंजिका/लाभकारी स्वामियों की सूची में शामिल होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तारीख को सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस को केवल जानकारी हेतु मानें।
2. ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु कम्पनी ने एजेंसी के तौर पर नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (‘एनएसडीएल’) की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग सुविधा **बुधवार, 04 फरवरी, 2026 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होकर गुरूवार, 05 मार्च, 2026 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स.) तक** खुली रहेगी। उसके बाद, ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। यदि एक बार सदस्य द्वारा रिजोल्यूशन पर वोट डाल दिया जाता है तो वह सदस्य बाद में उसे बदलने के लिए अनुमत्य नहीं होगा/होगी।
3. ईमेल पता को पंजीकृत करने/नवीकृत करने का तरीका:
   - जिन सदस्यों ने डिमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर रखे हुए हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से अपने संबंधित जमाकर्ताओं के पास अपने ईमेल पते और मोबाइल नम्बर पंजीकृत करवाएं।
   - जिन सदस्यों ने भौतिक रूप में शेयर रखे हुए हैं और कम्पनी या आर.टी.ए. के पास अपने ई-मेल पता सहित अपने के.वाई.सी. विवरणों को पंजीकृत/नवीकृत नहीं किया है, निम्नलिखित लिंक https://ris.kfintech.com/ से संबंधित प्रपत्रों को डाउनलोड करके ऐसे विवरणों को पंजीकृत/नवीकृत कर सकते हैं और केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड यूनिटः एचटी मीडिया लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत- 500032 को अपने विवरण के साथ विधिवत रूप से आग्रह पत्र को भरकर एवं प्रपत्र में अपेक्षित अनुसार अपने ऐसे दस्तावेजों को अनुलग्न करके इसे भौतिक रूप में भेज दें।
4. पोस्टल बैलट के परिणामों की घोषणा अध्यक्ष द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा **शनिवार, 07 मार्च, 2026** को या उससे पहले की जाएगी। श्री संकेत जैन, प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव की संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ वोटिंग परिणाम, कम्पनी की वेबसाइट यानी www.htmedia.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किया जाएगा। परिणाम को स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई व एनएसई की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी सूचित किया जाएगा।
5. ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में कोई पूछताछ होने पर, सदस्य वेबसाइटः www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों हेतु उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल को देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक उपाध्यक्ष (एनएसडीएल) को evoting@nsdl.com पर आग्रह कर सकते हैं या नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तृतीय तल, नरीमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400051, महाराष्ट्र, भारत को लिखित आग्रह कर सकते हैं या 022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते **एचटी मीडिया लिमिटेड**

हस्ता0/-

दिनांक: 03 फरवरी, 2026 **मनहर कपूर**

स्थान: नई दिल्ली **(ग्रुप जनरल काउन्सल एवं कम्पनी सचिव)**

गोल्डमैन ने वृद्धि अनुमान बढ़ाया

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा के मद्देनजर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वास्तविक वार्षिक वृद्धि के अपने 2026 के अनुमान को 0.20 प्रतिशत बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है।

गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि शुल्क कम होने से भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। चार प्रतिशत के बराबर का वस्तु निर्यात अमेरिकी उपभोग मांग पर निर्भर करता है।

ब्याज दरों में कटौती पर विराम संभव

नई दिल्ली, एजेंसी। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस बार ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। ऐसा होने पर कर्ज की किस्त घटने की संभावना कम हो जाएगी।

जानकार इस संभावना के पीछे कई तर्क दे रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, 4 से 6 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली में आरबीआई की बैठक में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती पर फिलहाल विराम लगाने की उम्मीद है। हालांकि केंद्रीय बैंक लिक्विडिटी, बॉन्ड बाजार की स्थिरता और करेंसी से जुड़े जोखिमों को संभालने के लिए सीधे कदम उठा सकता है। जानकारों का कहना है कि हाल ही में अमेरिकी फेड ने दरों में कटौती या बढ़ोतरी न करने का फैसला किया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजर्व बैंक भी इस बार रेपो रेट में कटौती नहीं करेगा। वहीं बजट और अमेरिका से समझौते का असर फैसले पर पड़ता दिख रहा है।

आरबीआई ने तरलता बढ़ाने के कई उपाय किए

आरबीआई ने हाल ही में तरलता बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिसके तहत बैंकिंग सिस्टम में दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डाली जाएगी। इसके लिए ओपन मार्केट में बॉन्ड खरीद, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप और वेरिएबल रेट रेपो ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कदम मौजूदा लिक्विडिटी और वित्तीय हालात की समीक्षा के बाद उठाए गए हैं। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, आरबीआई ने ओएमओ के जरिए 6.6 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डाली है।

सख्ती | आरबीआई ने सोने के दामों में तेज उछाल के बाद मिलने वाली शिकायतों के मद्देनजर उठाया कदम

गोल्ड लोन कारोबार पर निगरानी बढ़ाई

नई दिल्ली, एजेंसी। सोने की कीमतों में हालिया तेज उतार-चढ़ाव और गोल्ड लोन कारोबार में असाधारण बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पर करीबी निगरानी शुरू कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय बैंक यह परख रहा है कि ऋणदाता जोखिम प्रबंधन, मूल्यांकन और नियामकीय मानकों का कितना पालन कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष में बैंकों का गोल्ड लोन बकाया तेजी से बढ़कर करीब 3.8 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। यह उछाल मुख्य रूप से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ा है, क्योंकि समान मात्रा के सोने पर लोन की वैल्यू अपने-आप बढ़ जाती है।

आरबीआई की चिंता तीन प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित है।

पहला, गोल्ड लोन में तेज वृद्धि कहीं अत्यधिक जोखिम तो नहीं पैदा कर रही। दूसरा, क्या सभी ऋणदाता एलटीवी सीमा, ग्राहक के पुनर्भुगतान प्रोफाइल और उचित मूल्यांकन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन कर रहे हैं। तीसरा, नीलामी और रिकवरी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित है या नहीं।

आरबीआई ने यह कदम सोने की कीमतों में हाल ही में तेज उतार-चढ़ाव और गोल्ड लोन की बढ़ती मांग के कारण उठाया है।

दाम गिरने से संकट पैदा होगा

केंद्रीय बैंक विशेष रूप से उन संस्थाओं पर नजर रख रहा है जिनके पोर्टफोलियो में गोल्ड लोन का अनुपात तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सोने की कीमतों में तेज गिरावट आती है, तो कुछ खातों में संकट की स्थिति बन सकती है, जिससे अतिरिक्त मार्जिन कॉल या प्रोविजनिंग की जरूरत पड़ेगी।

नैतिकता वह रवैया है, जिसे हम उन लोगों के प्रति भी अपनाते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं। - ऑस्कर वाइल्ड

महीनों तक चले व्यापारिक तनाव, टैरिफ युद्ध और कूटनीतिक तल्खियों के बाद आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनना महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल अभी अनुत्तरित ही हैं।

समझौता और सवाल

महीनों तक चले व्यापारिक तनाव, टैरिफ युद्ध और कूटनीतिक तल्खियों के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनना निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बावजूद, यह पूरा परिदृश्य जितना आशाजनक दिखता है, उतने ही सवाल भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी का पारस्परिक टैरिफ लगाया था, जिसके बाद रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अतिरिक्त 25 फीसदी का दंडात्मक शुल्क थोप दिया गया, जिससे कुल टैरिफ 50 फीसदी तक पहुंच गया था। जवाब में भारत ने व्यापार के संदर्भ में अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दूसरे वैश्विक बाजारों की ओर रुख किया। नतीजा यह हुआ कि पिछले एक वर्ष में भारत अमेरिका से पहले ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते कर चुका है। भारत पिछले वर्ष से तमाम अड़चनों के बावजूद अमेरिका के साथ भी व्यापार समझौते के लिए वार्ता जारी रखे हुए था, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ महज एक फोन कॉल के बाद ट्रंप टैरिफ को कम करने के लिए मजबूर हुए, उससे यह मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि भारत के यूरोपीय संघ के साथ हुए ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते के बाद वह कई तरह के अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक राजनीति के दबाव में थे। हालांकि ट्रंप का यह दावा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से 500 अरब डॉलर के विभिन्न उत्पाद खरीदने का वायदा किया है, यह देखते हुए कि फिलहाल भारत अमेरिका से 50 अरब डॉलर से भी कम का आयात करता है, शंका ही पैदा करता है। भारत के आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी भले ही कम हो गई हो, लेकिन यह अभी भी कुल आयात का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। ऐसे में, ट्रंप का यह दावा भी, जिस पर अब तक भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, विश्वासयोग्य नहीं लगता कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनाज, जीएम उत्पादों इत्यादि, जिनको विदेशी बाजार के लिए खोलने का भारत विरोध करता रहा है, उस रुख पर भारत अब भी कायम है। हां, यह जरूर है कि प्रस्तावित 18 फीसदी का टैरिफ बांग्लादेश, श्रीलंका, और वियतनाम समेत कई दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से कम है। यह घोषणा भारत और अमेरिका को निस्संदेह भू-राजनीतिक रूप से फिर से एक साथ लाएगी। इसके बावजूद यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यापार समझौतों की अपनी जटिलताएं होती हैं, ऐसे में, जब तक इससे जुड़े सवालों के स्पष्ट जवाब सामने नहीं आते, तब तक इसे द्विपक्षीय संबंधों में एक सकारात्मक मोड़ मानना ही बेहतर होगा।

जीना इसी का नाम है

हम शायद ग्रेटर नोएडा के गड्ढे में डूबे युवा की चीखों को भुला कर आगे बढ़ जाएंगे, पर समय हमसे विचलित करने वाले सवाल पूछता रहेगा। किसी की जान बचाना कोई कौशल या पानी के तापमान का विषय नहीं है, बल्कि जीवन में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराना है और जीना इसी का नाम है।

नन्दितेश निलय
स्पीकर, लेखक एवं एथिक्स प्रशिक्षक

चलिए लेख की शुरुआत उन दो घटनाओं से करें, जहां एक घटना ने भारतीय मध्यवर्ग के शहर में खिसकते और सिकुड़ते सामाजिक व्यवहार की छवि से पूरे देश को झकझोर डाला, वहीं दूसरी घटना ने भारत के गांवों में बसे जनमानस की सेवा और साहस के मूल्यों से हमें रूबरू कराया। ऐसा लगा, मानो साहस, सेवा और संवेदना जैसे मूल्य शहर की सीमाओं को छोड़ अब सिर्फ गांवों की परिधि में घूम रहे हैं। उस ग्रामीण जीवन में, जहां न्यूटन के ऑर्डरली कॉस्मोस के केंद्र में अब भी मनुष्य और उसकी जान की नैतिक उपस्थिति बनी हुई है और सारे मानवीय मूल्य एक खास परिधि में उसके ही इर्द-गिर्द घूम रहे हैं।

दोनों घटनाओं में इन्सानों की जान सांसत में रही। दो पायलट अपने जहाज को लिए बहुत बड़े जलकुंभी में क्रैश कर जाते हैं, जो गहरा व फैला हुआ था और बहुत ठंडा भी। दोनों पायलट उस जहाज के अंदर कैद थे और शीशा भी बंद। तभी कुछ ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ती है। उनको बचाने के लिए, मनुष्य की जान की कीमत को सबसे ऊपर मानकर, गांव के दो व्यक्ति, पानी की शीतलता नहीं नापते, बल्कि बिना झिझके उस जलकुंभी में कूद पड़ते हैं। उनको तो उस समय बस एक ही बात समझ में आ रही थी कि कहीं वे पायलट हवाई जहाज संग डूब कर मर न जाएं और यह गांव की नजरों के सामने भला कैसे संभव हो पाता? उन्हें यह मालूम था कि किसी की जान बचाने के लिए शिक्षा और अशिक्षा की दीवारें कभी बाधा नहीं बनतीं और न ही जन्म व मृत्यु का दर्शन उनकी बेड़ियां बन सकता है। उन्हें यह इल्म था कि वे, जो दूसरों को बचाना चाहते हैं, स्वतंत्र मुल्क के आजाद नागरिक हैं। उन्हें यह ज्ञान था कि अपनी जान बचाने से ज्यादा दूसरों की जान बचाना ही जीवन का दर्शन है।

वे ईंट से शीशे को तोड़ते हैं और दोनों पायलट को सुरक्षित निकाल लेते हैं। हालांकि, उनमें से एक की तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ जीवन और मृत्यु से लड़ते पायलट डूबते दिख रहे थे। और वे दोनों यह ठान बैठे थे कि वे उन्हें मरने नहीं देंगे, क्योंकि इन्सान की जान अब भी उनकी नजरों में सबसे कीमती थी। और जान बचाना सबसे बड़ा साहस। वे शहर की निष्ठुरता व चुप्पी से अपने गांव को डुबोना नहीं चाहते थे।

वहीं दूसरी ओर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चकाचौंध में डूबे एनसीआर का शहरी जीवन उस लड़के को नहीं बचा सका, जो करीब दो घंटे तक मानव निर्मित दानवीय गड्ढे रूपी तालाब में अपनी कार संग डूबता रहा। उस स्थान से कुछेक सौ मीटर दूर टूटी पुलिया पर शहर की भीड़ जमा थी, मानो कोई शूटिंग चल रही हो और हर आदमी यह तय कर बैठा था कि पानी में किसी और के लिए भला वह क्यों कूदे। उधर डूबते पुत्र का पिता बार-बार मिन्नतें कर रहा था, पर शायद उन्हें उस धुंध में यह नहीं नजर आ रहा था कि जो भीड़ खड़ी है, वह उभरते शहर की थी, जो वीडियो तो बना सकती है, अफरा-तफरी तो दिखा सकती है, जमीन तो खरीद सकती है, पर वह पानी की शीतलता जानती है और यह भी कि औरों की जान सस्ती होती है। दो घंटे तक यह मानवीय क्रूरता की कहानी चलती रही। वह पिता असहाय दौड़ता रहा और शहर की निष्ठुर भीड़ जिसके लिए उसकी पत्नी और बच्चा ही 'जय हिंद' हैं, बिना किसी हिचक के यह फैसला कर चुकी थी कि वह पानी में नहीं उतरेगी, और न ही उतरेगा उनकी निष्ठुरता का वह आवरण, जो शहर के उस सामाजिक व्यवहार की क्रूरता और उन चेहरों को बचा के रख जाता है, जिनके लिए सिर्फ अपनी जान की कीमत होती है, बाकी कुछ नहीं।

वह लड़का अपनी कार संग डूब गया और डूब गई मानवीयता भी। डूब गया वह सब कुछ, जो शहर के स्कूलों और कॉलेजों की किताबों में संवेदना, साहस और देखभाल जैसे मूल्यों के तौर पर भी छपा था। जो बचा, वह सिर्फ वीडियो था, वह निष्ठुरता थी, उस पिता की सूखी आंखें थीं, जो ठंडे तापमान के बिना भी जमना सीख चुकी थीं। इसी सर्द रात उस डूबते शहर को बचाने, वह कम पढ़ा-लिखा एक गिग वर्कर भी आया, पागलों की तरह शहर को आवाज देता रहा, और पानी में उतरने के लिए निकल पड़ा। पर किसी ने साथ नहीं दिया, आखिर किसी गांव और शहर के बीच एक सामाजिक व्यवहार की दूरी तो होती ही है। और वह अकेला उस लड़के को ढूंढता रहा, पर तब तक निस्तेज शहर के ठंडेपन से हारकर वह लड़का जल समाधि ले चुका था। वह कार और फोन, जो शहर के अभिन्न साथी हैं, उसके संग ही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे फिर से ठीक हो सकते हैं। आदमी नहीं बचा, बाकी तमाशबीन भीड़ बच गई। किसी के लिए जीना और मरना किसी पाठ्यक्रम का विषय नहीं होता। पर सभी को मालूम था कि तैरना एक कौशल है तथा तमाशबीन बनकर नंगी आंखों से झांकना और खुद को बचाना भी एक सामाजिक कौशल है।

अंत में जिक्र उस घटना से जुड़े उन कर्मचारियों का भी, जिनके पास अपनी जान बचाने की तमाम संभावनाएं थीं और शायद समय व इतिहास उन व्यक्तियों को गलत नहीं ठहराता। लेकिन वे नहीं भागे। तमाम निकासी होने के बावजूद सारे कर्मचारी अपने अतिथियों को बचाने में लगे रहे। ग्राहक ही भगवान है, मानो उस दिन चरितार्थ हो रहा था। वे किसी शहर के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि रतन टाटा के उन मूल्यों के सिपाही थे, जो टाटा और होटल ताज की दीवारों और मुंबई के शहरी जीवन से ज्यादा ऊंचा और मजबूत था। और बाद में 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान मुंबई के मशहूर ताज होटल के कर्मचारियों की बहादुरी भरी प्रतिक्रिया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक केस स्टडी बन गई है, जिसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रोहित देशपांडे की मल्टीमीडिया केस स्टडी *टेरर एट द ताज बॉम्बे: कस्टमर-सेंट्रिक लीडरशिप* में डॉक्यूमेंट किया गया है। उस अध्ययन से यह भी बात सामने आई कि उनमें से तमाम कर्मचारी उन छोटे शहरों या गांवों से आते थे, जहां अब भी मनुष्य के होने का बोध बचा था।

शायद कुछ दिनों बाद यह शहरी जीवन सब कुछ आसानी से भुला दे, लेकिन गुरुत्व पर स्थिर शहर से बार-बार समय यह पूछेगा कि अगर पानी ठंडा नहीं होता, भीड़ को अगर तैरना आता, तो उस गिग वर्कर के साथ कोई और भी पानी में कूदता क्या? उस पिता को कोई हौसला देता क्या? पता नहीं क्या होता? लेकिन कोई वस्तु मरती नहीं, मरते इन्सान और जानवर हैं; इसलिए कार तो बच गई, लेकिन वह लड़का डूब गया। मरता मनुष्य है और शायद शहर को इस दंश से कुछ मुक्त करने और डूबने से बचाने लिए दूर गांव में उन दो पायलटों की जान बचाकर उन ग्रामीणों ने यह बताया कि किसी की जान बचाना कोई कौशल या तापमान का विषय नहीं, बल्कि जीवन में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराना है और जीना इसी का नाम है।

जीवन धारा

एपीजे अब्दुल कलाम

पृथ्वी पर हमारी उपस्थिति केवल देह तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे भीतर विद्यमान मूल तत्व की निरंतरता को इंगित करती है। संपूर्ण मानव जाति से हमारा संबंध है, क्योंकि मानवता के भीतर एक ही परम तत्व व्याप्त है।

हमारा जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं

मेरे लिए मुक्ति का अर्थ सबसे पहले अज्ञान के अंधकार को दूर करना है और उसके बाद मन में जमी उन विकृतियों को खत्म करना है, जो जीवन के मूल तत्व को ढक लेती हैं। मनुष्य का जीवन एक सतत विकास यात्रा है, जिसे हम तीन चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण है-परम तत्व की उपस्थिति का बोध। दूसरा चरण है-उस परम तत्व के साथ सह-अस्तित्व का अनुभव, जहां हम यह समझने लगते हैं कि हमारा जीवन किसी एक शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक चेतना से जुड़ा है। तीसरा और अंतिम चरण है-उस परम तत्व में ही पूर्णतः अभिभूत हो जाना, जहां व्यक्ति स्वयं को एक व्यापक उद्देश्य का साधन मानने लगता है।

यह जीवन-पथ का ज्ञान हर व्यक्ति को एक ही समय पर नहीं मिलता। कुछ आत्माओं को यह बोध बहुत कम उम्र में हो जाता है-जैसे रामानुजन या थॉमस एडिसन, जिन्होंने जिज्ञासा को अपना पथ बना लिया। कुछ को यह समझ जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त होती है-जैसे महात्मा गांधी, जिन्होंने अनुभवों की अग्नि में तपकर सत्य को पहचाना। कुछ व्यक्तियों में यह प्रयोजन स्पष्ट और साकार रूप में प्रकट होता है-जैसे नेल्सन मंडेला और वर्गीज कुरियन, जिनका जीवन उद्देश्य समाज के सामने दीपस्तंभ की तरह खड़ा दिखाई देता है। वहीं कुछ महान व्यक्तित्वों में यह प्रयोजन सूक्ष्म, निराकार और लगभग अदृश्य रहता है-जैसे सतीश धवन और काकरला सुब्बाराव, जिनकी साधना परिणामों में बोलती है, प्रचार में नहीं। एक बार जब मनुष्य अपने मार्ग को पहचान लेता है, तब वह अपनी आत्मिक शक्ति और जीवन के वास्तविक मूल्यों के विकास के लिए असीम संभावनाएं खोज लेता है। यह विकास जाग्रत अवस्था में जीवन जीने से आता है, यानी हर अनुभव को पूरी संवेदनशीलता के साथ स्वीकार करने और उससे सीखने से। अब्राहम लिंकन और नेल्सन मंडेला ने इस यात्रा में वर्षों लगाए, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। यह साधना मनुष्य को मूल तत्व के अस्तित्व की खोज कराती है और उसके विविध स्वरूपों की पहचान के जरिये उसे एक शिखर तक पहुंचाती है। सीवी रमण के जीवन में यह खोज इंग्लैंड से लौटते समय समुद्र यात्रा के दौरान आरंभ हुई, जब प्रकृति के सौंदर्य ने उनके भीतर वैज्ञानिक जिज्ञासा को नई दिशा दी। गांधी जी के जीवन में यह चिंगारी दक्षिण अफ्रीका में तब जली, जब उन्हें रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंका गया और अपमान ने उन्हें आत्मबल की शक्ति से परिचित कराया।

इससे हमें यह समझ मिलती है कि पृथ्वी पर हमारी उपस्थिति केवल देह तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे भीतर विद्यमान मूल तत्व की निरंतरता है। इसी बोध से हमें यह एहसास होता है कि हम मानवता के अभिन्न अंग हैं। तब हम संपूर्ण मानव जाति से अपने गहरे संबंध को महसूस करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारे व समस्त मानवता के भीतर एक ही परम तत्व व्याप्त है। यही अनुभूति हमें आत्मकेंद्रित जीवन से उठाकर मानव-कल्याण के पथ पर ले जाती है और यही सच्ची मुक्ति है।

हर परिस्थिति एक अवसर है

सूत्र

सच्ची मुक्ति अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने में है। अनुभव, संघर्ष और संवेदनशीलता ही व्यक्ति को उसका मार्ग दिखाते हैं। जो हर परिस्थिति को सीख का अवसर मानता है, वही आत्मिक शक्ति विकसित करता है। आत्मकेंद्रित दृष्टि से उठकर मानव-कल्याण के उद्देश्य से जुड़ना ही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि और सच्ची स्वतंत्रता है।

दूसरा पहलू

इतिहास की धुमावदार गलियों में कई बार सवालों के जवाब सीधे-सीधे नहीं मिलते, तुर्की सुल्ताना भी शायद ऐसा ही सवाल है।

भूली-बिसरी राजधानी का वह नायाब नगीना

भूपेंद्र कुमार

फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 से 1585 के बीच किया गया था। यह स्थान पहले सीकरी के नाम से जाना जाता था।

अकबर की सभी इमारतों में यह सबसे सुंदर और समृद्ध है। इतनी अलंकृत इमारत कोई नहीं। अबुल फजल ने लिखा है, छैनी-हथौड़े ने वह कमाल कर दिया, जो लकड़ी पर की गई नक्काशी भी नहीं कर सकती थी।

ऐसा लगता ही नहीं कि यह सदियों पुरानी भूली-बिसरी दास्तां है। एक ऐसी राजधानी, जो बसने के साथ ही उजड़ गई। फतेहपुर सीकरी पत्थरों पर लिखी एक ऐसी रुबाई है, जिसे सुनने के लिए वक्त चाहिए। थोड़ा ठहरकर हवा में गूंजती सरगोशियों को सुनेंगे, तो कही-अनकही दास्तानें महसूस कर पाएंगे। तब आप देख पाएंगे कि पत्थरों पर कितनी नाजुक-सी शायरी लिखी गई है। तो क्या है तुर्की सुल्ताना की दास्तां, जिसे आज भी कोई नहीं जानता? इस वीरान बस्ती की ऐसी कहानी, जो अनकही रह गई। सदियों पहले एक वक्त था, जब अकबर की बनाई राजधानी फतेहपुर सीकरी की इमारतें गुलजार थीं। पहले थोड़ा फतेहपुर सीकरी के बारे में जान लेते हैं। इसका निर्माण 1571 से 1585 के बीच किया गया था। यह स्थान पहले सीकरी के नाम से जाना जाता था, जो सिकरवार राजपूतों से निकला शब्द था। अकबर के दादा बाबर ने यहां एक उद्यान बनाने का निर्देश दिया था। बाद में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जब शहजादे सलीम, यानी जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ, तो अकबर ने यहां पूरा शहर बनवाना तय किया। तब अकबर ने गुजरात में जीत हासिल की थी, तो नई राजधानी को फतेहपुर-सीकरी नाम दिया गया। यहीं तुर्की सुल्ताना का अनोखा महल भी है, जैसे पत्थर पर लिखी कलात्मक कविता हो। इमारत की दीवारों पर लाल पत्थर पर जंगल के ऐसे दृश्य उकेरे गए हैं, जो कागज पर भी उकेरने असंभव से हैं। इतिहासकारों के अनुसार, तुर्की सुल्ताना कोई एक महिला नहीं थी, बल्कि यह अकबर की दो तुर्क बेगमों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था, रुकैया सुल्ताना बेगम और सलीमा सुल्ताना बेगम।

रुकैया अकबर की पहली पत्नी थीं, जो निःसंतान रहीं, जबकि सलीमा पहले बैरम खान की पत्नी थीं और बाद में उन्होंने अकबर से शादी की। पर दो बेगम एक कमरे के आवास में कैसे रह सकती थीं, इसका जवाब कहीं नहीं मिलता। अकबरकालीन इतिहासकार बदायूंनी ने लिखा है कि इस जगह 1571 में मजहबी चर्चा हुआ करती थी। इसे ही आज हम तुर्की सुल्ताना का महल कहते हैं। इसमें केवल एक कमरा है। इतिहासकार फर्ग्यूसन के अनुसार, अकबर की सभी इमारतों में यह सबसे सुंदर और समृद्ध है। इतनी अलंकृत इमारत कोई नहीं। अकबर के नवरत्नों में शुमार अबुल फजल ने लिखा है, छैनी-हथौड़े ने वह कमाल कर दिया, जो लकड़ी पर की गई नक्काशी भी नहीं कर सकती थी। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने अपनी चर्चित पुस्तक *इंडियन आर्किटेक्चर-द इस्लामिक पीरियड* में लिखा है, वास्तुकला का नायाब नगीना। देखा जाए, तो इतिहास की धुमावदार गलियों में कई बार सवालों के जवाब सीधे-सीधे नहीं मिलते, तुर्की सुल्ताना भी शायद ऐसा ही सवाल है।

आंकड़े

डब्ल्यूएचओ का बजट

पिछले कई वर्षों में अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन के बजट में सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा था, पर 2024 में वह खिसकर 7वें स्थान पर आ गया।

गेट्स फाउंडेशन	32.1
ब्रिटेन	26.5
गावी	25.7
जर्मनी	19.8
यूरोपीय आयोग	15.1

आंकड़े डब्ल्यूएचओ को दिए योगदान के, करोड़ डॉलर में | स्रोत : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

श्रीहरि ने तपस्वी दुर्वासा से कहा कि उनका हृदय तो उनके भक्तों में बसता है। फिर महर्षि ने अपनी भूल स्वीकार की। राजा ने चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद मांगा।

प्रभु का हृदय तो भक्तों में बसता है

अंतर्यात्रा
संकलित

चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद राजा अंबरीष का अंतर्मन भौतिक सुखों से निर्लिप्त और पूर्णतः हरिमय था। उनका वास्तविक ध्यान श्रीहरि की अनन्य आराधना में केंद्रित था। एक बार, जब वह एकादशी व्रत का पारण करने ही वाले थे, तभी वहां महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। वह तप व ज्ञान के प्रतीक तो थे, किंतु उनका चित्त अब भी क्रोध और अहंकार से भरा हुआ था। महर्षि ने यमुना स्नान के बाद भोजन ग्रहण करने की इच्छा जताई और स्नान करने चले गए। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त बीत रहा था। ऐसे में, राजपुरोहित के परामर्श पर राजा ने मात्र तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करके व्रत पारण की लाज रखी।

किंतु, जब महर्षि लौटे, तो उनके भीतर के अहंकार ने इसे स्वयं का अपमान समझा। उन्होंने अपनी जटा से 'कृत्या' नामक राक्षसी को जन्म दिया, और उसे राजा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तभी श्रीहरि का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने राक्षसी का वध कर दिया। फिर महर्षि का पीछा करने लगा। महर्षि ने स्वर्ग से लेकर शिवलोक तक गुहार लगाई, किंतु सबने उनकी रक्षा करने में असमर्थता जताई। अंततः वह नारायण की शरण में गए। भगवान ने उन्हें बताया कि उनका हृदय तो उनके भक्तों में बसता है। उन्होंने ऋषि से कहा कि तुमने अहं से अपराध किया है, इसलिए क्षमा वहीं मिलेगी, जहां विनय है। फिर तपस्वी दुर्वासा ने राजा अंबरीष से अपनी भूल स्वीकार की। राजा ने विनम्रता से चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद मांगा।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 4 फरवरी, 1951

हिंदी का बनावटी विकास न हो

हिन्दी का बनावटी विकास न हो
संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी के समर्थकों से कहा कि अगर वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे उस भाषा का द्वार सभी भाषाओं के शब्दों के लिए खुला रखें, ताकि वह वास्तविक राष्ट्रभाषा बन सके।

ताकि युवा किताबों से दूर न रहें

डिजिटल पढ़ाई बच्चों को आत्मकेंद्रित और चिड़चिड़ा बना रही है। भारत इस मामले में स्वीडन व डेनमार्क जैसे देशों से सबक ले सकता है।

क्षमा शर्मा

सबक

कुछ माह पहले स्वीडन ने अपने स्कूलों से कंप्यूटर्स की विदाई कर दी और पंद्रह साल बाद किताबों की वापसी की। वहां के अधिकारियों का कहना था कि सारी पढ़ाई डिजिटल और ऑनलाइन करने से बच्चों ने नया कुछ नहीं सीखा। वे आत्मकेंद्रित हुए। अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलना-कूदना बंद हुआ। दूसरों से मिलने-जुलने से कतराने लगे। उन्हें तरह-तरह के रोगों जैसे पीठ दर्द, सर्वाइकल, आंखों में रोशनी की कमी ने घेर लिया। वे चिड़चिड़े हो उठे।

पिछले अगस्त में खबर आई थी कि डेनमार्क में सरकार इस बात से चिंतित है कि स्क्रीन की इस दुनिया में क्या अब भी लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं। लोगों को किताबों तक वापस लाने के लिए वहां तमाम सामान पर लगाया जाने वाला पच्चीस प्रतिशत टैक्स, जो किताबों पर भी लगाया जाता है, उसे हटा दिया गया। वहां की संस्कृति मंत्री एंजेल स्मिट ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें।

उन्होंने यह भी कहा कि इन दिनों देश में एक तरह की रीडिंग क्राइसिस है। कोई पढ़ना नहीं चाहता। युवा लोग इसके अधिक शिकार हैं। किताबों पर टैक्स हटाने से वे सस्ती होंगी। युवा भी इनकी ओर आकर्षित होंगे। लोग अधिक से अधिक किताबें पढ़ना चाहेंगे। वैसे भी किताबों से अच्छा साथी कोई होता भी नहीं है। सिर्फ डेनमार्क ही नहीं, अमेरिका में भी यही स्थिति देखी जा रही है कि वहां लोग बहुत कम पढ़ते हैं। पढ़ने का कम कारण मोबाइल फोन और तरह-तरह के स्क्रीन टाइम को बताया जा रहा है। स्वीडन ने भी किताबों पर टैक्स कम कर दिया है। भारत में भी किताबों और पत्र-पत्रिकाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगता, लेकिन किताबें जिस कागज पर छपती हैं, उस पर बारह प्रतिशत और छपाई पर अठारह प्रतिशत जीएसटी लगता है। यानी कि कान इधर से नहीं पकड़ा, उधर से पकड़ लिया। महंगी किताबें कैसे कोई खरीदे, और कैसे पढ़े। हमारे देश को भी इस बारे में बहुत सीखने की जरूरत है।

अपने यहां लगातार कहा जा रहा है कि यहां भी पढ़ने की आदतें कम हो रही हैं। क्या बच्चे, क्या युवा, सब ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल पर बिता रहे हैं। हालांकि, हाल ही में दिल्ली में लगे पुस्तक मेले में बीस लाख लोगों की उमड़ी भीड़ ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि लोगों में किताबों के प्रति दिलचस्पी कम हो रही है। अब तक लगे तिरपन पुस्तक मेलों में आने वालों का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। किताबों की बिक्री भी खूब हुई। लेकिन बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि चूंकि इस बार मेले में प्रवेश निःशुल्क था, इसलिए भीड़ ज्यादा थी।

स्वीडन की तरह अब डेनमार्क में भी स्कूलों में किताबें वापस लाई जा रही हैं। सिर्फ किताबें ही नहीं कॉपी और पेन की वापसी भी हो रही है। वहां की सरकार का मानना है कि डिजिटल पढ़ाई से बच्चों की ध्यान केंद्रित होने की क्षमता कम होती जा रही थी। इसलिए उनके लिए कक्षाओं में किताबें, कॉपियां और पेन हों, इसकी जरूरत को महसूस किया गया। कागज के महत्व को दोबारा स्थापित किया जा रहा है। बहुत से स्कूलों ने मोबाइल फोन को बैन कर दिया है। बच्चों का पढ़ाई करते समय स्क्रीनटाइम कम से कम हो, इसकी योजनाएं बनाई जा रही हैं। कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक के आपसी तालमेल को भी रेखांकित किया जा रहा है। जबकि एक जमाने में डेनमार्क को डिजिटल चैंपियन कहा जाता था। वहां 2011 से ही स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन कर दिया गया था। कागज मुक्त समाज की बात की जा रही थी। लेकिन सरकार ने पाया कि इससे बच्चों के सीखने की क्षमता तो कम हो ही रही है, उन्हें तमाम तरह के शारीरिक और मानसिक रोगों ने भी घेर लिया है। वे किसी भी बात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अब वहां माना जा रहा है कि तकनीक का उपयोग ठीक है, लेकिन बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए स्कूलों में तकनीक से दूरी भी जरूरी है। किसी भी चीज की अति, चाहे वह तकनीक ही क्यों न हो, खतरनाक होती ही है।

स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों ने अपने बच्चों के बारे में सोचा और त्वरित निर्णय लिया। लेकिन हमारे यहां तो इन दिनों बहुत से दल अपने-अपने घोषणा पत्रों में इस बात का वादा करते रहते हैं कि वे जल्द से जल्द हर छात्र को लैपटॉप देंगे। मोबाइल देंगे। बच्चों और युवाओं को ये सुविधाएं मिलें, वे इन पर काम करना भी सीखें, लेकिन ये अति नुकसानदेह हैं, इसे हम स्वीडन और डेनमार्क से सीख सकते हैं।

edit@amarujala.com

न्यूज डायरी

शाह कल से जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर

जम्मू/कठुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 से 7 फरवरी तक जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर आ रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के बजट सत्र और किश्तवाड़ व उधमपुर में जारी आतंकरोधी अभियानों के बीच हो रहा यह दौरा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत अहम माना जा रहा है। शाह प्रदेश की सुरक्षा स्थिति पर उच्च उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। संवाद

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई 10 मार्च को

प्रयागराज। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते मंगलवार को सुनवाई टाल दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दिया है। राखी सिंह ने वजूखाने के वैज्ञानिक सर्वे की मांग में पुनरीक्षण अर्जी दायर की है। मस्जिद पक्षकार इसका विरोध कर रहा है। ब्यूरो

छत पर पार्टी...दोस्त को नीचे फेंका, मौत

बरेली। सिरौली थाना के गुरुगांव में शराब दुकान की छत पर बैठकर पार्टी कर रहे दोस्तों में रुपयों के लेनदेन को लेकर झगड़ा हो गया। तीन दोस्तों ने चौथे को छत से नीचे फेंक दिया। उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दो की तलाश की जा रही है। गुरुगांव में देसी और अंग्रेजी शराब की दुकान एक ही जगह है। सोमवार रात शमीम, रशीद व जीशान गांव निवासी विनोद को घर से पार्टी करने की बात कहकर साथ ले गए। संवाद

सांडों के दौड़ाने पर गिरा छात्र डीसीएम से कुचलकर मौत

उन्नाव। बदरका गांव में सड़क पर लड़ रहे सांडों ने भाइयों दीपांशु (17) और गोलू (14) को दौड़ा लिया। दीपांशु सड़क पर गिर गया। तेज गति से आ रही डीसीएम की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वह 10वीं का छात्र था। दीपांशु और गोलू सोमवार शाम बाबा के घर खाना खाने गए थे। रात 10:30 बजे दोनों भाई पिता के साथ घर लौट रहे थे। संवाद

बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट नाराज, पूछा-क्या यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं

हमीरपुर निवासी व दो अन्य ध्वस्तीकरण की आशंका पर पहुंचे तो कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा सवाल

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि क्या 2025 में रोक के बावजूद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं है। क्या यह कार्यपालिका का अपनी मंशा छिपाकर शक्तियों का प्रयोग करने का उदाहरण नहीं है। यह टिप्पणी हमीरपुर निवासी फैमुद्दीन व दो अन्य की याचिका पर की।

फैमुद्दीन के परिवार के आफान खान के खिलाफ सुमेरपुर थाने में 16 जनवरी को आईटी एक्ट, पॉक्सो व धर्मांतरण निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि घटना के बाद भीड़ ने याची के घर को निशाना बनाया, जबकि ये आरोपी नहीं हैं। इसके बाद भी इनको नोटिस दिया गया। साथ ही लॉज और मिल को सील कर दिया गया। ऐसे में याची ने आशंका जताई है कि इनकी संपत्तियों को बुलडोजर से गिराया जा सकता है। इसे लेकर इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

कोर्ट के सवाल

- क्या सुप्रीम कोर्ट के 2025 के आदेश का पालन हो रहा है?
- क्या अपराध के तुरंत बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना सरकार के विवेक का दुरुपयोग नहीं है?
- क्या राज्य का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सार्वजनिक आवश्यकता के अभाव में किसी का घर न गिराए?
- ध्वस्तीकरण की आशंका होने पर क्या कोई नागरिक अदालत जा सकता है?

राज्य सरकार का पक्ष

राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने दलील दी कि याचिका अभी अपरिपक्व है। आवास और लॉज सील नहीं किए गए हैं। मिल से प्रतिबंधित लकड़ी बरामद होने का तथ्य याचियों ने छिपाया है। भरोसा दिलाया कि कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई का अवसर देने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।

कहा-सजा का अधिकार न्यायपालिका के पास

कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे कई मामलों का साक्षी रहा है, जहां अपराध के तुरंत बाद संपत्तियों को निशाना बनाकर औपचारिकताएं पूरी कर ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है। निर्माण को तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2025 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या ध्वस्तीकरण शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन नहीं है। क्योंकि, सजा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। कोर्ट ने चार प्रमुख कानूनी सवाल तय करते हुए पक्षों से नौ फरवरी को जवाब मांगा है। अंतरिम आदेश में पुलिस को याचिकाकर्ताओं के जीवन, अंग और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-न्याय तक पहुंच लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय तक पहुंच लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद है और एक निष्पक्ष एवं न्यायसंगत समाज का आधार है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता कार्यवाही के कुशल संचालन से मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान की प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है।

पीठ ने माना कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29ए(5) के तहत मध्यस्थ के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए आवेदन धारा 29ए(1) और (3) के तहत निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी स्वीकार्य है। अधिनियम की धारा 29ए मध्यस्थता निर्णय की समय सीमा से संबंधित है। पीठ ने एक कानूनी प्रश्न उठाया कि क्या कोई अदालत अधिनियम की धारा 29ए(5) के अंतर्गत मध्यस्थ को निर्णय देने के लिए अधिकृत करने के आवेदन पर विचार कर सकती है। वह भी तब जब निर्णय दिए जाने के बाद 18 माह की वैधानिक समय सीमा समाप्त हो गई हो। मद्रास हाईकोर्ट के जनवरी 2025 के आदेश के विरुद्ध अपील पर अपने निर्णय में पीठ ने कहा, न्याय तक पहुंच लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है, जो एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज का मुख्य आधार है। एजेंसी

धोखाधड़ी मामले में शादी डॉट कॉम के संस्थापक अनुपम मित्तल की गिरफ्तारी पर दो सप्ताह की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शादी डॉट कॉम के संस्थापक अनुपम मित्तल और दो अन्य को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी से दो हफ्ते के लिए बड़ी राहत दे दी। इस वैवाहिक वेबसाइट की एक महिला यूजर ने आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने मित्तल के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को निरस्त करने से इनकार करते हुए मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए हाईकोर्ट के पास वापस भेजा था।

फ्लिपकार्ट के खिलाफ सीसीआई जांच वाला एनसीएलएटी का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के खिलाफ सीसीआई जांच वाला राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का 2020 का आदेश रद्द कर दिया। एनसीएलएटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक को ई-कॉमर्स दिग्गज की ओर से प्रतिस्पर्धा कानून उल्लंघनों की जांच करने का निर्देश दिया था। पीठ ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए एनसीएलएटी को वापस भेज दिया। एनसीएलएटी को फ्लिपकार्ट के इस तर्क को ध्यान में रखते हुए मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए कि न्यायाधिकरण ने आयकर कार्यवाही में एक मूल्यांकन अधिकारी की टिप्पणियों पर भरोसा किया था, जिन्हें बाद में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने रद्द कर दिया था।

रेलवे ने हासिल की गुजरात में अवसंरचना में ऐतिहासिक उपलब्धि

गांधीनगर। रेलवे ने गुजरात में अभूतपूर्व बजटीय सहयोग और अवसंरचना विकास के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इससे राज्य में सुरक्षित, आधुनिक और यात्री-केंद्रित रेल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत हुई है।

आधुनिक स्टेशन और विश्वस्तरीय ट्रेन सेवाओं से बदल रहा रेल परिदृश्य

गुजरात के लिए रेलवे का औसत वार्षिक बजट आवंटन वर्ष 2009–14 के दौरान 589 करोड़ रुपये से वर्ष 2026–27 की अवधि में बढ़कर करीब 29 गुना बढ़कर 17,366 करोड़ रुपये हो गया है। यह राज्य में रेल अवसंरचना और संपर्क सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाती है। वर्तमान में गुजरात में 1,28,748 करोड़ रुपये की रेल रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें नई रेल लाइनों के निर्माण, स्टेशन पुनर्विकास तथा सुरक्षा को उन्नत करना शामिल हैं। 2014 के बाद से गुजरात के रेल नेटवर्क में तीव्र विस्तार हुआ है। लगभग 2,900 किमी नई रेल लाइनों का निर्माण किया गया है, जो कई यूरोपीय देशों के कुल रेल नेटवर्क से भी अधिक है।

राज्य ने 4,005 किमी रेल लाइनों के विद्युतीकरण के साथ 100 फीसदी विद्युतीकरण का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। इससे हरित और ऊर्जा-कुशल संचालन को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त, समपार फाटकों को समाप्त करने हेतु 1,177 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे सुरक्षा बढ़ी है और सड़क-रेल यातायात सुगम हुआ है। एजेंसी

असम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रखा 100 सीटें जीतने का लक्ष्य

पीएम मोदी 14 को तो 21 को गृह मंत्री शाह करेंगे असम का दौरा

गुवाहाटी। भाजपा ने असम में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा लक्ष्य तय किया है। पार्टी ने राज्य में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो उसकी आक्रामक और संगठित चुनावी रणनीति की ओर इशारा करता है। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को गुवाहाटी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे असम के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं के विशाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में करीब एक लाख बूथ कार्यकर्ताओं की भागीदारी प्रस्तावित है।

इसके अलावा, गृह मंत्री अमित शाह 21 फरवरी को असम पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वे महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि यह दौरा भाजपा के चुनावी अभियान को और धार देगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लगातार दौरे से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा होगा और उन्हें स्पष्ट रणनीतिक दिशा मिलेगी। भाजपा विकास, सुशासन और मजबूत संगठनात्मक विस्तार को अपने प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रखने की तैयारी में है। मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस से माना जा रहा है। ब्यूरो

सात देशों की यात्रा के बाद धर्मशाला पहुंचा था चीनी नागरिक, अब एजेंसियां खंगालेंगी कुंडली

धर्मशाला। मैक्लोडगंज में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा बढ़ गया है। मंगलवार को धर्मशाला न्यायालय ने आरोपी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी है। बीते दिन ही पूछताछ में स्पष्ट हो गया था कि आरोपी चीनी पुलिस सेवा में रह चुका है। मंगलवार को पूछताछ में पता चला है कि चीनी नागरिक भारत आने से पहले मलयेशिया, इंडोनेशिया, अजरबैजान, तुर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र की यात्रा कर चुका है। कई देशों की यात्रा करने के बाद उसने भारत में प्रवेश के लिए नेपाल सीमा का सहारा लिया। एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि क्या इन देशों की यात्रा के पीछे कोई कॉमन पैटर्न है या फिर कुछ और। यानी अब यह मामला केवल अवैध प्रवास तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब इसमें जासूसी और स्थानीय लापरवाही के एंगल से भी जांच की जा रही है। संवाद

यूजीसी नियमों पर सुनील आंबेकर बोले-संघ समाज में एकता के पक्ष में

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी नियमावली पर रोक लगाने के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के वरिष्ठ नेता सुनील आंबेकर ने मंगलवार को कहा कि संघ समाज में एकता के पक्ष में है। इसे बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह करेगा।

केंद्र की तरफ से अधिसूचित नए नियम के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को भेदभाव के मामलों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए समता समितियां गठित करनी थीं। शीर्ष कोर्ट ने यह कहते हुए इस पर रोक लगा दी थी कि ढांचा प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है और अंततः यह समाज को विभाजित कर सकता है, जिसके खतरनाक प्रभाव होंगे। स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस के योगदान पर सवाल उठाने वालों की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संघ को 100 साल बाद यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसने देश की संप्रभुता और एकता को बनाए रखने के लिए क्या किया है। एजेंसी

भाषा थोपना कभी स्वीकार नहीं करेंगे तमिल लोग : जस्टिस आनंद

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि एक तमिल नागरिक भले ही स्वेच्छा से अन्य भाषाएं सीख रहा हो और दूसरी भाषाओं का विरोध न करता हो लेकिन अपने ऊपर कोई भाषा थोपे जाने को कभी स्वीकार नहीं करेगा।

जस्टिस एन आनंद वेंकटेश

चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा, मैंने हाल ही में अपने बेटे के साथ तमिल फिल्म पराशक्ति देखी, जिसमें 1960 के दशक के हिंदी विरोधी आंदोलन को दर्शाया गया है। फिल्म देखने के बाद मैंने बेटे से पूछा कि क्या वह भाषा संघर्ष के बारे में जानता है। जब उसने बताया कि उसे इसकी जानकारी नहीं है, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं अपने कर्तव्य में विफल रहा। उन्होंने कुछ दिन पहले यहां कानून के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, यह इतिहास सभी को पता होना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसा कि वरिष्ठ अधिवक्ता एनआर एलंगो ने कहा, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी जाने बिना तमिलनाडु से बाहर निकलना मुश्किल है। एक तमिल भाषी अन्य भाषाओं का विरोध नहीं करता, बल्कि अपनी इच्छा से अन्य भाषाएं सीखता भी है। हालांकि, मेरी भाषा (तमिल) की प्राचीनता और उससे जुड़े मेरे गौरव को देखते हुए, यदि कोई मुझ पर कोई भाषा थोपता है, तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, गर्व से कहो कि मैं एक तमिल भाषी हूं, और जब भाषा का अपमान हो, तो आवाज उठानी चाहिए, और हर हाल में भाषा की रक्षा करना और उसे कभी न भूलना हमारा कर्तव्य है। एजेंसी

दिल्ली-एनसीआर

रवि काना की रिहाई के मामले में जेल अधीक्षक समेत कई पर प्राथमिकी दर्ज

जांच के लिए गठित विशेष टीम ने मंडल कारागार से महत्वपूर्ण रिकॉर्ड खंगाले

संवाद न्यूज एजेंसी

बांदा। कुख्यात स्क्रैप माफिया व गैंगस्टर रविंद्र सिंह उर्फ रवि काना की बांदा मंडल कारागार से रहस्यमय हालात में रिहाई के मामले में जेल अधीक्षक, जेलर और अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 260 सी के तहत कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की है।

घटना तब सामने आई जब वसूली से जुड़े एक मामले में बी-वारंट पर तलब किए गए रवि काना की 29 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। बाद में उसी दिन शाम को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर ने मामले में जवाब तलब किया था।

रवि काना।

डीजी जेल की जांच के बाद जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया था। मंगलवार को गठित विशेष टीम ने मंडल कारागार का दौरा कर गैंगस्टर की रिहाई से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, जेल के अंदर लगे कैमरों की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड खंगाले। जांच के दौरान टीम ने जेल अधीक्षक अनिल गौतम सहित 10 जेल कर्मियों और नौ बंदियों से पूछताछ की।

जेल प्रशासन पर कार्रवाई और नई नियुक्ति

भारतीय न्याय संहिता की धारा 260 सी के तहत लोक सेवक द्वारा जानबूझकर गिरफ्तारी में चूक करना दंडनीय अपराध है। इसी धारा के तहत जेल चौकी प्रभारी अनुराग पांडेय की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, जेलर के निलंबन के एक सप्ताह के भीतर, प्रयागराज जोन से नए जेलर आलोक कुमार की तैनाती जिला कारागार में कर दी गई है। पुलिस जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में रवि काना को रिहा किया गया था।

जेल चौकी प्रभारी की तहरीर पर अपराधी रवि काना की रिहाई के संबंध में जेल अधीक्षक, जेलर और अन्य के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम जांच कर बताएगी कि किन परिस्थितियों में अभियुक्त को रिहा किया गया। – **पलाश बंसल, पुलिस अधीक्षक**

विदेशी छात्र के शव को अंतिम यात्रा के लिए एनओसी का इंतजार

ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पैरामाउंट गोल्फ जीटा-1 में रहने वाले नाइजीरियाई छात्र एमा डल्ला (41) की इलाज के दौरान मौत हो गई। एंबेसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न मिलने के कारण आठ दिन बाद भी उसका पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका है। आवश्यक प्रपत्र पूरे होने के बाद मंगलवार को थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

पुलिस के अनुसार, एमा डल्ला मूलरूप से नाइजीरिया के निवासी थे। वर्तमान में पैरामाउंट गोल्फ जीटा-1 में रह रहे थे। 20 जनवरी 2026 को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दिमागी दौरा (ब्रेन स्ट्रोक) पड़ा। जिसके बाद उनके दोस्तों द्वारा उन्हें तत्काल उपचार के लिए नॉलेज पार्क स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान हालत गंभीर बनी रही और 25 जनवरी को उपचार के दौरान एमा डल्ला की मृत्यु हो गई। चूंकि मृतक विदेशी नागरिक थे। इसलिए शव को उनके देश भेजने और अंतिम क्रिया-कर्म से पूर्व संबंधित देश की एंबेसी से एनओसी लिया जाना आवश्यक था। लेकिन मृतक के दोस्तों और परिजनों द्वारा एंबेसी में समय से आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कराए जा सके। जिसके चलते एंबेसी द्वारा एनओसी जारी नहीं की गई। एनओसी न मिलने के कारण पुलिस भी नियमानुसार पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकी। इस बीच शव अस्पताल में सुरक्षित रखा गया। बाद में मृतक के परिजनों द्वारा आवश्यक प्रपत्र पूरे कर एंबेसी में जमा किए गए। इसके बाद एंबेसी की ओर से एनओसी मिलने पर मंगलवार को नॉलेज पार्क पुलिस कोतवाली ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। ब्यूरो

दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण को मिली स्वीकृति, जल्द शुरू होगा काम

परियोजना पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान

अनिल त्यागी

बीते दिनों रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव ने की थी इसकी घोषणा

गाजियाबाद। दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण का काम मार्च में शुरू होने की उम्मीद है। बजट की स्वीकृति मिलने के बाद विभागीय स्तर पर इसकी कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई तेज हो गई है। दोहरे ट्रैक और विद्युतीकरण पर एक हजार करोड़ से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है।

दिल्ली-शाहदरा-लोनी-शामली-टपरी (सहारनपुर) रेल मार्ग 175 किलोमीटर लंबा है। इस रूट से एक एक्सप्रेस व 28 पैसेंजर ट्रेन गुजरती हैं। इस मार्ग के दोहरीकरण को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही थी। बीते दिनों रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसके दोहरीकरण की घोषणा की थी।

इसके बाद अक्टूबर 2025 में इसका सर्वे शुरू हुआ। दिसंबर के शुरू में डीपीआर बनाकर मुख्यालय को भेजी गई। अब केंद्र सरकार ने बजट जारी किया तो इस परियोजना के साकार होने का रास्ता भी साफ हो गया है।

योजना है कि पहले चरण में दिल्ली से शामली और दूसरे चरण में शामली से टपरी तक का काम पूरा कराया जाएगा। इसको तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। काम पूरा होने के बाद पैसेंजर के अलावा इस रूट से लंबी दूरी की कई ट्रेनों के गुजरने का रास्ता भी साफ होगा।

इस बारे में नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि तय समय सीमा में कार्य पूरा कराने को लेकर आधिकारिक स्तर पर मंथन किया जा रहा है। कार्य के दौरान लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

बड़ी आबादी को मिलेगा फायदा

योजना पर काम पूरा होने के बाद जिले के लोनी समेत आसपास की 50 हजार से अधिक आबादी को फायदा मिलेगा। इस रूट पर एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन होने पर लोनी, साहिबाबाद क्षेत्र की बड़ी आबादी को गाजियाबाद का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी। ट्रैक बढ़ने पर लोकल ट्रेनों के समय से चलने का रास्ता खुलेगा। इससे ड्यूटी और शिक्षण कार्य में लगे छात्रों को बड़ा फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, बागपत, खेकड़ा, सहारनपुर, बड़ौत, शामली के लाखों की आबादी को भी इससे बड़ा लाभ होगा।

व्यावसायिक गतिविधि

लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए सेल और राइट्स के बीच समझौता

नई दिल्ली (वि)। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने संयंत्रों और खानों में लॉजिस्टिक्स एवं परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राइट्स लिमिटेड (राइट्स) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सेल अपने संयंत्रों और खदानों में कच्चे माल की आवक, इन-प्रोसेस ट्रांसफर तथा तैयार उत्पादों के निर्बाध परिवहन के लिए समर्पित 'मिनी रेल नेटवर्क' का संचालन करता है। एमओयू के तहत डीजल लोकोमोटिव बेड़े के प्रभावी संचालन, रखरखाव और भविष्य की क्षमता विस्तार योजनाओं में राइट्स की विशेषज्ञ सेवाएं ली जाएंगी। एमओयू पर सेल की ओर से कार्यपालक निदेशक (प्रचालन) पीके बैसाखिया और राइट्स की ओर से कार्यपालक निदेशक (तकनीकी सेवाएं) संदीप जैन ने हस्ताक्षर किए।

रजत शर्मा मानहानि मामला : जयराम रमेश और रागिनी नायक को समन

छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो पोस्ट कर रजत पर लगाया था रागिनी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए वीडियो क्लिप के प्रसार के संबंध में वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टीवी के प्रधान संपादक रजत शर्मा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि और जालसाजी की शिकायत में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को तलब किया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवंशी जनमेजा ने कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 465 (जालसाजी), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कपटपूर्ण या बेईमानी से उपयोग), 499 (आपराधिक मानहानि) और 500 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। तीनों को 27 जुलाई, 2026 को तलब करने का निर्देश दिया।

अदालत ने 2 फरवरी को अपने आदेश में कहा, शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया यह साबित कर दिया है कि आरोपियों ने ऐसी खबरें प्रकाशित की हैं जिनमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने कांग्रेस की महिला प्रवक्ता रागिनी नायक के खिलाफ आपत्तिजनक अपशब्द कहे हैं। अदालत ने कहा, इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि शिकायतकर्ता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणियों और पोस्टों के माध्यम से अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। शर्मा ने आरोप लगाया कि खेरा और रमेश ने यह जानते हुए भी कि वीडियो फर्जी है, उसे दोबारा पोस्ट कर दिया। एजेंसी

अदालत ने पाया, वीडियो बाद में किया गया संपादित

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया कि वीडियो बाद में संपादित किया गया था। अदालत ने आगे कहा, शिकायतकर्ता ने यह भी पर्याप्त रूप से साबित कर दिया है कि आरोपी व्यक्तियों ने 4 जून, 2024 को प्रसारित टीवी शो का फुटेज प्राप्त किया था और उस पर अपशब्दों को कैप्शन के रूप में चिपका दिया था, साथ ही एक व्याख्यात्मक पाठ के माध्यम से यह भी बताया था कि ये शब्द शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ कहे थे।

जिला रजिस्ट्रार सचिन यादव निलंबित

फरीदाबाद। सोसाइटी और आरडब्ल्यूए से जुड़े मामलों में शिकायतें मिलने के बीच जिला रजिस्ट्रार सचिन यादव को निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमित अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई को एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय के सहायक राजीव गुप्ता की रिश्वत लेते हुए 9 दिसंबर 2025 को गिरफ्तारी के बाद की गई जांच के आधार पर होने की चर्चा है। सोसाइटी पंजीकरण, चुनाव विवाद और शिकायत निपटान में ढिलाई और अनियमितताओं की बात सामने आई। इसी आधार पर सरकार ने तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रार के निलंबन का फैसला लिया। ब्यूरो

निवाड़ी एसएचओ 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

मोदीनगर (गाजियाबाद)। निवाड़ी थाने के प्रभारी (एसएचओ) निरीक्षक जयपाल सिंह रावत को विजिलेंस मेरठ की टीम ने 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निरीक्षक पर गांव अबूपुर के पूर्व प्रधान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर फाड़ने के मुकदमे में नाम हटाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।

विजिलेंस मेरठ सेक्टर के उपाधीक्षक आजाद सिंह केसरी ने बताया कि गांव अबूपुर के पूर्व प्रधान राकेश कुमार उर्फ बिट्टू ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। उनका कहना था कि घटना के समय बैंक में मौजूद थे। इसका साक्ष्य देने के बावजूद निरीक्षक रिश्वत नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी दे रहा था। शिकायतकर्ता ने निरीक्षक के खिलाफ साक्ष्य भी उपलब्ध कराए थे। इस आधार पर विजिलेंस अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह के निर्देश के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए 15 सदस्यीय टीम गठित की गई थी। मंगलवार सुबह विजिलेंस की टीम निवाड़ी थाने पहुंची। यहां पूर्व प्रधान को रसायन लगे नोटों की गड्डी सौंपी गई। इसके बाद टीम के कुछ सदस्य मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने के बहाने थाने में दाखिल हुए। कुछ सदस्य स्वास्थ्य विभाग के वाहन से पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के बहाने पहुंचे। वहां जैसे ही उन्होंने रसायन लगी नोटों की गड्डी निरीक्षक को सौंपी, वैसे ही विजिलेंस टीम ने उसे पकड़ लिया। संवाद

सुप्रीम सवाल-एफआईआर में उचित धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं

नोएडा में घृणा अपराध का शिकार हुए बुजुर्ग की याचिका पर यूपी सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि 2021 में नोएडा के घृणा अपराध मामले में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की उचित धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने शीर्ष अदालत को बताया कि उन्होंने संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पूछा, क्या इससे उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज न होने की समस्या का समाधान हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2021 में नोएडा के घृणा अपराध में दुर्व्यवहार और यातना का शिकार हुए एक वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर निष्पक्ष जांच और सुनवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता के वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि धारा 153-बी और 295-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। धारा 153-बी

राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों और बयानों से संबंधित है, जबकि धारा 295-ए किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है। इसमें उनके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना शामिल है। अहमदी ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलने के अपराध से जुड़ी आईपीसी की धारा 298 का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और यह राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है। इस पर पीठ ने कहा, आइए इसे वह रंग न दें। यह एक व्यक्तिगत घटना है जिसके लिए आप इस अदालत में आए हैं। ब्यूरो

एजुकेशन & कॅरिअर

सच्ची जीत किसी और के हारने में नहीं, खुद के बेहतर बनने में है।

अमर उजाला **Job Alert**

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

इंडिया पोस्ट में निकली भर्ती

ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर रिक्तियां

28635 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 14 फरवरी, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष
यहां आवेदन करें : indiapost.gov.in

बीटीएसटी में आवेदन आमंत्रित ■ 191 पद

पंप ऑपरेटर के पदों पर योग्य उम्मीदवार करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि
08 फरवरी, 2026
योग्यताएं
दसवीं, आईटीआई व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
btsc.bihar.gov.in

एम्स, पटना में संभावनाएं ■ 43 पद

जूनियर रेजिडेंट के पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि
20 फरवरी, 2026
योग्यताएं
एमबीबीएस डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
aiimspatna.edu.in

बैंक ऑफ बड़ौदा में करें आवेदन ■ 418 पद

सीनियर मैनेजर, मैनेजर व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 19 फरवरी, 2026
पात्रताएं : ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : bankofbaroda.bank.in

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में मौके ■ 21 पद

वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि
27 फरवरी, 2026
पात्रताएं
एमबीबीएस, एमडी व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें
recruit.barc.gov.in

सी-डॉट में रोजगार के अवसर ■ 10 पद

साइंटिस्ट के पदों पर योग्य उम्मीदवार करें अप्लाई
आवेदन की अंतिम तिथि
16 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें
cdot.in

यहां भी रोजगार के अवसर...

- अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान, दिल्ली : परियोजना तकनीकी सहायक-II का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 18 फरवरी, 2026
- aiims.edu
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग : डाटा और एनालिटिक्स लीड व यूआई/यूएक्स लीड के पदों पर रिक्तियां।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 20 फरवरी, 2026
- negd.gov.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

दूसरों की गलतियों से सीख लें

दूसरों की गलतियों पर खुश न हों, बल्कि उनसे सीख लेकर अपनी समझ और क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान दें

कुमार बिस्वास
लेक्चरर, वोलॉन्गॉन्ग यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया

कार्यस्थल पर कभी-कभी हम मन ही मन किसी सहकर्मी के साथ कुछ गलत होने पर खुशी महसूस कर लेते हैं। भले ही हम इसे खुले तौर पर स्वीकार न करें, लेकिन यह भावना अनजाने में कई लोगों के भीतर पैदा हो सकती है। दूसरों की परेशानियों से प्रसन्न होने की इस आम मानवीय भावना को जर्मन भाषा में 'शाडेनफ्रायड' कहा जाता है। प्रतिस्पर्धी कामकाजी माहौल ऐसी भावनाओं को और अधिक प्रबल बना सकता है। हालांकि इस भावना को अपने आप में बुरा मानना जरूरी नहीं, लेकिन इसे अनैतिक व्यवहार में बदलने से रोकना बेहद जरूरी है। शोध बताते हैं कि सही समझ और आत्म-नियंत्रण के जरिये इस भावना को संतुलित किया जा सकता है।

■ भावना को पहचानें

यह वह भावना है जब आप किसी और की परेशानी को देखकर अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। हम अनजाने में खुद को किसी और से तुलना करके ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। बजाय इसके अगर संभव हो तो सहयोग करें और मदद का हाथ बढ़ाएं। इससे नकारात्मक भावना कम होती है।

■ चिंतन करें

जब ऐसी भावना आए, तो थोड़ा रुककर खुद से ईमानदारी से पूछें कि क्या मैं सच में ऐसा महसूस करना चाहता हूं? क्या कभी ऐसी ही स्थिति मेरे साथ भी हो सकती है? और क्या मैं इस असफलता से कुछ सीख सकता हूं? जब आप खुद को उनकी जगह रखकर देखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक गलती करने वाला व्यक्ति समझने के बजाय इन्सान के रूप में समझ पाते हैं, और यही सोच इस तरह की नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद करती है।

■ नकारात्मकता से बचें

जब किसी और की असफलता देखकर मन में नकारात्मक या खुशी महसूस हो, तो यह बहुत जरूरी है कि वह भावना आपके व्यवहार में न दिखे। इस भावना के कारण गपशप करना, किसी सहकर्मी की छवि खराब करना या जानबूझकर सहयोग न देना कार्यस्थल के लिए बेहद हानिकारक होता है। ऐसे व्यवहार से टीम में सहयोग की भावना कमजोर पड़ती है और एक नकारात्मक कार्यसंस्कृति बनती है, जहां लोग एक-दूसरे का साथ देने के बजाय गिराने की सोचने लगते हैं। इसलिए भावनाओं को पहचानना ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसे कामों में बदलने से बचना जरूरी है, जो संगठन और रिश्तों दोनों को नुकसान पहुंचाएं।

■ आत्म-सुधार में लगें

किसी सहकर्मी की असफलता पर ध्यान देने के बजाय, इस मौके को खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। सोचें कि आप अपने काम, कौशल और सोच को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा सीखने, मेहनत करने और अपने पेशेवर विकास में लगाते हैं, तो दूसरों की तुलना अपने आप कम हो जाती है और आप अधिक सकारात्मक व आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। -द कन्वर्सेशन

आवेदन आमंत्रित

टीएसएल अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रतियोगिता-2026

टीएसएल अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रतियोगिता-2026 के लिए दुनिया भर के 7 से 18 वर्ष के सभी छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता का थीम सस्टेनेबिलिटी कल्चर है। इसका उद्देश्य युवाओं को इस विषय पर अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक मंच प्रदान करना है, जिससे उनमें सक्रियता और सशक्तीकरण की भावना विकसित हो। छात्र अपनी रचनात्मकता को कलाकृति, संगीत, वीडियो, कविता, निबंध, पत्र, कहानी आदि किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिभागी थीम पर आधारित एक से अधिक कार्य भी सबमिट कर सकते हैं। वीडियो या ऑडियो का अधिकतम समय 3 मिनट और लिखित कार्य अधिकतम 600 शब्दों का होना चाहिए। इस प्रतियोगिता में ओवरऑल ग्रैंड प्राइज विजेता को ट्रॉफी और 1,000 पाउंड का नकद पुरस्कार मिलेगा, जबकि उनके स्कूल को 500 पाउंड दिए जाएंगे। रनर-अप को ट्रॉफी और 500 पाउंड का नकद पुरस्कार मिलेगा और उनके स्कूल को 250 पाउंड दिए जाएंगे। कैश प्राइज स्थानीय मुद्रा में प्रदान किए जाएंगे। प्रतिभागी आधिकारिक लिंक tinyurl.com/mr3cbzad पर जाकर 01 मार्च, 2026 तक भाग ले सकते हैं।

फेलोशिप प्रोग्राम

डॉन राइजिंग फेलोशिप-2026

डॉन फेमिनिस्ट द्वारा डॉन राइजिंग फेलोशिप-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह फेलोशिप 40 वर्ष से कम आयु की महिला नारीवादियों के लिए है। यह फेलोशिप पोस्ट-डॉक्टोरल महिला शोधकर्ताओं को अपनी रुचि व विशेषज्ञता के क्षेत्र में कौशल निखारने का अवसर देती है। चयनितों को दस महीनों के लिए प्रतिमाह 1,200 अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे। आवेदकों से नारीवादी सिद्धांतों और कार्यप्रणालियों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जाएगी। महिला शोधार्थियों का चयन पात्रता मानदंडों की पूर्ति, शोध रुचियों और अनुभव के आधार पर किया जाता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 01 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है। योग्य आवेदक अपनी अर्हता की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक tinyurl.com/52e33ax5 पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से इस फेलोशिप प्रोग्राम में आवेदन कर सकते हैं।

इंटर्नशिप अलर्ट

फिलिप्स का समर इंटर्नशिप-2026

फिलिप्स समर इंटर्नशिप प्रोग्राम-2026 के लिए छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए आवेदक का हाई स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज या व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में नामांकित होना आवश्यक है। इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को फिलिप्स के मेड-टेक उत्पादों के विभागीय संचालन में विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करने, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने, उत्कृष्ट पारस्परिक और संचार कौशल दिखाने और समर्पित विभाग की दैनिक गतिविधियों में सहायता करने का अवसर मिलेगा। इसमें आमतौर पर रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक कार्य शामिल होते हैं, ताकि गतिशील वातावरण में काम करते हुए निरंतर सुधार के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। आवेदक आधिकारिक लिंक tinyurl.com/mr3e45m8 पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में आवेदन कर सकते हैं।

खुद को परखें

1. जापोटेक सभ्यता मुख्य रूप से किस देश में फली-फूली?
   (a) मेक्सिको
   (b) न्यूजीलैंड
   (c) भारत
   (d) मलयेशिया
2. हाल ही में, भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य में अग्नि परीक्षा अभ्यास किया?
   (a) असम
   (b) मणिपुर
   (c) नगालैंड
   (d) अरुणाचल प्रदेश
3. छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन-2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है?
   (a) नई दिल्ली
   (b) हैदराबाद
   (c) मुंबई
   (d) बंगलूरू

उत्तर : 1.a, 2.d, 3.c

सामान्य ज्ञान

ओएएल पॉलिसी

■ क्या है

ओएएलपी भारत सरकार की नीति है, जिसमें तेल-गैस कंपनियां अपनी पसंद के क्षेत्र में खोज और उत्पादन के लिए लाइसेंस ले सकती हैं।

■ चर्चा में क्यों

ऑयल इंडिया ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) के नौवें चरण के दौरान आवंटित ब्लॉकों का भूकंपीय अध्ययन कराया।

■ एचईएलपी के तहत लागू

ओएएलपी को 30 मार्च, 2016 को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के तहत लागू किया, जिसने पुरानी एनईएलपी व्यवस्था की जगह ली।

■ उद्देश्य

इसका उद्देश्य तेल व गैस की खोज को बढ़ावा देना, कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना और देश में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है।

■ इसमें डाटा कहां से मिलता है?

सरकार ने नेशनल डाटा रिपॉजिटरी बनाई है, जिसमें भूकंपीय, भूवैज्ञानिक और तकनीकी डाटा उपलब्ध होता है, जिससे कंपनियां तेल-गैस की संभावनाओं का अनुमान लगा सकती हैं।

टेक•टॉक

Gadgets Ai Technology

एआई को चाहिए छोटी चिप

वैज्ञानिकों ने ऐसे कृत्रिम न्यूरॉन विकसित किए हैं, जो 'ब्रेन-इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग' की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह छोटी चिप कम ऊर्जा खपत करने के साथ अधिक कुशल और भरोसेमंद हो सकते हैं।

पिछले कुछ दशकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने तेज गति से विकास किया है। आज एआई का उपयोग तस्वीरों और वीडियो की पहचान, आवाज को टेक्स्ट में बदलने, भाषा अनुवाद, मेडिकल डायग्नोसिस और चैटबॉट जैसे उन्नत संवादात्मक सिस्टमों में व्यापक रूप से हो रहा है। इतनी उन्नत क्षमताओं के बावजूद मौजूदा एआई सिस्टम अत्यधिक ऊर्जा खपत जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। बड़े डेटा सेंटर और शक्तिशाली प्रोसेसर भारी मात्रा में बिजली खर्च करते हैं, जिससे लागत और पर्यावरणीय प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं।

इसी समस्या के समाधान की दिशा में हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटीएच ज्यूरिख और यूनिवर्सिटी डी बौर्गोइन यूरोप के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने 'रोशनी उत्सर्जित करने वाले ऐसे कृत्रिम न्यूरॉन' विकसित किए हैं, जो पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तुलना में अधिक ऊर्जा-कुशल और भरोसेमंद हो सकते हैं।

■ क्या हैं ये कृत्रिम न्यूरॉन?

ये नए कृत्रिम न्यूरॉन 'मेमरिस्टर' नामक नैनो-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आधारित हैं। मेमरिस्टर की खासियत यह है कि यह पहले बह चुके विद्युत प्रवाह को याद रख सकता है और उसी के अनुसार अपना प्रतिरोध बदलता है। यह व्यवहार काफी हद तक मानव मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं जैसा है, जो अनुभव के आधार पर सीखती और प्रतिक्रिया देती हैं। जब इन कृत्रिम न्यूरॉन्स को पर्याप्त विद्युत संकेत मिलते हैं, तो वे रोशनी की सूक्ष्म पल्स उत्सर्जित करते हैं। यही प्रकाश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जानकारी पहुंचाने का माध्यम बनता है।

■ तारों के बिना संवाद

इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पारंपरिक तारों और भारी सर्किट की आवश्यकता नहीं होती। रोशनी के माध्यम से डेटा ट्रांसफर होने के कारण ये न्यूरॉन फोटोनिक कनेक्शन के जरिये आपस में जुड़े रहते हैं। इससे वैज्ञानिक अत्यंत घने और त्रि-आयामी (3डी) न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं, जो कम स्थान घेरते हैं और तेजी से काम करते हैं-जो मौजूदा सिलिकॉन-आधारित तकनीक में मुश्किल है।

■ प्रयोगों में शानदार प्रदर्शन

प्रयोगों में शोधकर्ताओं ने इन कृत्रिम न्यूरॉन्स से बने दो 3डी न्यूरल नेटवर्क को स्पीच क्लासिफिकेशन और हस्तलिखित अंकों की पहचान जैसे कार्यों पर परखा। परिणाम प्रभावशाली रहे-स्पीच क्लासिफिकेशन में 91.5 प्रतिशत और अंकों की पहचान में 92.27 प्रतिशत सटीकता प्राप्त हुई।

■ एआई तकनीक की नींव

विशेषज्ञों का मानना है कि ये रोशनी-आधारित कृत्रिम न्यूरॉन भविष्य के एआई हार्डवेयर की नींव रख सकते हैं। ये कम ऊर्जा खपत करेंगे, अधिक तेज और भरोसेमंद होंगे तथा मोबाइल डिवाइस, रोबोटिक्स और एज कंप्यूटिंग में आसानी से उपयोग किए जा सकेंगे। यह खोज 'ब्रेन-इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग' की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जो आने वाले वर्षों में एआई तकनीक को अधिक टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल बना सकती है। यह शोध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रकाशित हुआ है।

क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट से खुद को हटा सकेंगे

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम जल्द ही एक नया फीचर 'क्लोज फ्रेंड्स' लाने की तैयारी कर रहा है। इसके माध्यम से आप खुद को किसी दूसरे यूजर की क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट से हटा सकेंगे। फिलहाल यह फीचर शुरुआती स्टेज में है और आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। 'क्लोज फ्रेंड्स' फीचर आपको यह सुविधा देता है कि आप अपनी स्टोरीज या रील्स दूसरे अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। अभी अगर कोई आपको अपनी क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में जोड़ता है तो आपके पास खुद को हटाने का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन नए अपडेट के बाद आप खुद ही उस लिस्ट से बाहर निकल सकेंगे। ऐसा करने पर उस यूजर की प्राइवेट स्टोरीज और रील्स आपको तब तक दिखाई नहीं देंगी, जब तक वह दोबारा आपको क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में न जोड़े। हालांकि स्नैपचैट पर यह फीचर पहले से ही है।

व्हाट्सएप चलाने के लिए देने होंगे पैसे

इन दिनों सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि व्हाट्सएप अब फ्री नहीं रहेगा और इस चलाने के लिए पैसे देने होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, व्हाट्सएप एक 'पेड सब्सक्रिप्शन' लाने की तैयारी कर रहा है, जो कि पूरी तरह ऑप्शनल होगा। नॉर्मल व्हाट्सएप पहले की तरह ही मुफ्त रहेगा, लेकिन अगर आप कुछ खास और नए फीचर्स चाहते हैं, तो आप इस प्रीमियम प्लान को चुन सकते हैं। कंपनी इसे अभी बीटा वर्जन पर टेस्ट कर रही है। व्हाट्सएप के इस नए पेड वर्जन में यूजर्स को कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे, जो आम यूजर्स के पास नहीं होंगे।

आने वाला है

नए अवतार में दिखेगा सैमसंग का एफ 70

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता कंपनी सैमसंग इसी महीने अपनी नई किफायती स्मार्टफोन एफ70 सीरीज लॉन्च कर सकती है। ये नई F70 सीरीज उन यूजर्स को टारगेट करेगी, जो ज्यादा पैसे खर्च किए बिना अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस चाहते हैं। सैमसंग गैलेक्सी F70 सीरीज पहले से मौजूद F सीरीज में एक अपग्रेड है। कंपनी के अनुसार, एफ 70 लाइनअप अच्छे कैमरा हार्डवेयर के साथ आएगा। सैमसंग का कहना है कि ये डिवाइस कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करेंगे यानी ये फोन उन यूजर्स के लिए होंगे, जो सोशल मीडिया पर अपने खास पल शेयर करते हैं। 5,000 एमएएच की बैटरी से लैस हो सकता है। कंपनी ने अभी तक डिवाइस के किसी फीचर का खुलासा नहीं किया है।

आने वाली है

ब्रिक्सटन की क्रॉसफायर 500 स्टॉर

अगर आप एडवेंचर बाइक के शौकीन हैं तो ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल अपनी नई एडवेंचर बाइक, क्रॉसफायर 500 स्टॉर, इसी महीने लॉन्च कर सकती है। इस गाड़ी की कीमत लगभग 6 लाख रुपये होने का अनुमान है। यह 486 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन वाली बाइक है, जो 47 बीएचपी की शक्ति और 43एनएम का टार्क उत्पन्न करेगा। इस बाइक में 7-इंच का टीएफटी डिस्प्ले, रैली टायर्स, ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स और बेहतर सफर के लिए 16-लीटर का फ्यूल टैंक है। इसका मुकाबला होंडा एनएक्स500, बेनेली टीआरके 502 और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 से होगा।

आज का दिन

4 फरवरी, 1932

संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूयॉर्क के लेक प्लासिड गांव में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। यह यूरोप के बाहर आयोजित होने वाले पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल थे।

- 1921 : अमेरिकी लेखिका बेट्टी फ्राइडन का जन्म हुआ था।
- 1948 : सीलोन को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।
- 2003 : यूगोस्लाविया ने अपना नाम बदलकर सर्बिया और मोंटेनेग्रो कर लिया था।
- 2004 : मार्क जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया साइट 'द फेसबुक' लॉन्च किया था।

व्रत त्योहार

आज : फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया।
कल : चतुर्थी व्रत, शिशिर ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले।
राहुकाल : दिन में 13.30 से 15.00 तक।

■ सूर्योदय : 07.11
■ सूर्यास्त : 17.59
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 16 माघ मास शक 1947, माघ मास 23 प्रविष्टे, 16 सावान हिजरी 1447, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी 24.22 तक उपरांत पंचमी, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 22.56 तक उपरांत हस्त नक्षत्र, सुकर्मा योग 24.03 तक उपरांत धृति योग, बव करण 12.15 तक उपरांत बालव करण, चंद्रमा कन्या राशि में दिन-रात।

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : भाग्य सहायक रहेगा। अटके कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे।

वृष : दिनचर्या अस्त-व्यस्त रहेगी। व्यय अधिक होगा। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी। व्यवसाय में लाभ होगा।

मिथुन : दिनमान अनुकूल रहेगा। शुभ सूचना मिल सकती है। राजनीतिक संबंध सहायक रहेंगे। यात्रा संभव है।

कर्क : भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील रहेंगे। स्वजनों से निराशा होगी। नौकरी में स्थिति सुखद रहेगी।

सिंह : स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। विरोधी पक्ष से सचेत रहें। मन शांत रहेगा।

कन्या : धैर्य बनाए रखें। योजना में श्रमोपरांत सफलता मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें।

तुला : मानसिक उलझन बनी रहेगी। नौकरी में मन नहीं लगेगा। शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक : दिनमान प्रतिकूल रहेगा। राजकाज में परेशानी होगी। दूसरों पर भरोसा न करें। व्यवसाय में लाभ होगा।

धनु : मानसिक उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। योजना में सफलता मिल सकती है।

मकर : पूर्व में किए श्रम का लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अनैतिक कार्य से दूरी बनाए रखें।

कुंभ : लोकप्रियता बनी रहेगी। नई योजना में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में परिवर्तन का अवसर मिल सकता है।

मीन : राजकाज में सफलता मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में दबदबा बना रहेगा।

जन्मदिन

उर्मिला मातोंडकर, अभिनेत्री

आज जन्मे जातक बुद्धिमान, समाजसेवी एवं स्वतंत्र विचारों के होते हैं। इस वर्ष योजनाओं में सफलता मिलेगी। विकास के नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से वर्ष अनुकूल रहेगा। परिवार में समरसता बनी रहेगी। अविवाहितों की विवाह वार्ता चल सकती है। रोजगारपरक परीक्षाओं में अनुकूल सफलता मिलेगी।

सुडोकू

			3		2		9	8
		7		1				
9						1		6
8				6	1			
	3	5				4	8	
			8	3				2
5		1						9
				2		3		
3	9		5		4			

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

1	6	4	3	5	2	7	9	8
2	8	7	9	1	6	5	3	4
9	5	3	7	4	8	1	2	6
8	7	2	4	6	1	9	5	3
6	3	5	2	9	7	4	8	1
4	1	9	8	3	5	6	7	2
5	2	1	6	7	3	8	4	9
7	4	8	1	2	9	3	6	5
3	9	6	5	8	4	2	1	7

डेली हेल्थ कैप्सूल

कई बीमारियों में लाभकारी है वज्रदंती

वज्रदंती में मौजूद औषधीय गुण गठिया, दांतों के रोग, त्वचा और मानसिक परेशानियों में लाभ पहुंचाते हैं।

आयुर्वेद में वज्रदंती के पौधे को विशेष महत्व दिया जाता है। पुराने समय से ही पारंपरिक चिकित्सा में वज्रदंती की छाल, पत्ती, जड़ और फूल का उपयोग किया जाता रहा है। इसमें एंटीअर्थराइटिक क्लोरोफॉर्म और मेथेनॉल होता है, जो गठिया के दर्द में आराम पहुंचाता है। इससे मांसपेशियों की सूजन को कम करने में भी मदद मिलती है।

वज्रदंती की पत्तियों में पाए जाने वाला हाइड्रॉक्सीफ्लेवॉन केमिकल चिंता और घबराहट को दूर करने में सहायक होता है। वज्रदंती में एंटीबैक्टीरियल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मसूड़ों में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। अक्सर मसूड़ों की सूजन और दर्द की वजह गंदगी और कीटाणु होते हैं, जो दांतों के बीच जमा हो जाते हैं। वज्रदंती इन कीटाणुओं को साफ करने का काम करता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। वज्रदंती की पत्तियों को पीसकर दांतों पर रगड़ने से दांतों के दर्द को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही इससे दांतों की चमक भी बरकरार रहती है। वज्रदंती एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है, इसलिए चिकित्सा के साथ-साथ इसे त्वचा संबंधी विकारों को दूर करने में भी मदद मिलती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

वज्रदंती की गलत खुराक से गंभीर पाचन संबंधी समस्याएं, बेचैनी, बार-बार डकार आना, पेट में जलन और एलर्जी हो सकती हैं। इसलिए चिकित्सक की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें।
-डॉ. नवीन चंद्र जोशी
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक

न्यूज डायरी

वेतन बढ़ने से कोल इंडिया पर 3,400 करोड़ का बोझ

नई दिल्ली। सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने अधिकारियों के वेतन को मध्य स्तर तक बढ़ा दिया है। यह 1 जनवरी, 2017 से सांकेतिक रूप से प्रभावी है। कंपनी ने कहा, हालांकि, वेतन संशोधन का वित्तीय प्रभाव 23 अगस्त, 2023 से लागू होगा। 31 दिसंबर, 2026 तक के लिए वेतन वृद्धि का अनुमानित वित्तीय प्रभाव लगभग 3,400 करोड़ रुपये है। एजेंसी

बिक्री बढ़ाने के लिए टेस्ला की किस्त योजना

नई दिल्ली। टेस्ला इंडिया ने देश में बिक्री में आई कमी को दूर करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इनमें किस्त योजना भी शामिल है। इलेक्ट्रिक कारों की ओर रुख करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने को टेस्ला ने 3 लाख का एक्सचेंज प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। मॉडल वाई को मात्र 6 लाख के डाउन पेमेंट के साथ 49,000 रुपये की मासिक किस्त पर खरीद सकते हैं। एजेंसी

एसके फाइनेंस का एयूएम 23 फीसदी बढ़ा

जयपुर। रिटेल फाइनेंशियल क्षेत्र की प्रमुख एनबीएफसी कंपनी एसके फाइनेंस लि. ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में दमदार वित्तीय प्रदर्शन किया है। इस दौरान कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) सालाना आधार पर 23 फीसदी बढ़कर 15,049 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी की कुल परिचालन आय 711.22 करोड़ रुपये रही, जबकि शुद्ध लाभ 88.37 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। ब्यूरो

आर्टेमिस मेडिकेयर का राजस्व 272 करोड़

नई दिल्ली। आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज का तीसरी तिमाही में राजस्व 272.35 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 17.2 फीसदी अधिक है। शुद्ध मुनाफा 20.60 करोड़ से 7.9 फीसदी बढ़कर 22.23 करोड़ हो गया। चेयरमैन ओंकार कंवर ने कहा, चालू वित्त वर्ष के नौ महीनों में आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम का राजस्व 17.5 फीसदी बढ़कर 762.77 करोड़ रहा। ब्यूरो

सेंसेक्स में आठ माह की बड़ी एकदिनी तेजी, टैरिफ प्रभावित शेयरों में उछाल

दिग्गज शेयरों में चौतरफा तेजी के साथ छोटी एवं मझोली कंपनियों में भारी खरीदारी का असर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ में कटौती की घोषणा से घरेलू शेयर बाजारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी 2.55 फीसदी तक चढ़कर बंद हुए। व्यापार समझौते की खबर से वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री खाद्य निर्यात और विशेष उपयोग वाले रसायन क्षेत्रों से जुड़े शेयरों में तेज उछाल देखा गया।

दिग्गज शेयरों में चौतरफा तेजी के साथ छोटी एवं मझोली कंपनियों में भारी खरीदारी से सेंसेक्स 2,072.67 अंक या 2.54 फीसदी की बढ़त के साथ 83,739.13 पर बंद हुआ। यह 12 मई, 2025 के बाद सेंसेक्स में आठ महीने की सबसे बड़ी एक दिवसीय तेजी है। उस दिन सेंसेक्स 2,975.43 अंक उछलकर 82,429.90 पर बंद हुआ था।

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा और भारतीय निर्यात पर टैरिफ में कटौती से निर्यात-उन्मुख एवं कमोडिटी से जुड़े क्षेत्रों की अगुवाई में बाजार का दायरा बेहद सकारात्मक रहा। मेहता इक्विटीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, बाजार को इस समझौते की घोषणा का लंबे समय से इंतजार था, जिसने अब एक बड़ी तेजी का रास्ता तैयार किया है। इससे पहले यूरोपीय संघ के साथ भी व्यापार समझौता हुआ था। इस तरह, भारतीय उत्पादों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

पांच शेयर सर्वाधिक उछले	
अदाणी पोर्ट्स	9.12%
बजाज फाइनेंस	6.68%
इंडिगो	5.51%
पावरग्रिड	4.85%
सनफार्मा	4.54%

सभी इंडेक्स हरे निशान में	
सर्विसेज	4.86%
रियल्टी	4.79%
बिजली	4.79%
यूटिलिटी	3.92%
इंडस्ट्रियल्स	3.44%

5,236 करोड़ की खरीदी — विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 5,236 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की | घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1,014.24 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे

टेक्सटाइल शेयरों में 20 फीसदी तक की बढ़त	
गोकलदास एक्सपोर्ट्स	20%
वेलस्पन लिविंग	19.85%
गरवारे टेक. फाइबर्स	17.07%
केपीआर मिल	15.31%
वर्धमान टेक्सटाइल	12.12%

रत्न और आभूषण शेयर भी 20 फीसदी तक चढ़े	
गोल्डियम इंटरनेशनल	20%
वैभव ग्लोबल	9.13%
कल्याण ज्वेलर्स	4.91%
टाइटन	2.80%
पीएन गाडगिल	1.52%

विदेशी निवेश की बढ़ी उम्मीद

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और रुपये में मजबूती से बाजार में विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) आने की उम्मीद बढ़ी है। अमेरिकी टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने से उभरते बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत हुई है और निर्यातोन्मुख क्षेत्रों के लिए परिदृश्य बेहतर हुआ है। **-विनोद नायर, शोध प्रमुख, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि.**

दुनियाभर के बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी करीब सात फीसदी उछला। जापान के निक्केई, चीन के शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग के हैंगसेंग भी बढ़त में रहे।

■ यूरोपीय बाजार में भी तेजी। अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए थे।

रूसी तेल के सौदों को पूरा करने के लिए भारतीय रिफाइनरियों को चाहिए समय

नई दिल्ली। रूसी तेल के सौदों को पूरा करने को भारतीय रिफाइनरियों को समय चाहिए होगा। इसके बाद ही वहां से आयात रोका जा सकेगा। सरकार ने अभी तक उन्हें आयात रोकने का आदेश नहीं दिया है। सूत्रों ने कहा, अमेरिका व भारत के बीच व्यापार समझौते में रूस से भारतीय तेल खरीद पर रोक शामिल है।

भारतीय कंपनियों ने फरवरी में लोड होने वाले और मार्च में पहुंचने वाले कार्गो की बुकिंग पहले ही कर ली है। इनको पूरा करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी। 2022 में यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद भारत रियायती दरों पर मिलने वाले रूसी कच्चे तेल का बड़ा खरीदार बन गया। अमेरिका रूस के तेल राजस्व को कम करना चाहता है ताकि मॉस्को के लिए युद्ध का वित्तपोषण करना मुश्किल हो जाए। भारत धीरे-धीरे रूस से तेल का आयात कम करेगा। आयात पूरी तरह बंद होने से रूस समर्थित भारतीय रिफाइनर नायरा की 4 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता की रिफाइनरी के संचालन पर असर पड़ेगा। एजेंसी

नायरा का आयात शून्य होगा : पिछले साल जुलाई में यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बाद भुगतान कठिनाइयों के चलते इराक की सोमो और सऊदी अरामको द्वारा आयात बंद करने के बाद नायरा रूसी कच्चे तेल पर निर्भर है। नायरा का अप्रैल में रूसी तेल आयात नगण्य होगा, क्योंकि रखरखाव के लिए 10 अप्रैल से एक महीने से अधिक समय तक रिफाइनरी बंद रहेगी।

आरबीआई : तीन दिवसीय एमपीसी बैठक आज से

नई दिल्ली। विकास केंद्रित केंद्रीय बजट, कम महंगाई और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के मद्देनजर आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बुधवार से तीन दिवसीय बैठक शुरू करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई ने फरवरी से अब तक रेपो दर में 1.25 फीसदी की कमी की है। चूंकि, विकास या महंगाई को लेकर गंभीर चिंताएं नहीं हैं, इसलिए वह दरों में यथास्थिति बनाए रख सकता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, एमपीसी के रेपो दर पर कायम रहने की संभावना है और यह दर-कटौती चक्र का अंत भी हो सकता है। वहीं, इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, इस समय विराम उचित है, ताकि जनवरी, 2026 की खुदरा महंगाई और 2023-24 से 2025-26 तक के जीडीपी आंकड़ों का आकलन किया जा सके। हालांकि, कम महंगाई आरबीआई को दर कटौती पर विचार करने की गुंजाइश देती है। एजेंसी

किफायती हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का घटेगा एयूएम

नई दिल्ली। किफायती आवासीय परियोजनाओं को कर्ज देने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां यानी एयूएम चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान घटकर 21 फीसदी रह सकती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किफायती हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का एयूएम 23 फीसदी रहा था।

घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा, आने वाले वित्त वर्ष 2026-27 में भी इन कंपनियों के एयूएम में वृद्धि की रफ्तार 20-21 फीसदी पर स्थिर बनी रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रॉपर्टी के बदले लोन (एलएपी) सेगमेंट में वृद्धि भी 30 फीसदी से घटकर चालू वित्त वर्ष में 24-26 फीसदी रह सकती है, क्योंकि कुछ खास तरह के कर्जदारों की संपत्ति की गुणवत्ता पर दबाव के बाद लेंडर्स अंडरराइटिंग को फिर से एडजस्ट कर रहे हैं। इससे क्रेडिट लागत में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। एजेंसी

सोना : विदेशी बाजार में 2008 के बाद एक दिन में सर्वाधिक उछाल

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में दो दिनों की गिरावट के बाद फिर बड़ी तेजी आ रही है। मंगलवार को विदेशी बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत दिन के कारोबार में 4.9 फीसदी की बढ़त के साथ 4,895.69 डॉलर पर पहुंच गई। यह नवंबर, 2008 के बाद सोने में सबसे बड़ा एकदिनी उछाल है।

निवेशकों ने दो दिनों की गिरावट में सोने और चांदी की जमकर खरीदारी की। इससे कीमतों में तेजी देखी गई।

स्पॉट गोल्ड का भाव सोमवार को 4,403.24 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था। पिछले सप्ताह का 5,594.82 डॉलर प्रति औंस का स्तर फिलहाल ऐतिहासिक उच्चतम स्तर बना हुआ है। अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने के वायदा भाव में 5.7 फीसदी की वृद्धि हुई और यह 4,918.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी 8.6 फीसदी बढ़कर 86.3 डॉलर प्रति औंस हो गई। शुक्रवार को इसमें रिकॉर्ड 27 फीसदी और सोमवार को 6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। ब्यूरो

■ ***रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचेगी सोने की कीमत :*** *विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के केविन वॉर्श को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के रूप में नामित करने की घोषणा के बाद बाजार में अत्यधिक बिकवाली हुई थी। हालांकि, सोने में तेजी जारी रहेगी और इस साल के अंत तक यह नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगी। सोने ने अब 4,858 डॉलर पर अपनी पहली बाधा पार कर ली है।*

देश में 2030 तक जीसीसी की संख्या बढ़कर 2,400 तक होने का अनुमान

नई दिल्ली। देश में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की संख्या 2030 तक बढ़कर लगभग 2,400 होने का अनुमान है। एफआईसीआई और एनारॉक के मुताबिक, इन जीसीसी में 28 लाख से अधिक पेशेवर कार्यरत होंगे।

2024 के अंत तक भारत में 1,700 से अधिक जीसीसी कंपनियां थीं। तब 19 लाख से अधिक पेशेवर इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। देश में जीसीसी कंपनियों का बाजार आकार 2024 में 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 105-110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह 10 फीसदी चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत का जीसीसी बाजार तेजी से विस्तारित हुआ है। इसका आकार 2019 में 30 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 64 अरब डॉलर हो गया है। यह वृद्धि आईटी/आईटीईएस, बीएफएसआई, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान, और इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों से लगातार बढ़ती मांग से प्रेरित है। यह गति जारी रहेगी। जीसीसी उपस्थिति शीर्ष सात शहरों से आगे फैल रही है और जयपुर, इंदौर, सूरत, कोच्चि और कोयंबटूर जैसे टियर-2 शहरों में भी लगातार विस्तार कर रही है। एजेंसी

संभाव्यता का अध्ययन एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

ई-निविदा सूचना संख्या. KIR/GSU/01 of 2026 तारीख: 31-01-2026। नीचे उल्लेखित कार्यों के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-निविदा आमंत्रित किया गया है। **कार्य का संक्षिप्त विवरण:** (क) कटिहार मंडल के रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रीज सहित लेवेल क्रासिंग के विलोपन हेतु संभाव्यता के अध्ययन एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (38 एल-जिंग)। (ख) कटिहार मंडल के रेलवे क्रासिंग पर रोड ओवर ब्रीज सहित लेवेल क्रॉसिंग के विलोपन हेतु संभाव्यता का अध्ययन एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (55 एल-जिंग)। **निविदा राशि:** ₹8,25,28,175.89/-। **धरोहर राशि:** ₹5,62,700/-। **निविदा बंद होने की तारीख एवं समय:** 25-02-2026 तारीख के 15.00 बजे में **एवं खुलेगी:** 15.30 बजे में। उपरोक्त ई-निविदा की संपूर्ण जानकारी आगामी 25-02-2026 तारीख के 15.00 बजे तक www.ireps.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

डीवाई.सीपीएम/जीएस/कटिहार
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
मुस्कान के साथ ग्राहकों की सेवा में

पश्चिम मध्य रेल
सामग्री प्रबंधन विभाग
भंडार आपूर्ति हेतु 'ई'-निविदा सूचना संख्या/ईपीएस/118/2025)

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदायें आमंत्रित करते हैं। कोई भी हस्तलिखित/डाक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पूर्ण विवरण/विनिर्देशन के लिए वेबसाइट https://ireps.gov.in पर ई निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक	टेंडर नं.	संक्षिप्त विवरण	निविदा मात्रा	नियत तारीख
1	30251205A	स्क्रू कपलिंग असेंबली (एनहांस्ड)	850 नंबर	24.02.2026
2	20265001	सप्लाई, इंस्टालेशन ऑफ क्लाउड बेस्ड टेम्परेचर सेंसर मॉनिटरिंग ऑफ 3 फेज लोकोमोटिव्स	94 सेट्स (47 सेट्स सप्लाई एंड 47 सेट्स AMC आफ्टर कम्पलीशन ऑफ वारंटी)	02.03.2026
3	30251545	YAW डैम्पर फॉर आल टाइप ऑफ LHB कोचेस	1412 नंबर	10.03.2026

50 लाख रुपये से कम अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के लिए इच्छुक फर्मों को www.ireps.gov.in पर जाने की सलाह दी जाती है।
(हस्ता.)
प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	आरंभिक तिथि अंतिम तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (अनुमानित) रु. में	बोर्ड/निगम प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/संपर्क जानकारी/ईमेल
1	नगर परिषद बहादुरगढ़	वार्ड सं. 15, नगर परिषद, बहादुरगढ़ में विभिन्न सीसी गली का निर्माण एवं नाला की मरम्मत + 4 कार्य।	Closing Date 07.02.2026	Rs. 1,87,71,584/-	https://etenders.hry.nic.in	9812433393 eo-bahadurgarh@ulbharyana.gov.in

अग्रिम जानकारी हेतु कृपया वेबसाइट www.haryanaeprocurement.gov.in या www.etenders.hry.nic.in पर जाएं। SAMVAD:-13/2026/40/42646/I/1/7 Dt.03/02/2026

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	आरंभिक तिथि अंतिम तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (अनुमानित) रु. में	बोर्ड/निगम प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/संपर्क जानकारी/ईमेल
1	नगर निगम फरीदाबाद	5 वर्ष के संचालन एवं रखरखाव आधार के साथ 2 अदद वाहन की प्राप्ति, जिन पर सूखे एवं गीले कचरे की सक्शन मशीनें जड़ी हों। (फरीदाबाद)	31.01.2026 11.02.2026	EST. COST Rs. 2.09 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9729424282 mc2swmsbm@gmail.com

अग्रिम जानकारी हेतु कृपया वेबसाइट www.haryanaeprocurement.gov.in या www.etenders.hry.nic.in पर जाएं। SAMVAD:-13/2026/40/42652/I/1/7 Dt.03/02/2026

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	आरंभिक तिथि अंतिम तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (अनुमानित) रु. में	बोर्ड/निगम प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/संपर्क जानकारी/ईमेल
1	नगर निगम फरीदाबाद	सैक्टर-13, एमसीएफ में 5 टीपीडी वेस्ट को बायोगैस प्लांट के संचालन एवं रखरखाव हेतु एजेंसी का चयन।	02.02.2026 21.02.2026	EST. COST EMD CONTRACTOR RS. 50,000/-	https://etenders.hry.nic.in	9729424282 memandeep188@gmail.com
2	नगर निगम फरीदाबाद	नगर निगम फरीदाबाद में डिवीजन-I (एनआईटी) में 6 माह की अवधि हेतु जीवीपी प्वाईंट्स/अन्य खाली प्लाट जहां कचरा डम्प/संचित किया हुआ है से हस्तांतरित किये वाले केंद्र तक एमएसडब्ल्यू को उठाने हेतु अनुमान+ 4 कार्य।	02.02.2026 12.02.2026	EST. COST Rs. 890.74 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9729424282 memandeep188@gmail.com

अग्रिम जानकारी हेतु कृपया वेबसाइट www.haryanaeprocurement.gov.in या www.etenders.hry.nic.in पर जाएं। SAMVAD:-13/2026/60/42649/I/1/7 Dt. 03/02/2026

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	आरंभिक तिथि अंतिम तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (अनुमानित) रु. में	बोर्ड/निगम प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/संपर्क जानकारी/ईमेल
1	एचएसएएमबी पानीपत	जिला पानीपत में 3 अदद सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत (सड़क आईडी-3498, 6352 , एवं 9715) (1) बलाना से मुख्य मार्ग गोहाना आईडी एच-3498 (2) सिवाह-छज्जपुर रोड से सैक्टर -29 पानीपत आईडी एच-6352 (3)झत्तीपुर से रेलवे फाटक आईडी एच-9715 + 2 कार्य।	27.01.2026 06.02.2026	Rs. 3,15,44,576/-	https://etenders.hry.nic.in	01804002275 xenpanipat2025.hsamb@gmail.com

अग्रिम जानकारी हेतु कृपया वेबसाइट www.haryanaeprocurement.gov.in या www.etenders.hry.nic.in पर जाएं। SAMVAD:-13/2026/60/42659/I/1/7 Dt. 03/02/2026

कार्यालय - सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून

पत्रांक–161/XLII–1/2026–05(08)2012/E–70356 देहरादून: दिनांक 02 फरवरी, 2026

विज्ञप्ति

संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार में **सचिव के 01 पद वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड पे रू0–8000/– (छठे वेतनमान के अनुसार)** पर सेवास्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी एवं राज्य सरकार की वेबसाइट **www.uk.gov.in** से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त वांछित अभिलेख संलग्नकों सहित नियत तिथि/समय तक **सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, कक्ष संख्या–205, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम भवन, 04 सुभाष रोड, देहरादून–248001** के पते पर स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्राप्त न होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

सेवास्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले सचिव के रिक्त पद तैनाती हेतु निर्धारित शर्तों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अर्हताएं/अधिमानी अर्हताएं
1	सचिव उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार	रू0 37400–67000 ग्रेड पे रू0–8000/– (छठे वेतनमान के अनुसार)	01	**अनिवार्य अर्हताएं:–** 1. आवेदक राजकीय महाविद्यालय में संस्कृत/हिन्दी में प्रवक्ता (छठे वेतनमान के अनुसार) के पद पर अध्यापन कार्य के साथ शोध निर्देशन का अनुभव रखता हो। **अथवा** आवेदक उत्तराखण्ड के किसी राजकीय इण्टर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हो 2. आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2026 को 50 वर्ष से कम तथा 55 वर्ष से अधिक न हो। 3. आवेदक को सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति हेतु अपने पैतृक विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। 4. आवेदक को विगत 05 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न दी गयी हो। 5. मा0 न्यायालय में वाद न चलने सम्बन्धी प्रमाण पत्र। 6. विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न होने का प्रमाण पत्र। **अधिमानी अर्हता:–** समान अंक होने की स्थिति में स्नातकोत्तर डिग्री/पी.एच.डी. उपाधि धारक को वरीयता दी जायेगी।

आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि के 01 माह के भीतर अथवा 30 दिवसों में किसी भी कार्य दिवस में सायं 6:00 बजे तक स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से विज्ञप्ति में प्रकाशित पते पर जमा किये जा सकते हैं। इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

कवीन्द्र सिंह, अपर सचिव।

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, बेतिया।

शुद्धि पत्र

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित **ई०–निविदा आमंत्रण सूचना सं०–27/2025–26 (S.B.D. Based)** जो दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक– 22.11.2025 एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था जिसका **PR No. 017622 (BCD) 2025-26** है एवं शुद्धि पत्र का संशोधित तिथि जिसका **PR No. 020228 (BCD) 2025-26** है, जो दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक– 25.12.2025 एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, कार्य के तिथियों को निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है–

क्र. सं.	विवरणी	पूर्व का तिथि	संशोधित तिथि	पुनः संशोधित तिथि
3	निविदा (परिमाण विपत्र) को सिस्टम पर अपलोड करने की तिथि	दिनांक– 08.12.2025	दिनांक– 08.01.2026	दिनांक– 19.02.2026
4	निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक– 02.01.2026 को 03:00 बजे अप० तक।	दिनांक– 02.02.2026 को 03:00 बजे अप० तक।	दिनांक– 16.03.2026 को 03:00 बजे अप० तक।
5	निविदा जमा करने (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक– 03.01.2026 को 03:00 बजे अपराहन् तक।	दिनांक– 03.02.2026 को 03:00 बजे अप० तक।	दिनांक– 17.03.2026 को 03:00 बजे अप० तक।
6	निविदा खोलने (तकनीकी बीड) की तिथि एवं समय	दिनांक– 05.01.2026 को 03:00 बजे अपराहन् तक।	दिनांक– 05.02.2026 को अपराहन् 3:00 बजे तक।	दिनांक– 18.03.2026 को अपराहन् 3:00 बजे तक।
7(i)	प्रिबीड मिटिंग की तिथि समय एवं स्थान	दिनांक– 15.12.2025 को 12:30 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी का कार्यालय।	दिनांक– 12.01.2026 को 12:30 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी का कार्यालय।	दिनांक– 23.02.2026 को 12:30 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी का कार्यालय।
7(ii)	प्रिबीड मिटिंग की तिथि समय एवं स्थान	दिनांक– 22.12.2025 को 12:30 बजे मुख्य अभियंता, उ० उपभाग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय।	दिनांक– 19.01.2026 को 12:30 बजे मुख्य अभियंता, उ० उपभाग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय।	दिनांक– 09.03.2026 को 12:30 बजे मुख्य अभियंता, उ० उपभाग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय।

शेष शर्ते यथावत रहेगी।
PR- 023148 (B C D) 2025-26
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, बेतिया।
नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
बेस नंबर 67-70, सेक्टर-2, पंचकुला-134151, वेबसाईट www.hssc.gov.in

परिशिष्ट-ए में शुद्धिपत्र (विज्ञापन संख्या 02/2026)

विज्ञापन संख्या 2/2026, दिनांक 09.01.2026 के क्रम में, उम्मीदवारों की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ने अनुरोध संख्या 2901 के अनुसार समूह संख्या 5 श्रेणी संख्या 36 के अंतर्गत गैस रूम ऑपरेटर के पदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 32 कर दी है। **पदों का संशोधित विभाजन निम्नानुसार है:-**

श्रेणी नं.	विभाग का नाम	पद का नाम	वेतनमान	जनरल	डीएससी	ओएससी	बीसीए	बीसीबी	ईडब्ल्यूएस	ईएसएम जनरल	ईएसएम डीएससी	ईएसएम ओएससी	ईएसएम बीसीए	ईएसएम बीसीबी	कुल	पीडब्ल्यूडी बीएच	पीडब्ल्यूडी एचएच	पीडब्ल्यूडी ओएच	पीडब्ल्यूडी एमडी
36	डीएमईआर, हरियाणा	गैस कक्ष संचालक	एफपीएल-4	17	4	0	4	0	4	3	0	0	0	0	32	2	1	1	1

-हस्ता /-
अवर सचिव
कृते सचिव,
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग,
पंचकुला
स्थान: पंचकुला
दिनांक: 03.02.2026
SAMVAD:- 1159/13/699/2026/42634/1/7 Dt.03/02/2026

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	आरंभिक तिथि अंतिम तिथि	राशि /ईएमडी (लगभग) रु. में	विभाग की वेबसाईट	नोडल अधिकारी/संपर्क जानकारी/ईमेल
1	महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, पंचकुला, हरियाणा	आईएस-9271:2004 के अनुसार छिद्रित नालीदार पीवीसी पाइप और फिटिंग की खरीद के लिए 2 साल का दर अनुबंध। आकार 80 मिमी बाहरी व्यास, 160 मिमी बाहरी व्यास, 200 मिमी बाहरी व्यास, 294 मिमी बाहरी व्यास।	03.02.2026 17.02.2026		https://etenders.hry.nic.in dsndharyana.gov.in	0172-2570122 Supplies@hry.nic.in
2	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा, पंचकुला	जल सुरक्षा हरियाणा कार्यक्रम (डब्ल्यूएसएचपी) के अंतर्गत कार्यों के विस्तृत अनुमानों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के संबंध में निविदा सूचना का प्रकाशन।	02.02.2026 23.02.2026	EMD 10 LACS	https://etenders.hry.nic.in	01722585444 xenproject1pkl@gmail.com
3	बीपीएस गवर्नमेंट. मेडिकल कॉलेज फॉर विमेन खानपुर कलां सोनीपत	बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर विमेन, खानपुर कलां, सोनीपत में दो साल के लिए रसोई और आहार सेवाओं के लिए निविदा।	03.02.2026 12.02.2026	EMD 2.88 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9416803361 Bpsgmc.purchase@gmail.com
4	पंचायती राज, नारनौल	आजमाबाद मोखुता ब्लॉक निजामपुर - चोरया से ढाणी ततला तक आईपीबी रास्ता का निर्माण + 4 कार्य	02.02.2026 09.02.2026	136.97 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9017179090 prexeeng.nrl@gmail.com
5	नागरिक उड्डयन विभाग, हरियाणा	डीजीसीए/बीसीएएस/एमओसीए आदि द्वारा अपेक्षित सभी प्रासंगिक नियमावली की तैयारी, प्रस्तुति, अनुमोदन, संशोधन और रखरखाव।	03.02.2026 09.02.2026	EMD 40,000/-	https://etenders.hry.nic.in	01722709386 cavation@hry.nic.in

अधिक जानकारी हेतु कृपया वेबसाइट www.etenders.hry.nic.in पर जाएं। PRDH : 11/2026/100/42661/I/1/7 Dt. 03/02/2026

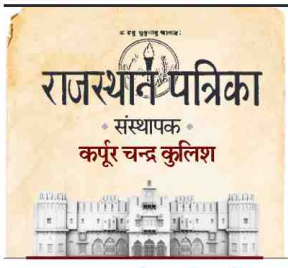

व्यवस्था और अभिभावकों की साझी जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि बच्चों को ऐश के लिए पैसा और कार की चाबियां थमाने के लिए माता-पिता जिम्मेदार हैं, यह केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी भी है। खासतौर से यह चेतावनी उन अभिभावकों के लिए है, जो जाने-अनजाने अपने नाबालिग बच्चों के हाथों में न सिर्फ वाहन, बल्कि जोखिम और मौत की चाबियां सौंप रहे हैं। चेतावनी उस व्यवस्था के लिए भी है, जो हादसों के बाद महज मौतों और घायल होने वालों के आंकड़े गिनकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है।

आंकड़े इस बात को बखूबी बयां करते हैं कि किस तरह से नाबालिगों का वाहन चलाना जोखिम भरा है। वर्ष 2023-24 के दौरान देश में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से 11,890 हादसे हुए जिनमें 2,537 मौतें हो गईं। ये महज नंबर नहीं हैं। हर नंबर के पीछे एक परिवार का उजड़ना, एक भविष्य का खत्म होना तो है ही, इसमें समाज की सामूहिक विफलता छिपी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कहा है कि नाबालिगों को वाहन चलाने देना महज कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध है, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर माता-पिता पर आती है। अदालत का यह रुख उस मानसिकता पर करारा प्रहार है, जिसमें बच्चा है, सीख जाएगा या थोड़ा बहुत चलाने से क्या होगा जैसी दलीलें दी जाती हैं। हकीकत यह है कि आज बच्चों के हाथ में मोबाइल की तरह ही वाहन की चाबी आसानी से पहुंच रही है।

आधुनिकता और दिखावे की होड़ में अभिभावक यह भूल जाते हैं कि सड़क कोई खेल का मैदान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अनुशासन भरी राह है। वाहन चलाना केवल संतुलन और रफ्तार का सवाल नहीं, बल्कि निर्णय क्षमता, कानून की समझ और मानवीय संवेदनशीलता की मांग करता है। ये सब नाबालिग उम्र में स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं होती। इसीलिए कानूनी प्रावधान भी इसी हिसाब से किए गए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हादसे के बाद नाबालिग के नाम पर सहानुभूति बटोरना या परिवार की सामाजिक हैसियत का हवाला देना सजा से बचने का रास्ता कतई नहीं हो सकता। कानून की नजर में जिम्मेदार वही होगा, जिसने नियम तोड़ने की छूट दी- चाहे वह माता-पिता हों, वाहन मालिक हों या लाइसेंसिंग और पुलिस व्यवस्था की ढिलाई। यह तथ्य भी उतना ही चिंताजनक है कि कई मामलों में हादसे के बाद सबूत मिटाने, ड्राइवर बदलने या रसूख के दम पर मामले को हल्का करने की कोशिशें होती हैं।

अभिभावकों को समझना होगा कि बच्चों को अनुशासन सिखाना, 'ना' कहना और नियमों की सीमा तय करना भी उतना ही जरूरी है जितना उन्हें सुविधाएं देना। सरकार और प्रशासन को लाइसेंस प्रणाली, वाहन पंजीयन और यातायात निगरानी को और सख्त बनाना होगा। अब भी अनसुनी की गई, तो हर अगला हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सामूहिक लापरवाही का प्रमाण होगा।

भारत-अमरीका ट्रेड डील: इस समझौते को ट्रंप पर बने व्यापारिक और वैश्विक दबाव के रूप में देखा जाना चाहिए

आर्थिक अवसर और वैश्विक रणनीति का संगम

विनय कौड़ा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
@patrika.com

भारत की ऊर्जा नीति कभी किसी एक ध्रुव पर आश्रित नहीं रही। रूस से तेल आयात, विशेषकर यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के लिए सस्ते कच्चे तेल का स्रोत भर नहीं था। वह न तो पश्चिम के विरोध में था न ही रूस के समर्थन में, वह सिर्फ भारतीय हितों के पक्ष में था।

भारत और अमरीका के मध्य व्यापारिक समझौता दोनों देशों के रिश्तों में ऐसा मोड़ है जहां आर्थिक अवसर, कूटनीतिक अपेक्षाएं और रणनीतिक विवेक आमने-सामने खड़े हैं। इस समझौते को यदि केवल आंकड़ों, शुल्क दरों और निर्यात-आयात की भाषा में पढ़ा जाए तो उसका अर्थ सीमित रह जाएगा। वैश्विक शक्ति-संतुलन और उभरते बहुध्रुवीय परिप्रेक्ष्य में यह समझौता निर्णायक क्षण के रूप में उभरता है। अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से घोषित यह समझौता, जिसमें भारत पर लगाए जाने वाले शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, प्रथम दृष्टि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत का संकेत देता है।

भारत के वस्त्र, रत्न-आभूषण, चमड़ा, कृषि एवं श्रम-प्रधान उद्योग वे क्षेत्र हैं, जहां उत्पादन केवल पूंजी से नहीं, बल्कि श्रम, कौशल और परंपरा से जन्म लेता है। अमरीकी बाजार में शुल्क में कटौती भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य देगी, निर्यात की संभावनाएं बढ़ाएगी और घरेलू उद्योगों के लिए नई गति प्रदान करेगी। परंतु यह अवसर सिर्फ आर्थिक लाभ का प्रश्न नहीं है। यह भारत की विनिर्माण क्षमता, श्रम कौशल और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसकी बढ़ती प्रभावशाली भूमिका का सजीव प्रतिबिंब भी है। दरअसल, इस समझौते को ट्रंप पर बने वैश्विक और व्यापारिक दबाव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। भारत की ओर से द्वितीयक शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारत ने रूस से तेल आयात करना जारी रखा, जिससे स्पष्ट हो गया कि भारत अपने रणनीतिक और ऊर्जा हितों से समझौता नहीं करेगा। इसी बीच, पिछले महीने भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हो गया, जिसने अमरीका के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी। करीब दो दशक की लंबी बातचीत के बाद यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अमरीका पर निर्भरता को कम करने के प्रयास का प्रतीक बन गया। इसे वैश्विक व्यापार संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों के संतुलन का प्रयास है।

भारत-ईयू 'मेगा डील' ने वाइट हाउस पर दबाव बढ़ाया और अमरीका को भारत के साथ पुनः व्यापार वार्ता में जुटने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम ट्रेड डील के रूप में सामने आया है जिसे ट्रंप प्रशासन की उस रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है जिसमें सख्त व्यापार रुख और प्रमुख साझेदार खोने के जोखिम के बीच संतुलन साधा गया। यह पूरी प्रक्रिया न केवल भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक शक्ति को उजागर करती है, बल्कि उसकी कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी मजबूती देती है। हालांकि यह समझौता जिस समय सामने आया है, वह समय सामान्य नहीं है। विश्व व्यवस्था एक गहरे संक्रमण से गुजर रही है। चीन के साथ अमरीका का व्यापार युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन और 'फ्रेंड-शोरिंग' की नीति- इन सबके बीच भारत को एक वैकल्पिक उत्पादन केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि भारत को इससे लाभ होगा या नहीं। प्रश्न है कि यह लाभ कितना स्थायी होगा। यही वह बिंदु है जहां इस समझौते का भूराजनीतिक पक्ष उभरता है और वही सबसे अधिक विचारणीय है। बहरहाल, भारत की ऊर्जा नीति कभी किसी एक ध्रुव पर आश्रित नहीं रही। रूस से तेल आयात, विशेषकर यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के लिए सस्ते कच्चे तेल का स्रोत भर नहीं था। वह न तो पश्चिम के विरोध में था न ही रूस के समर्थन में- वह केवल भारतीय हितों के पक्ष में था।

भारत ने जब बाद में रूसी तेल आयात में आंशिक कमी की तो भी उसके पीछे वैश्विक कीमतों में बदलाव, बीमा और शिपिंग प्रतिबंध तथा बाजार की व्यावहारिक स्थितियां थीं। इसलिए यह अपेक्षा कि भारत अपनी ऊर्जा नीति को अमरीकी रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालेगा, न तो व्यावहारिक है और न भारत के हित में। फिलहाल इस आशंका पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतना अवश्य है कि भारत, रूस से आयात घटाकर अमरीका-वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ा सकता है। फिर भी वेनेजुएला से तेल की मात्रा अभी सीमित है और लॉजिस्टिक चुनौतियां बरकरार हैं। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना का प्रश्न अवश्य गूढ़ हो जाता है। चाबहार भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं, एक ऐसा मार्ग है जो पाकिस्तान की भौगोलिक बाधा को लांघकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाता है। यह परियोजना भारत की उस रणनीतिक कल्पना का हिस्सा है जिसमें वह स्वयं को केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रखता बल्कि यूरेशियाई शक्ति-संरचना में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। इस व्यापार समझौते में चाबहार पोर्ट पर काई ठोस विवरण शामिल नहीं हैं, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। भारत को अमरीका से मिले 6 माह के प्रतिबंध छूट ने चाबहार के रणनीतिक भविष्य पर अस्थायी राहत दी थी, जो अप्रैल 2026 तक ही वैध है। 2026-27 के बजट में चाबहार परियोजना के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया है जो यह संकेत देता है कि भारत इस परियोजना पर पूर्वनिर्धारित कर रहा है। हालांकि अगर भारत इस परियोजना से पीछे हटता है तो रिक्त स्थान को भरने के लिए चीन तत्पर खड़ा है।

भारत-अमरीका संबंध दीर्घकालिक रणनीतिक हितों पर आधारित हैं। भविष्य की स्थिरता इसी में निहित है कि भारत आत्मविश्वास के साथ आर्थिक और रणनीतिक क्षमताओं को सुदृढ़ करे तथा अमरीका सहित अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग को व्यापक क्षेत्रीय संतुलन और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की दिशा में आगे बढ़ाए।

प्रसंगवश

जोखिम में मासूमों की जिंदगी, आखिर जिम्मेदार कौन?

अनफिट, क्षतिग्रस्त और बिना अनुमति सड़कों पर दौड़ रहीं बाल वाहिनियां

स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा क्या अब सिर्फ हादसे के बाद चर्चा का विषय रह गई है? हर सुबह सड़कों पर दौड़ती बाल वाहिनियां इस सवाल का जवाब खुद देती नजर आती हैं। क्षमता से दोगुने बच्चों को ठूंसकर ले जाते वाहन, टूटे दरवाजे, जर्जर सीटें और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के सफर करते मासूम चेहरे... क्या यही हमारा भविष्य है? नियम कागजों में हैं, लेकिन सड़क पर उनकी कोई मौजूदगी दिखाई नहीं देती। सबसे बड़ा सवाल स्कूल प्रबंधन पर खड़ा होता है। जिन संस्थानों के कंधों पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, वही उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अनफिट, क्षतिग्रस्त और बिना अनुमति चलने वाले वाहन किसके संरक्षण में सड़कों पर दौड़ रहे हैं? यदि कोई हादसा नहीं होता तो क्या सब कुछ ठीक मान लिया जाता है? और जब हादसा हो जाता है, तब जिम्मेदारी तय करने के नाम पर केवल जांच के आदेश क्यों रह जाते हैं? इस लापरवाही में अभिभावकों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। क्या सुविधा और समय की बचत बच्चों की जान से ज्यादा अहम हो गई है?

राजस्थान में आए दिन ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। हाल ही डीडवाना जिले में हुआ हादसा भी सिस्टम पर तमाचा ही है। लोडिंग पिकअप में ठूंस-ठूंस कर बैठाई गई 44 छात्राएं, चालक का नियंत्रण खोना और वाहन का पलटना, यह महज दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही का सीधा नतीजा है। छात्राओं का घायल होना और कुछ की हालत गंभीर होना चेतावनी है, लेकिन क्या यह चेतावनी भी पहले की तरह भुला दी जाएगी? प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। क्या परिवहन नियम सिर्फ कागजों में लागू हैं? निरीक्षण कब होता है और किस स्तर पर होता है? हादसे के बाद कार्रवाई की रस्म अदायगी कब तक चलती रहेगी? आज जरूरत है आत्ममंथन की। बच्चों की जान किसी समझौते का विषय नहीं हो सकती। स्कूल प्रबंधन, अभिभावक और प्रशासन, तीनों को जवाब देना होगा कि आखिर कब तक मासूमों को मौत के साये में स्कूल भेजा जाता रहेगा। अगर आज भी सवाल नहीं उठे, तो कल हादसों की सूची और लंबी होगी। - **महेन्द्र त्रिवेदी**
mahendra.trivedi@in.patrika.com

बुक इनसाइट

द फ्लावर बेयरर्स : आत्मसंघर्ष कथा

रेचल एलाइजा ग्रिफिथ्स की पुस्तक 'द फ्लावर बेयरर्स' एक आत्मकथा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह आत्मकथा होते हुए भी आत्मप्रदर्शन नहीं बनती, बल्कि मनुष्य की नाजुकता और टूटन को ईमानदारी से सामने रखती है। यह किताब किसी सुसंगठित जीवन-कथा की तरह आगे नहीं बढ़ती, बल्कि स्मृतियों, आघात और आत्मसंघर्ष की परतों में उतरती जाती है। इस पुस्तक में ग्रिफिथ्स निजी जीवन के सुख, शोक और भय को किसी नाटकीय ढांचे से नहीं, बल्कि बेहद संवेदनशील भाषा में दर्ज करती हैं। वे अपने अनुभवों को सजाने या उन्हें अर्थ देने की जल्दबाज़ी नहीं करतीं। लेखिका का जोर घटनाओं से अधिक उनके भीतर उठने वाली प्रतिक्रियाओं पर है। मानसिक अस्थिरता, दोस्त की आकस्मिक मृत्यु और जीवनसाथी पर हुए हिंसक हमले जैसे विषय इस आत्मकथा में गहरे व्यक्तिगत अनुभव के रूप में आते हैं। ग्रिफिथ्स की भाषा-शैली इस पुस्तक की आत्मा है। वे छोटे-छोटे वाक्यों में भी गहरी पीड़ा और प्रेम को व्यक्त कर देती हैं। उनकी लेखनी में मौन का भी महत्व है।

फैक्ट फ्रंट

कंगारू रैट : छलांग लगाने में माहिर

कंगारू रैट एक छोटा लेकिन बेहद रोचक जीव है। यह चूहों की एक प्रजाति है, इसका यह नाम इसके पिछले पैरों की बनावट और छलांग लगाकर चलने की आदत के कारण पड़ा है, जो कंगारू जैसी होती है। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमरीका के शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी टांगें और पूंछ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू से मिलती जुलती है। इसके गालों के बाहर की ओर थैलियां भी होती हैं।

इन थैलियों में ये खाने का सामान लाता है, फिर इसे अपने बिलों में इकट्ठा करता है। कंगारू रैट की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यह बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है। इसे आवश्यक पानी अपने भोजन से मिलता है, खासकर सूखे बीजों के पाचन से। इसके गुर्दे इतने सक्षम होते हैं कि यह शरीर से पानी की एक-एक बूंद बचाकर रखते हैं। यही कारण है कि यह कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी आसानी से जीवित रह पाता है। कंगारू रैट की पिछली टांगें लंबी व मजबूत होती हैं और इसकी लंबी पूंछ संतुलन बनाने में मदद करती है।

छिपी मंशा जख्म अपने पैदा किए, ठीकरा भारत पर

दहलता बलूचिस्तान, फिर पुरानी चाल पर लौटा पाक

बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के एक के बाद एक समन्वित हमलों और उसके जवाब में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में दर्जनों लोगों की मौत ने एक बार फिर पाकिस्तान की अस्थिर और विस्फोटक स्थिति को उजागर कर दिया है। ये हालात न सिर्फ पाकिस्तान, अपितु पूरे क्षेत्र की शांति के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदारी किसी और की नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान की है, जिसने वर्षों से बलूचिस्तान को एक उपनिवेश समझते हुए उसके लोगों और संसाधनों का शोषण किया और विदेशी हितों को साधने में लगा रहा।

अरुण जोशी
दक्षिण एशियाई कूटनीतिक मामलों के जानकार
@patrika.com

यह स्थिति बेहद चिंताजनक है कि बलूचिस्तान में अपने ही पैदा किए गए संकट से निपटने के बजाय पाकिस्तान ने वहां की हर गड़बड़ी का ठीकरा भारत पर फोड़ना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भारत पर उंगली उठाना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि पाकिस्तान की शरारत सिर्फ दोधारीपन तक सीमित नहीं रहती। इन्हीं आरोपों के सहारे वह कश्मीर पर अपने भारत-विरोधी नैरेटिव को जिंदा रखता है और अपनी हर हरकत को जायज ठहराने की कोशिश करता है। बलूचिस्तान में शनिवार से शुरू हुए सबसे घातक हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने के पीछे पाकिस्तान की गहरी मंशा छिपी है। यह सीमा-पार आतंकवाद की जमीन तैयार करने की उसकी पुरानी रणनीति का संकेत है। मार्च 2025 में जब बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा किया था, तब भी पाकिस्तान ने भारत पर ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगाए थे। इन आधारहीन आरोपों का भारत-विरोधी माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया।

उस समय सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने 15 अप्रैल को इस्लामाबाद में दिए अपने भाषण में दो-राष्ट्र सिद्धांत तक उछाल दिया था। इसके बाद 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया। उस कार्रवाई में उसके आतंकी ढांचे और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ था और वह संघर्ष विराम की गुहार लगाने पर मजबूर हो गया था। इसके बावजूद वह एक बार फिर उसी षड्यंत्रकारी खेल में लौट आया है। भारत के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा कि अपनी अंदरूनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

सर्दी में ठहराव व मौन समेटे स्वप्निल दुनिया

जर्मनी का हार्ज क्षेत्र

***जर्मनी** के हार्ज क्षेत्र में बर्फ से ढका यह प्राकृतिक दृश्य सर्दी की शांत और अलौकिक सुंदरता को दर्शाता है। इस तस्वीर में सफेद चादर ओढ़े दिखाई दे रहा है। मानो प्रकृति ने स्वयं को कुछ समय के लिए ठहराव और मौन में समेट लिया हो। दूर-दूर तक फैली बर्फ सूर्य की हल्की रोशनी में चमकती हुई एक स्वप्निल दुनिया रचती है, जहां हर रंग फीका पड़कर सिर्फ सफेदी की प्रधानता स्वीकार करता नजर आता है।*

दृष्टिकोण विश्व कैंसर दिवस: जागरूकता की दरकार

कैंसर रोकथाम की मुहिम में जीवनशैली बदलना भी जरूरी

कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनते ही हर किसी के जेहन में डरावनी तस्वीर सामने आती है। कैंसर विश्व भर में मृत्यु का अग्रणी कारण है एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार वर्ष 2020 में लगभग 10 मिलियन मौतें और छह में से एक मौत कैंसर के कारण हुई हैं, वहीं दुनियाभर में कैंसर के 19.2 मिलियन नए केस दर्ज किए गए हैं। बहुतायत से निदान किए जाने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों, बड़ी आंत, मलाशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर शामिल हैं।

ज्यादातर लोग कैंसर को अपनी नियति मान तकदीर को कोसते हैं जबकि इसके लिए हम स्वयं एवं हमारी जीवनशैली भी काफी हद तक जिम्मेदार है। संबंधित जोखिम कारकों से बचते हुए एवं साक्ष्य आधारित रोकथाम रणनीति को लागू करके 30 से 50 प्रतिशत तक कैंसर से बचाव किया जा सकता है। कैंसर से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्तर पर जीवन शैली में कुछ परिवर्तन कर अच्छी आदतों को अपनाना होगा। तंबाकू एवं तंबाकू से बने उत्पादों एवं शराब का सेवन न करें। फाइबर युक्त संतुलित पौष्टिक आहार के साथ शरीर के वजन को स्थिर रखने के लिए शारीरिक व्यायाम को तरजीह दें। हिपेटाइटिस और पैपिलोमा वायरस के लिए आवश्यक टीकाकरण जरूर कराएं। अल्ट्रा वॉयलेट किरिणों, रेडिएशन, घर व बाहर के वायु प्रदूषण से बचें। विधायी उपायों में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के बिक्री प्रमोशन पर नियंत्रण, उत्पादों एवं विज्ञापनों में स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी, उत्पादों में शामिल सभी हानिकारक तत्वों का विस्तृत विवरण, इन उत्पादों पर अधिक कर, बिक्री पर प्रतिबंध, सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर धूम्रपान पर रोक शामिल हैं। भारत में ज्यादातर राज्य सरकारों द्वारा बंद जगहों जैसे सिनेमा हॉल, बस, शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों में धूम्रपान निषिद्ध करने के लिए कानून लागू किए गए हैं।

डॉ. पंकज जैन
प्रोफेसर एवं फिजिशियन मेडिकल कॉलेज, कोटा
@patrika.com

कैंसर से बचाव की मुख्य व अंतिम कड़ी आमजन में इसके प्रति जागरूकता एवं समय पर स्क्रीनिंग की महत्ता को स्थापित करना है। कैंसर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही लोगों को कैंसर के जल्द निदान व उपचार के प्रति प्रेरित करना है। फिजिशियन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात चिकित्सकों को भी सचेत रहना होगा क्योंकि कैंसर का मरीज सर्वप्रथम इसी स्तर पर परामर्श लेता है। तो आइए एकजुट होते हैं, कैंसर रोकथाम की इस मुहिम में, ताकि कैंसर से होने वाली बीमारी और मृत्यु को काफी हद तक कम किया जा सके।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

आपकी बात

कोई विशेष योजना नहीं

आम बजट 2026 देश की समग्र आर्थिक स्थिति में मजबूती के लिए मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। फिर भी मध्यमवर्गीय लोगों और गरीबों के उत्थान की कोई विशेष योजना नहीं है। रोजमर्रा की चीजों की महंगाई कम करने की आवश्यकता थी। - **दिनेश मेघवाल**, उदयपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'आम बजट आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/WKoIS
इसे स्कैन करें

आज का सवाल

दिव्यांगजन को रोजगार देने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं?
ईमेल करें: edit@epatrika.com

बजट विश्लेषण रोगों की रोकथाम के बजाय इलाज को बढ़ावा देने पर ही केंद्रित है यह बजट

प्रदूषण नियंत्रण की घटती प्राथमिकता क्या बेहतर स्वास्थ्य दे पाएगी?

डॉ. विवेक एस. अग्रवाल
स्वास्थ्य एवं पर्यावरण विषयों के जानकार
@patrika.com

केंद्रीय बजट में स्टील, ऊर्जा, सीमेंट जैसे भारी उद्योगों से कार्बन इकट्ठा करने, उपयोग और भंडारण के लिए बीस हजार करोड़ रुपए का कोष स्थापित कर स्वच्छ उत्पादन को दिशा देने का प्रयास किया गया है। वहीं, नाभिकीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी बीस हजार करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है।

युवा शक्ति को समर्पित बजट में संसाधनों के समान रूप से सभी वर्गों तक बंटवारे को कर्तव्य बोध के साथ संकल्पित करते हुए हरित मिशन के मद में भी दोगुने से अधिक राशि की वृद्धि की गई है। वायु प्रदूषण को लेकर प्रकट की जा रही गंभीर चिंताओं को दरकिनार कर प्रस्तुत केंद्रीय बजट में प्रदूषण नियंत्रण प्रावधानों में गत वर्ष की अपेक्षा 16 प्रतिशत की कमी करते हुए मात्र 1091 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हालांकि संबंधित वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए गत वर्ष की अपेक्षा आठ प्रतिशत अधिक बजट रखा गया है। अब भी विडंबना यह है कि पर्यावरण के मूलभूत उद्देश्य बेहतर जीवन को इस सीमित पहल के जरिए हासिल किया जाना कठिन प्रतीत होता है। स्थापित कोष की अवधि पांच वर्ष होना उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रश्न खड़े करता है।

स्वास्थ्य समस्याओं के क्षेत्र में हुए परिवर्तन के चलते गैर संक्रामक रोग शीर्ष पर आ गए हैं, जिनके अहम कारक में से एक तेजी से फैलता प्रदूषण है। हृदय एवं फेफड़ों की बीमारियों में निरंतर विस्तार हो रहा है। बेहतर वायु कायम कर इन बीमारियों पर बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। बढ़ते गैर संक्रामक रोगों के निदान के दौरान प्लास्टिक एवं कपड़े की भूमिका को लेकर भी गहरी चिंता प्रकट की जाती रही है। हालांकि बजट प्लास्टिक नियंत्रण पर विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं करता किंतु कपड़े से हो रही बीमारियों को प्राकृतिक, सस्टेनेबल, हथकरघा वस्त्रों के विस्तार एवं उन्नयन के लिए वस्त्र संबंधी एकीकृत कार्यक्रम के फलस्वरूप सीएनजी निर्माण एक कारगर कदम के रूप में उभरकर आया है। यहां तक की छोटी मात्रा में भी कचरे का प्रसंस्करण करने में यह कारगर विधि साबित हुई है। यह रियायत प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए दूरगामी कदम साबित होगी।

इस बार के बजट में स्वास्थ्य की मद में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 1.06 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है और प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में भी गत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर लगभग 39 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य के मद में बढ़ोतरी की गई है किंतु अब भी यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत प्रावधान के लक्ष्य से आधी भी नहीं है। इतने प्रावधानों के बावजूद बजट बीमारी रोकने की जगह इलाज को बढ़ावा देने पर ही केंद्रित है। स्वास्थ्य का मुद्दा ऐसा है, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

बजट जहां विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के प्रोत्साहन का जिक्र करता है, वहीं शहरी पर्यावरणीय स्वास्थ्य इसका मुद्दा नहीं बन पा रहा है। उचित होता कि यह बजट संस्थानिक विकास के साथ बचाव के कदमों पर अधिक ध्यान दे पाता। लक्ष्य बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए, ताकि स्वस्थ जीवन जिया जा सके।

भारत ने अमरीका के साथ बहुत अच्छा व्यापार समझौता हासिल किया है, जो अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर है और इसमें कृषि तथा डेयरी क्षेत्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है।
पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री

पत्रिका फाइनेंस
@बिजनेस & वेल्थ

भारत-अमरीका ट्रेड डील 'मेड इन इंडिया' पहल के लिए बड़ी राहत है। इससे दोनों बड़े लोकतांत्रिक देशों के लोगों को फायदा मिलेगा। देश के गरीबों, मत्स्यकर्मियों, किसानों और युवाओं के लिए बड़े अवसर खोलेगा।
निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री

डबल स्ट्राइक @पत्रिका इंफोग्राफिक्स

एक हफ्ते में ही भारत ने किए 2 मेगा ट्रेड डील्स

भारत-अमरीका ट्रेड डील खेल फिर बराबरी का...

2.8% थी भारतीय उत्पादों पर औसत वेटेड टैरिफ अमरीका में 2025 से पहले, ***वहीं भारत में अमरीकी उत्पादों पर औसत टैरिफ 7.7% था***

नई दिल्ली@पत्रिका. भारत पर 18% अमरीकी टैरिफ लगने से देश अब चीन-बांग्लादेश, वियतनाम जैसे अपने निर्यात प्रतिस्पर्धियों के साथ बराबरी की स्थिति में आ गया है, कुछ मामलों में भारत को बढ़त भी हासिल होगी। अगस्त के आखिर में लागू हुए 50% टैरिफ ने कई सेक्टरों को गहरा झटका दिया था। हालांकि कुछ सेक्टर्स ने वैकल्पिक बाजारों में पकड़ बनाकर कुछ हद तक मजबूती दिखाई। जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाइल और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को अब टैरिफ घटने से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सबसे अधिक से सबसे कम...
प्रतिद्वंद्वी देशों के मुकाबले टैरिफ

देश	टैरिफ
ब्राजील	50%
चीन	34%
मैक्सिको	25%
द. कोरिया	25%
बांग्लादेश	20%
वियतनाम	20%
पाकिस्तान	19%
थाईलैंड	19%
इंडोनेशिया	19%
भारत	18%

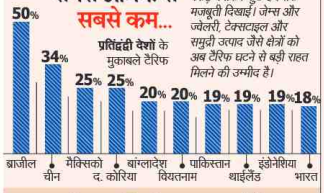

भारत से इतना निर्यात
कुल निर्यात **437.7 अरब डॉलर** (राशि अरब डॉलर में)

ईयू	अमरीका	शेष दुनिया
75.9	86.5	275.3

19.8% **हिस्सेदारी** अमरीका की भारत के कुल निर्यात में, ***देश के कुल आयात में अमरीका की हिस्सेदारी 6.3% रही 2024-25 में)***

ट्रेड डील से इन सेक्टर्स से सबसे ज्यादा लाभ

सेक्टर	टैरिफ से अमरीका को घटा निर्यात
जेम्स-ज्वैलरी	-60.1%
टेक्सटाइल	-25.2%
समुद्री उत्पाद	-21.8%
लेदर प्रोडक्ट्स	-15.5%
केमिकल्स	-9.2%
इंजीनियरिंग गुड्स	-3.6%

(सितंबर में 50% टैरिफ लगने के बाद से नवंबर के बीच घटा निर्यात, अब इन श्रम आधारित सेक्टर्स से सबसे ज्यादा लाभ होने की उम्मीद)

हालांकि इन उत्पादों पर ऊंचा रहेगा टैरिफ

उत्पाद	टैरिफ	निर्यात
स्टील	50%	2.5
एल्यु.-तांबा	50%	1.8
फर्नीचर	25%	1.50
ऑटोपार्ट्स	25%	3.9

*(इन पर ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 के तहत लगा है टैरिफ, **2024-25 में हुआ निर्यात अरब डॉलर में)***

अमरीका से ऐसे बढ़ा-घटा भारत का कारोबार
*(राशि अरब डॉलर में, * अप्रेल से दिसंबर तक के आंकड़े)*

वर्ष	ऊपरी रेखा	निचली रेखा
2020-21	51.6	28.9
2024-25	86.5	45.6
2025-26*	65.9	39.4

टैरिफ का निर्यात पर ज्यादा असर नहीं

माह	अमरीका को निर्यात	सालाना इजाफा
जुलाई	8.01	20%
अगस्त	6.86	2.4%
सितंबर	5.46	-12%
अक्टूबर	6.30	-8.6%
नवंबर	6.98	22.6%
दिसंबर	6.89	-1.83%

(निर्यात राशि अरब डॉलर में)

26.45 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस भारत का अमरीका के साथ वर्ष 2025-26 में अप्रेल से दिसंबर के बीच, ***इस दौरान 10% बढ़ा अमरीका को निर्यात ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद***

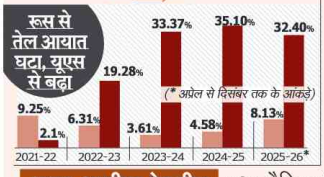

इन उत्पादों का सबसे ज्यादा निर्यात

उत्पाद	निर्यात
इलेक्ट्रिक मशीनरी	15.9
डायमंड-कलर्ड मोती	10.0
फार्मा उत्पाद	9.8
न्यूक्लियर रिएक्टर	6.7
मिनरल फ्यूल-ऑयल	4.2

(राशि अरब डॉलर में, 2024-25 के आंकड़े)

रूस से तेल आयात घटा, यूएस से बढ़ा

वर्ष		
2021-22	9.25%	2.1%
2022-23	6.31%	19.28%
2023-24	3.61%	33.37%
2024-25	4.58%	35.10%
2025-26*	8.13%	32.40%

(अप्रेल से दिसंबर तक के आंकड़े)*

9 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी सेंसेक्स 2073 अंक चढ़ा, 20% तक चढ़े अमरीका पर निर्भर स्टॉक्स, ₹12 लाख करोड़ बढ़ी बाजार पूंजी

ट्रेड डील से 7वें आसमान पर एक्सपोर्ट शेयर

खुशी से झूमा शेयर बाजार, निर्यातकों की बल्ले-बल्ले

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. भारत-अमरीका ट्रेड डील की घोषणा से शेयर बाजार झूम उठा। इस खबर से भारतीय शेयर बाजार की चाल ही बदल गई। ट्रंप की ओर से भारत पर प्रभावी टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा से ग्लोबल और घरेलू बाजारों में जबरदस्त पॉजिटिव माहौल बन गया। बाजार की धमाकेदार ओपनिंग हुई। पहली बार सेंसेक्स 4200 अंक की तेजी के साथ खुला। निफ्टी ने भी पहली बार 1220 अंकों की तेजी के साथ ओपन हुआ। बैंक निफ्टी तो 61,764 के रेकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। जेम्स-ज्वैलरी, टेक्सटाइल, सी-फूड, केमिकल्स सहित कई सेक्टर्स के एक्सपोर्ट आधारित शेयरों में अपर सर्किट लग गया। एक्सपोर्ट स्टॉक्स 20% तक चढ़ गए।

मंगलवार को सेंसेक्स 4164 अंक की तेजी के साथ 85,323 अंक पर खुला देखते ही देखते 85,871 पर पहुंच गया। अंत में 2073 अंक की तेजी के साथ 83,739 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 639 अंक यानी 2.55% की तेजी के साथ 25,727 के स्तर पर बंद हुआ। यह 9 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी है। इस तेजी से कंपनियों की बाजार पूंजी एक दिन में ही 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत बैंकिंग और अदाणी स्टॉक्स में जोरदार उछाल से बाजार को सपोर्ट मिला। साथ ही रुपए में 1.4% से ज्यादा मजबूती और विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने भी बाजार को सपोर्ट दिया। बड़े शेयरों में विदेशी निवेशकों के लौटने की उम्मीद और भारत-अमरीका के बीच एनर्जी ट्रेड लिंक मजबूत होने से अदाणी-अंबानी के शेयर चढ़े।

टैरिफ पर शेयर बाजार का हाल

25% टैरिफ के बाद: 76,617 (2 अप्रेल) → 73,137 (7 अप्रेल)
(2 अप्रेल को ट्रंप ने ***भारत पर 26% टैरिफ लगाया, जिससे 5 दिन में 4.5% टूटा***)

25% पेनल्टी टैरिफ की घोषणा पर: 81,435 (31 जुलाई) → 79,857 (8 अगस्त)
(1 अगस्त को ट्रंप ने रूस से तेल खरीद पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, ***जिससे एक हफ्ते में सेंसेक्स 2% गिरा***)

50% टैरिफ लागू होने पर: 81,635 (27 अगस्त) → 79,809 (29 अगस्त)
(दो दिन में ही सेंसेक्स 1826 अंक यानी 2.23% लुढ़क गया, हालांकि ***इसके बाद बाजार एक महीने में 4% चढ़ गया***)

बाजार में लौटी बहार...

इंडेक्स	तेजी
सेंसेक्स	2.54%
निफ्टी 50	2.55%
मिडकैप	2.92%
स्मॉलकैप	2.94%
माइक्रोकैप	3.72%

सी-फूड शेयर भी आसमान पर

शेयर	तेजी
अवंती फीड्स	20%
एपेक्स फ्रोजन	20%
वाटर बेस	20%
कोस्टल कॉर्प	05%
जील एक्वा	10.6%
किंग्स इंफ्रा	7.64%
एसेक्स मरीन	7.86%

इन सेक्टर्स में सबसे अधिक तेजी

इंडेक्स	उछले
निफ्टी बैंक	2.43%
निफ्टी ऑटो	2.81%
निफ्टी मेटल	2.87%
फाइनेंशियल्स	3.20%
निफ्टी फार्मा	3.02%
केमिकल्स	3.84%
कं. ड्यूरेबल्स	3.05%
निफ्टी रियल्टी	4.79%

5,426 करोड़ के शेयर खरीदे विदेशी निवेशकों ने, यह एफआइआइ की ***4 महीने की सबसे बड़ी खरीदारी***

(**2072 अंक** यानी 2.54% चढ़ा सेंसेक्स, ***निफ्टी 20 के साथ स्मॉल-मिडकैप में भी 3% तक आई तेजी)***

रुपया 2018 के बाद सबसे तेजी से चढ़ा: डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 126 पैसे यानी 1.48% मजबूत होकर 90.27 के स्तर पर बंद हुआ, जो सोमवार को 91.53 पर बंद हुआ था। यह रुपए में वर्ष 2018 के बाद की सबसे बड़ी एकदिवसीय तेजी है। यह रुपए का तीन सप्ताह का उच्च स्तर है। बीते 12 साल में ऐसी तेजी सिर्फ 10 बार दर्ज हुई हैं। यह 18 दिसंबर 2018 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी तेजी है, जब रुपए 1.62% चढ़ा था। विदेशी निवेशकों की वापसी की उम्मीद से रुपए चढ़ा।

दौड़ पड़े अदाणी-अंबानी के शेयर: अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। समूह की लिस्टेड कंपनियों के शेयर 10% तक चढ़ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 3.35% की तेजी आई।

क्या कह रहे दिग्गज

साझा विकास का रास्ता
टैरिफ घटने से भारत-अमरीका के रणनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे। निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा। यह डील दोनों देशों के लिए साझा विकास का रास्ता तैयार करती है। - **कुमार मंगलम बिड़ला,** उद्योगपति

'इंडिया-फर्स्ट' सोच
पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व और 'इंडिया-फर्स्ट' सोच की वजह से भारत अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ा रहा है। यह समझौता दिखाता है कि भारत वैश्विक आर्थिक फैसलों में आत्मविश्वास के साथ अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। - **संजीव गोयनका,** उद्योगपति

देश पर भरोसा बढ़ेगा
ट्रेड डील ने भारतीय बाजारों से अनिश्चितता की तलवार हटा दी है। रुपया, शेयर बाजार को लेकर भरोसा बढ़ेगा। भुगतान संतुलन सुधरेगा। विदेशी निवेश और बाजार वैल्यूएशन को भी समर्थन मिलेगा। -**नीलेश शाह,** एमडी, कोटक एएमसी

रणनीतिक बढ़त मिलेगी
वेनेजुएला का कच्चा तेल बेहद भारी ग्रेड का है, जिसे कई देश प्रोसेस नहीं कर पाते। पर देश की रिफाइनरियां इसे प्रोसेस करने में सक्षम हैं। इससे भारत को छूट, रणनीतिक बढ़त मिलेगी। **आशीष चौहान,** चेयरमैन, एनएसई

इ्यूटी कट ग्लोबल ब्रैंड्स भारत की ओर शिफ्ट हो रहे

टैरिफ में कटौती से टेक्सटाइल निर्यात डबल डिजिट में बढ़ने की उम्मीद

36.61 अरब डॉलर का टेक्सटाइल-अपैरल निर्यात 2024-25 में रहा भारत का, अमरीका की हिस्सेदारी 10 अरब डॉलर से ज्यादा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. भारत-यूएस ट्रेड डील से एक बार टेक्सटाइल (कपड़ा उद्योग) और अपैरल सेक्टर (परिधान उद्योग) की आंखें चमक रही हैं। इस डील में टैरिफ में राहत मिलने से बाजार तक बेहतर पहुंच होने की उम्मीद है, इससे एक्सपोर्ट ग्रोथ डबल डिजिट में बढ़ सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा अपैरल मार्केट है। यहां से करीब एक-तिहाई गारमेंट निर्यात होता है।

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि टैरिफ राहत से सोर्सिंग के फैसले बदल सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा निटवियर, होम टेक्सटाइल्स और कॉटन गारमेंट्स जैसी प्राइस-सेंसिटिव चीजों को राहत मिलने की संभावना है।

8.37% *हिस्सेदारी भारत के कुल निर्यात में टेक्सटाइल सेक्टर की, जो पिछले साल 6.32% थी*

टेक्सटाइल शेयरों का जलवा

शेयर	तेजी
गोकलदास एक्सपोर्ट	20%
वेल्सपुन लिविंग	20%
इंडोकाउंट	20%
केपीआर मिल्स	15.25%
एसपी अपैरल	13.83%
ट्राइडेंट	11.40%
पर्ल ग्लोबल	11.25%

इसलिए आई तेजी: टैरिफ की मार टेक्सटाइल शेयरों पर सबसे ज्यादा पड़ी थी। अब टैरिफ 50% से घटकर 18% होने से भारत को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले लागत में 2% की फायदा मिलेगा।

इसलिए होगा भारत को फायदा
घरेलू हिंसी की वजह से बांग्लादेश का रेडीमेड कपड़े का निर्यात बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दबाव में है। राजनीतिक अस्थिरता, लेबर की दिक्कत और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं ने फैक्ट्रियों को प्रभावित किया है, जिसके चलते शिपमेंट में देरी हो रही है। वहीं वियतनाम अभी भी अपैरल निर्यात में बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है। वियतनाम यार्न और फैब्रिक के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर रहता है। ऐसे में टैरिफ से बढ़ी लागत को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इससे भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ा मौकी बन रहा है।

रिपोर्ट... घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट

ट्रेड डील से इफेक्टिव टैरिफ 35% से घट 12-23% संभव

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. भारत-अमरीका के बीच हुए ट्रेड डील से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलने के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म्स का कहना है कि इस डील के बाद अमरीका सहित ग्लोबल कंपनियां फिर से चाइना प्लस वन स्ट्रैटजी के तहत भारत का रुख कर सकती हैं।

भारत-अमरीकी ट्रेड डील पर बैंक ऑफ अमरीका सिक्योरिटीज (बोफा) का कहना है कि टैरिफ घटकर 18% होने से भारतीय उत्पादों पर इफेक्टिव टैरिफ 35% से घटकर 12-23% संभव है। इसके चलते भारत के एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कॉम्पिटीटिव हो सकते हैं।

चीन प्लस वन थीम हावी होगी: सिटी बैंक
सिटी बैंक का कहना है कि ईयू और यूएस के साथ ट्रेड डील के बाद अनिश्चितता खत्म हुई है। भारत में ग्रोथ घटने का रिस्क कम हुआ है। एफडीआइ निवेश में जोरदार उछाल आ सकता है। अन्य देशों के मुकाबले भारत पर टैरिफ कम है। ऐसे में चीन प्लस वन थीम हावी हो सकती है।

तेजी का ट्रिगर: एसएंडपी के मुताबिक, ट्रेड डील लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव है। इससे मेक इन इंडिया थीम को सबसे बड़ा फायदा होगा। डाटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को फायदा होगा। बाजार पहले से लाइट है। ऐसे में डील तेजी का ट्रिगर बन सकती है।

हल्दी-जीरा को लाभ

भारतीय मसालों का जायका होगा तेज

नई दिल्ली@ पत्रिका. ट्रेड डील का भारतीय मसालों के कारोबार पर सकारात्मक असर रहा। टैरिफ घटने से भारतीय मसालों का अमरीका को निर्यात बढ़ सकता है। इस डील से अब ग्वार गम के साथ ही हल्दी, धनिया, जीरा जैसे मसाले, चावल, सोया खली के निर्यात को लाभ होगा। जिंस विश्लेषक रवि शंकर पांडे ने कहा कि ट्रेड डील से ग्वार गम को काफी लाभ होने वाला है। आईग्रेन इंडिया में निदेशक राहुल चौहान ने बताया कि ट्रेड डील की खबर से वायदा और हाजिर बाजार में जीरा, हल्दी, धनिया,मिर्च आदि जिंसों की कीमतों प्रति क्विंटल 135 से 415 रुपए तक की तेजी देखने को मिली। ट्रेड डील से इंपोर्ट की लागत घटने से कई प्रोडक्ट्स पर सीधा असर पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में दालें, डेयरी उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड जैसे सामान सस्ते हो सकते हैं।

राहत अनिश्चितता खत्म, फिर मिलेगी मजबूती

जेम्स-ज्वैलरी सेक्टर में लौटी उम्मीद, दूसरे देशों से एफटीए से भी फायदा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. करीब छह महीने से जारी अनिश्चितता के बाद भारत-अमरीका व्यापार समझौते ने देश के रत्न एवं आभूषण उद्योग को बड़ी राहत दी है। अमरीका जेम्स एंड ज्वैलरी उद्योग का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहां से उद्योग की कुल बिक्री का 30% हिस्सा आता है। ऊंचे टैरिफ के चलते चालू वित्त वर्ष के दौरान अमरीका को जेम्स-ज्वैलरी निर्यात 44.42%घटकर 3.86 अरब डॉलर रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 6.95 अरब डॉलर था। दिसंबर 2025 में तो निर्यात में सालाना आधार पर 50.44% की गिरावट दर्ज की गई। अब टैरिफ कम होने से भारतीय ज्वैलरी चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले अमरीका में सस्ती हो जाएगी, जिससे निर्यात फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। इससे मंगलवार को ज्वैलरी स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आई।

जेम्स-ज्वैलरी स्टॉक में लगे चार चांद

शेयर	तेजी
टाइटन	3.22%
कल्याण ज्वैलर्स	4.79%
राजेश एक्सपोर्ट	5%
त्रिभुनवदास झवेरी	7.54%
मोतीसंस ज्वैल्स	9.23%
वैभव ग्लोबल	9.38%
गोल्डियम इंटरनेशनल	20%

50% टैरिफ से हुआ नुकसान

उत्पाद	निर्यात घटा	ट्रेड लॉस
कट डायमंड	74.3%	82.90
गोल्ड डायमंड ज्वैलरी	49.1%	22.39
गोल्ड ज्वैलरी	85.6%	12.21
नॉन-इंडस्ट्रियल हीरे	-91.6%	15.60
अन्य जैवलरी	-62.1%	2.41

सितंबर-नवंबर में **₹12,250 करोड़** ट्रेड लॉस

उद्योग में अब भरोसा लौटा:
उद्योग को अब ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड समेत अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से भी राहत की उम्मीद है। जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अनुसार भारत के नए व्यापार समझौते आने वाले समय में नए बाजार खोलेंगे, जिससे निर्यात बढ़ेगा।

अमरीकी नौसेना ने मार गिराया यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ता ईरानी ड्रोन

वाशिंगटन. अरब सागर में तैनात विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहे ईरान के शहीद-139 ड्रोन को अमरीकी नौसेना के एफ-35सी लड़ाकू विमान ने मार गिराया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी कि ड्रोन आक्रामक तरीके से अस्पष्ट इरादे के साथ आगे बढ़ रहा था और चेतावनियों के बावजूद नहीं रुका। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के दक्षिणी तट से करीब 800 किमी दूर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में था।

भारत-अमरीका ट्रेड डील 50% टैरिफ की मार झेल रहे एक-तिहाई भारतीय निर्यात को मिलेगी संजीवनी...

48.2 अरब डॉलर के निर्यात को मिलेगी राहत, बढ़ेगा निर्यात

नई दिल्ली@पत्रिका. भारत-अमरीका के बीच व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी 50% टैरिफ का मार झेल रहे एक-तिहाई भारत निर्यात को संजीवनी मिलने की उम्मीद है। इस समझौते के बाद अमरीका जाने वाले भारत के करीब 48.2 अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ कम होकर 18% जाएगा। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मिलेगा, जहां रोजगार बड़ी संख्या में जुड़ा होता है।

8.3 **अरब डॉलर** के निर्यात पर अब भी 25% या अधिक टैरिफ लागू रहेग, ये शुल्क अमरीका के ट्रेड एक्सपैंशन ***एक्ट की धारा 232 के तहत लगाए गए हैं, जो नहीं हटेगा***

इन्हें ज्यादा फायदा

सेक्टर	अमरीका को निर्यात
कपड़ा	11
रत्न-आभूषण	10
समुद्री उत्पाद	2.7
रसायन	4.2
फुटवियर	1.1

(2024-25 में निर्यात अरब डॉलर में)

टैरिफ के बावजूद इनका बढ़ा निर्यात

उत्पाद	बढ़ोतरी
इलेक्ट्रॉनिक्स	90%
स्मार्टफोन	217%
पर्सनल कंप्यूटर	400%

30% घटा था निर्यात सितंबर-नवंबर के बीच अमरीका को 19 अरब डॉलर के निर्यात में 6 अरब डॉलर ऐसा था, जिसमें टैरिफ बढ़ने से 30% से अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। टैक्स कम होने से इन उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा।

इन पर पड़ी थी मार
ऊंचे टैरिफ ने भारत के कृषि और खाद्य निर्यात को लगभग शून्य पर ला खड़ा किया था। पिछले साल की तुलना में बासमती चावल का निर्यात गिरकर शून्य हो गया, जो पहले 83 मिलियन डॉलर के करीब था। पॉम्फ्रेट मछली, मक्का और सूखे पास्ता जैसे उत्पादों के निर्यात में भी 70% से अधिक की गिरावट आई। सर्दियों के कपड़ों, जैसे ऊनी जैकेट और ब्लेजर की मांग भी 35% कम रही क्योंकि टैक्स की वजह से कीमतें बढ़ गईं।

पेज एक का शेष

इस बार...
पुजारी आशीष गुरु ने बताया कि जिस तरह से कोई दूल्हा बाने बैठता है, उसी तरह भगवान महाकाल को 9 दिन का बाना बैठाया जाता है।
भद्रा का साया बेअसर: पं. डब्बावाला ने बताया कि भगवान शिव कालों के काल हैं, इसलिए भद्रा का साया उनकी पूजा में बाधक नहीं बन सकता। बाबा महाकाल तो स्वयं कालों के भी काल हैं। इसलिए उनकी पूजा के चार प्रहर होते हैं। भद्रा का साया उनकी पूजा में निषिद्ध नहीं माना जा सकता।

भारत मजबूत...
ये प्रगति भारत की विदेश व्यापार नीति की परिपक्वता दर्शाती है। अमरीका से ट्रेड डील से भारत की स्थिति और सुदृढ होगी।

3. कृषि जैसे समझौते के कोई खतरे भी हैं?
भारत ने ट्रेड डील में हमेशा कृषि, डेयरी एवं मत्स्य क्षेत्रों के हितों की रक्षा की है और अमरीकी डील में भी ऐसा ही हुआ होगा। यह राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील हैं, इसलिए कोई जोखिम नहीं लेगा।

4. क्या रूसी तेल खरीद बंद होगी?
वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में रूस की हिस्सेदारी 10% है। भारत रूसी तेल खरीद रोकता है तो आयात बिल बढ़ेगा। भारत को संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा।

5. ट्रंप के जीरो टैरिफ के दावों का क्या?
भारत अमरीकी वस्तुओं के लिए अपने बाजार को सीमित एवं चरणबद्ध रूप से खोल सकता है। लेकिन कृषि-डेयरी जैसे क्षेत्रों के संरक्षण से समझौता नहीं करना चाहिए। सामान्य जीरो टैरिफ मुश्किल है।

राहुल के...
इसके चलते कांग्रेस के आठ सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने राहुल की अगुवाई में मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। इससे पहले सुबह सदन जुटते ही विपक्षी सांसदों ने अमरीका से हुई ट्रेड डील और राहुल गांधी को नहीं बोलने पर हंगामा किया। दूसरी बार कार्यवाही शुरू होने पर राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ के आर्टिकल को सदन के पटल पर रखा तोपक्ष-विपक्ष में काफी देर बहस हुई। राहुल ने कहा विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल के समर्थन में तीन विपक्षी सांसदों ने भी बोलने से इनकार कर दिया।

बाजार खिलखिलाया...
उन्होंने कहा कि जैसे ही डील पर तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर पूरी तरह मुहर लग जाएगी,भारत और अमरीका की टीमें जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की में सारी डिटेल शेयर की जाएंगी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि उन्हें देश की तरक्की से कोई लेना-देना नहीं, वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

इंडस्ट्रियल गुड्स, मेवे, फल पर जीरो टैरिफ: ग्रीर—अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि ग्रीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत कृषि क्षेत्र पर संरक्षण बनाए रखेगा जिस पर अमरीका आगे प्रयास करता रहेगा। उन्होंने दावा किया कि भारत अमरीकी इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ 13.5% से शून्य करेगा। इसके अलावा मेवे, वाइन, स्पिरिट, फल, सब्जियां आदि कई चीजों पर टैरिफ शून्य होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल आयात कम किया हैं और अमरीका इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। भारत के पास तेल आपूर्ति में विविधता लाने के कई विकल्प हैं। ग्रीर ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने पर काम चल रहा है।

जीडीपी में 20-40 अंकों का सुधार: सीईए— केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी.अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अमरीका से ट्रेड डील के कारण अगले साल जीडीपी अनुमान में 20 से 40 अंक तक सुधार हो सकता है। जीडीपी अगले साल अनुमानित 6.8-7.2% के बजाय 7.4% हो सकती है।

उच्च शिक्षा में नेतृत्व संकट गहराया, टीएनओयू के अधिनियम और विनियमों के अनुसार कार्यकाल का विस्तार संभव नहीं

तमिलनाडु के 15 विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद खाली

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

चेन्नई. राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में गंभीर संकट गहरा गया है। राज्य की 22 में से 15 सरकारी विश्वविद्यालयों में इस समय कुलपति नहीं हैं। जनवरी में तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी (टीएनओयू) के कुलपति एस. अरुमुगम का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह संख्या बढ़ी है। उनके साथ ही मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय की कुलपति के. कला का कार्यकाल भी समाप्त हुआ, राज्यपाल ने 20 विश्वविद्यालयों के चांसलर होने के नाते, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्हें एक वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया। टीएनओयू के अधिनियम और विनियमों के अनुसार कुलपति के कार्यकाल का विस्तार संभव नहीं है।

दो वर्षों से राज्यपाल आर.एन. रवि और राज्य सरकार के बीच कुलपति नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। यह मामला अभी न्यायालय में लंबित है, जिससे विश्वविद्यालयों में नेतृत्व का संकट बढ़ता जा रहा है। उच्च शिक्षा सचिव पी. शंकर कई राज्य विश्वविद्यालयों की समितियों के संयोजक हैं और कुलपतियों की अनुपस्थिति में प्रशासन संभाल रहे हैं। इस कारण उन पर कार्यभार अधिक हो गया है।

इसी वजह से, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी (टीएनओयू) की समिति के लिए कानून विभाग सचिव एस. जॉर्ज अलेक्जेंडर को संयोजक नियुक्त किया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह नियुक्ति पी शंकर के अत्यधिक व्यस्त होने के कारण की गई है। अब एस जॉर्ज अलेक्जेंडर टीएनओयू समिति की जिम्मेदारी संभालेंगे।

...तो वर्ष के अंत तक 20 विश्वविद्यालयों में नहीं होंगे कुलपति

शिक्षाविदों का कहना है कि यदि यह गतिरोध जारी रहा तो वर्ष के अंत तक 20 विश्वविद्यालयों में भी कुलपति नहीं रहेंगे। मद्रास विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने बताया, 'संयोजक समिति की बैठक हर तिमाही में एक बार होती है। बीते दो वर्षों में उच्च शिक्षा विभाग में सात सचिव बदले हैं, जिससे हर नए सचिव को विषय समझने में समय लगता है।'

पूर्व कुलपति एस.पी. त्यागराजन का कहना है कि कुलपति की अनुपस्थिति केवल प्रतीकात्मक समस्या नहीं है, यह विश्वविद्यालय के संचालन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। शिक्षकों की नियुक्ति, शोध स्वीकृति, धनराशि का उपयोग और अकादमिक सुधार सब ठप पड़ जाते हैं। अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति इ. बालागुरुस्वामी ने कहा, 'विश्वविद्यालयों को बिना नेतृत्व के चलाना छात्रों के लिए घातक है और राज्य की उच्च शिक्षा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।'

कई विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम संशोधन और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य लंबित हैं। आंकड़ों के अनुसार, राज्य विश्वविद्यालयों में लगभग 50 प्रतिशत शिक्षण पद खाली हैं। नेतृत्व संकट के कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों की रैंकिंग भी प्रभावित हो रही है।

रजनीकांत ने सफाईकर्मी को भेंट किया सोने का हार

चेन्नई @ पत्रिका. अभिनेता रजनीकांत ने मंगलवार को सफाईकर्मी पद्मा को उसके ईमानदार कार्य के लिए अपने निवास पर बुलाकर सोने का हार देकर सम्मानित किया। इस महीने की शुरुआत में टी नगर में सफाई के दौरान पद्मा को सड़क पर एक लावारिस बैग मिला था जिसमें 45 सवरन सोने के आभूषण थे। पद्मा ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और जेवरातों से भरा बैग पांडी बाजार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच के बाद जेवरात उनके असली मालिक को लौटा दिए। पद्मा के इस ईमानदार कृत्य की विभिन्न वर्गों में खूब सराहना हुई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी उसे सम्मानित करते हुए 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। रजनीकांत ने पद्मा से मिलकर उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की। सूत्रों के अनुसार इससे पहले रजनीकांत ने मदुरै के अपने एक प्रशंसक को भी सोने का हार भेंट किया था। यह प्रशंसक रजनी शेखर अपने परिवार के साथ अभिनेता से मिला था।

मिड-डे मील खाने के बाद बीदर में 50 छात्र बीमार, 20 भर्ती

बेंगलूरु @ पत्रिका. बीदर जिले के औराद तालुक के जमलापुर गांव स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को मिड-डे मील खाने के बाद 50 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। बेचैनी की शिकायत के बाद सभी छात्रों को निगरानी के लिए औराद तालुक सरकारी अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाए गए छात्रों में से 20 को पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत होने पर भर्ती किया गया, जबकि शेष छात्रों को प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच के बाद छुट्टी दे दी गई। तालुक स्वास्थ्य अधिकारी गायत्री ने बताया कि भर्ती सभी छात्रों की हालत स्थिर है। मिड-डे मील में परोसे गए भोजन की जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर औराद तहसीलदार महेश पाटिल तथा मिड-डे मील योजना के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और छात्रों के स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि सभी छात्र खतरे से बाहर हैं और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है।

गुजरात को बेस्ट स्टेट फॉर एविएशन इकोसिस्टम का पुरस्कार

अहमदाबाद @ पत्रिका. गुजरात ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर गत दिनों आयोजित विंग्स इंडिया 2026 सम्मेलन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुजरात को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ सिविल एविएशन इकोसिस्टम पुरस्कार से सम्मानित किया।

गुजरात के नागर विमानन आयुक्त के एल बचाणी ने बताया कि यह पुरस्कार राज्य के विमानन क्षेत्र में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा एयरक्राफ्ट लीजिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है। इस श्रेणी में गुजरात के साथ तेलंगाना और उत्तराखंड भी संयुक्त विजेता रहे। उनके अनुसार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने विमानन क्षेत्र को आर्थिक विकास का इंजन बनाने और अंतिम व्यक्ति तक हवाई कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह सम्मान विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाने की राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले भी गुजरात को विंग्स इंडिया 2022 तथा विंग्स इंडिया 2024 भी अवार्ड मिल चुके हैं। यह तीसरी बार है जब गुजरात को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है।

पर्यटकों के लिए आधुनिक नौकाएं जल्द कन्याकुमारी पहुंचेंगी

कन्याकुमारी में 3 नई यात्री नौकाओं का निर्माण कार्य अंतिम चरण में

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

चेन्नई. कन्याकुमारी में पर्यटकों के लिए तीन आधुनिक यात्री नौकाओं के संचालन के लिए निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। सार्वजनिक निर्माण, राजमार्ग और लघु बंदरगाह मंत्री इ. वी. वेलु ने गोवा के सिनर्जी शिपयार्ड का दौरा कर इन नौकाओं के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने 31 दिसम्बर 2024 को तिरुवल्लुवर प्रतिमा की रजत जयंती पर घोषणा की थी कि कन्याकुमारी में तीन नई यात्री नौकाएं खरीदी जाएंगी, जिससे पर्यटक तीन समुद्रों के संगम से प्रतिमा तक आसानी से पहुंच सकें। इन नौकाओं का नाम पेरुनतलैवर कामराजर, मार्शल नेसमणि और जी.यू. पोप के नाम पर रखा जाएगा।

तमिलनाडु समुद्री बोर्ड के निधियों से इन नौकाओं के लिए निर्माण कार्य गोवा में चल रहा है। निरीक्षण के दौरान मंत्री इ. वी. वेलु के साथ राजमार्ग और लघु बंदरगाह विभाग के सचिव डॉ. आर. सेल्वराज, तमिलनाडु समुद्री बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी.एन. वेंकटेश, राज्य पोर्ट अधिकारी कैप्टन एम. अन्बरसन और विशेष अधिकारी (तकनीकी) आर. चंद्रशेखर उपस्थित रहे। पेरुनतलैवर कामराजर नामक नौका का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसकी समुद्री परीक्षण प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। फरवरी 2026 के अंत तक यह नौका तमिलनाडु समुद्री बोर्ड को कन्याकुमारी बंदरगाह पर सौंप दी जाएगी। मंत्री ने शेष दो नौकाओं, मार्शल नेसमणि और जी.यू. पोप के शेष कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने किया विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित

रक्त शोधन और पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन अवसर पर सीएम स्टालिन।

चेन्नई @ पत्रिका. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उत्तरी चेन्नई विकास परियोजना के तहत कोलातूर विधानसभा क्षेत्र के अगरम, जगन्नाथन स्ट्रीट पर 11.74 करोड़ रुपए की लागत से बने रक्त शोधन और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। इसी परिसर में निर्मित 6 उचित मूल्य दुकानों का भी उद्घाटन किया गया। रेटेरी जंक्शन के पास 4.98 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किए गए कोलातूर लेकफ्रंट पार्क को जनता को समर्पित किया गया।

रक्त शोधन और पुनर्वास केंद्र में कुल पांच मंजिलें हैं, जिसमें भूतल भी शामिल है। इस केंद्र में पार्किंग, रिसेप्शन, लिफ्ट, फिजियोथेरेपी, कृत्रिम अंग केंद्र, 15 डायलिसिस बेड, चिकित्सा परामर्श कक्ष, स्टाफ चेंजिंग रूम, डाइनिंग एरिया और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य दुकानों का उद्घाटन कर स्थानीय लोगों को राशन वितरण भी किया।

कोलातूर लेकफ्रंट पार्क में वॉकिंग पाथ, बच्चों के खेल क्षेत्र, संगीत पार्क, बैठने की सुविधाएं, ड्रेसिंग रूम, आधुनिक शौचालय, पेयजल, कंट्रोल रूम और झूला जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय नागरिकों को बेहतर जीवनशैली प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने पेरेम्बूर, पेपर मिल्स रोड जंक्शन पर 310 खुले ट्रांसफार्मर संरचनाओं को सुरक्षित कवर में बदलने की 39 करोड़ रुपए की परियोजना का भी शिलान्यास किया। उन्होंने रक्त शोधन केंद्र में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन, स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमणयन, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष, महापौर आर. प्रिया सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, कार्यवाही स्थगित

आबकारी मंत्री के खिलाफ जांच, बर्खास्तगी पर अड़ा विपक्ष

विधानसभा अध्यक्ष खादर।

मंत्री तिम्मापुर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बेंगलूरु. विधानसभा में मंगलवार को आबकारी मंत्री आर. बी. तिम्मापुर के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराने और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा रहा। इस मुद्दे पर विपक्ष के तीखे तेवरों के कारण सदन में काफी देर तक हंगामा चलता रहा।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक और विधायक मंजूनाथ ने नियम 69 के तहत इस मामले को उठाते हुए आरोप लगाया कि आबकारी विभाग में लाइसेंस जारी करने और तबादलों के लिए खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग में बड़े पैमाने पर हो रही रिश्वतखोरी के कारण ही आबकारी राजस्व में भारी गिरावट आई है। इस कथित लूट के लिए आबकारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार हैं।

अशोक ने कहा कि इस मामले से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है और लोकायुक्त में शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। इसके बावजूद मंत्री का पद पर बने रहना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा कि आखिर किस नैतिकता के आधार पर तिम्मापुर को अब तक मंत्रिमंडल में रखा गया है। क्या सरकार इस कथित भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है?

कथित घोटाले का ऑडियो आया सामने

उन्होंने दावा किया कि आबकारी विभाग के कथित घोटाले से जुड़ा एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें मंत्री तिम्मापुर और उनके बेटे पर आरोप लगाए गए हैं। अशोक ने कहा कि राज्य में 14,229 शराब आपूर्ति करने वाली दुकानें हैं, जबकि इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं हैं। हर दुकान से हर महीने रिश्वत वसूली जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आबकारी विभाग में तबादलों के लिए बाकायदा रेट तय हैं। अशोक ने कहा कि पूर्व में भाजपा सरकार के दौरान जब मंत्रियों पर तबादलों में रिश्वत लेने के आरोप लगे थे, तो उनसे इस्तीफा लिया गया था। लेकिन अब इतने गंभीर आरोप सामने आने के बावजूद आबकारी मंत्री तिम्मापुर का पद पर बने रहना कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर को उजागर करता है। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी रही।

अशोक ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो नेता वीबी-जी-राम-जी योजना का विरोध कर रहे हैं, वे महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस स्वयं गांधी के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है। अशोक ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग में नए परमिट जारी करने और पुराने परमिट के नवीनीकरण के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत ली जा रही है।

अमानवीय: वीडियो वायरल, बेड़ियों में इलाज ने जताई मानवता की कमी

सुरक्षा पर उठे सवाल: बेड़ियों में बंधे गुजरात के मछुआरे की पाकिस्तान जेल में हुई मौत!

दिनेश भारद्वाज
patrika.com

सूरत. गुजरात के गिरसोमनाथ जिले के उना तहसील के चीखली गांव निवासी भगाभाई परबतभाई बामनिया का 16 जनवरी 2026 को कराची की जेल में उपचार के दौरान निधन हो गया। चार साल पहले, 18 फरवरी 2022 को, अरब सागर में मछली पकड़ते समय उन्हें पाकिस्तान की मरीन सिक्योरिटी एजेंसी ने हिरासत में ले लिया था। उनके ऊपर लगे आरोपों की सजा अवधि पूरी हो चुकी थी, फिर भी रिहाई नहीं हुई। इस घटना ने समुद्री मछुआरों की सुरक्षा और विदेशों में कैद भारतीय नागरिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गत महीने ही भारत-पाकिस्तान के बीच 2008 के कॉन्स्युलर एक्सेस समझौते के तहत कैदियों की सूची साझा की गई थी। इसमें भारत ने 199 मछुआरों और 58 अन्य नागरिकों की जानकारी दी थी, जिनमें से 167 की सजा अवधि पूरी हो चुकी थी। बीमार और सजा पूरी कर चुके कैदियों की जल्द रिहाई की मांग भी की गई थी। पिछले वर्ष फरवरी में पाकिस्तान ने 22 बीमार भारतीय कैदियों को रिहा किया था।

वायरल वीडियो ने उजागर की अमानवीयता: मृत्यु से पहले भगाभाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें वे अस्पताल के बेड पर लेटे दिखाई दे रहे थे, जहां किसी पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी से बातचीत कर रहे थे। उनकी पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई थीं।

यह दृश्य मानवाधिकारों और कैदी अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करता है। मछुआरा संगठनों ने इसे अमानवीय बताया है और परिवार सहित लोगों में गहरा आक्रोश है।

परिवार की टूटी उम्मीदें, पत्नी पीहर गई

भगाभाई के छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनकी पत्नी कुछ समय पहले मायके चली गई, जबकि बुजुर्ग मां आज भी बेटे के लौटने का इंतजार कर रही हैं। समुद्र श्रमिक सुरक्षा संघ के प्रमुख बालूभाई सोचा ने कहा, 'अगर समय पर बीमार कैदियों की रिहाई होती, तो शायद भगाभाई आज परिवार के साथ होते।' भगाभाई का शव 6 फरवरी को अहमदाबाद होते हुए पैतृक गांव पहुंचेगा।

मछुआरा संगठनों और सांसद की चिंता

दमण-दीव के सांसद उमेश पटेल ने इसे अमानवीय घटनाक्रम बताते हुए कहा कि जेल में उपचार के दौरान बेड़ियों में बांधना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पाकिस्तान मामलों के संयुक्त सचिव के सामने पूरी स्थिति रखी है।

सूरत मनपा का ड्राफ्ट बजट

अब तक का सबसे बड़ा 10,593 करोड़ का बजट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सूरत. सूरत महानगरपालिका ने वर्ष 2026-27 के लिए 10,593 करोड़ का ड्राफ्ट बजट पेश कर शहर के विकास को नई दिशा देने का दावा किया है। मनपा आयुक्त एम. नागराजन द्वारा पेश यह बजट न सिर्फ आकार में अब तक का सबसे बड़ा है, बल्कि बिना किसी कर-दर बढ़ोतरी के तैयार किया गया प्रगतिशील दस्तावेज भी है। वर्ष 2025-26 के 10,004 करोड़ के बजट की तुलना में इसमें 589 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बजट का सबसे अहम पहलू 5073 करोड़ का पूंजीगत खर्च है, जो आने वाले वर्षों में सूरत के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, जल-निकासी, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं को मजबूती देगा।

बजट में 257 करोड़ रुपए का अनुमानित रेवेन्यू सरप्लस भी दर्शाया गया है, जिससे मनपा की वित्तीय सेहत मजबूत होने का संकेत मिलता है। जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश का प्रावधान किया गया है। नए शामिल क्षेत्रों में लगातार पानी आपूर्ति के लिए कुल 2632 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में से वर्ष 2026-27 में 388 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

परिवहन, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान

पुराने शहर और नए विस्तार क्षेत्रों में ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ाने, एसटीपी और एसपीएस निर्माण के लिए भी सैकड़ों करोड़ का प्रावधान है। परिवहन और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 600 इलेक्ट्रिक बसें, नए बीआरटीएस कॉरिडोर, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और नदी-खाड़ी पुलों की योजना शामिल है। सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सीसी रोड, माइक्रो-सर्फेसिंग और प्लास्टिक वेस्ट से रीसर्फेसिंग पर भी फोकस किया गया है।

भाजयुमो की ओर से 'चाकरी चाय बांग्ला' हस्ताक्षर अभियान

चाकरी चाय बांग्ला हस्ताक्षर अभियान के दौरान मौजूद पदाधिकारी।

कोलकाता. @ पत्रिका. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा (भाजयुमो) उत्तर कलकत्ता जिला द्वारा मंगलवार को एस्प्लानेड चौराहे पर 'चाकरी चाय बांग्ला' हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि शिल्प और उद्योग नहीं होने के कारण यहां के बेरोजगार युवा काम के सिलसिले में भटक रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वाम मोर्चा के शासन को तोड़कर परिवर्तन की आवाज पर आने वाली ममता सरकार को पंद्रह साल हो गए लेकिन बंगाल में अभी भी कोई भी उद्योग विकसित नहीं हुआ है। इनकी नीतियों के कारण कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बंगाल में अपना उद्योग लगाना नहीं चाहती हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए पाँच लाख पोस्टकार्ड मुख्यमंत्री को भेज कर उनसे रोजगार की मांग की जाएगी। इस मौके पर भारतीय जनता युवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनील खान, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, कलकत्ता उत्तर जिला अध्यक्ष तमोघ्न घोष, पार्षदा मीना देवी पुरोहित, विजय ओझा भाजयुमो उत्तर जिला अध्यक्ष सुबोध दास, काली खटीक सहित अन्य कई नेता, पदाधिकारो और कार्यकर्ता मौजूद थे।

सीपीआइ करेगी अधिक सीटों का दावा

डीएमके गठबंधन वार्ता: सीटों की मांग पर सीपीआइ सक्रिय

वेलूर @ पत्रिका. विधानसभा चुनाव करीब आते ही डीएमके ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे और गठबंधन पर औपचारिक वार्ता शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, डीएमके बुधवार से इन वार्ताओं की शुरुआत कर सकती है। इसी क्रम में सीपीआइ राज्य सचिव एम. वीरापांडियन ने कहा कि उनकी पार्टी डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में अधिक सीटों की मांग करेगी।

वीरापांडियन ने स्पष्ट किया क्या कम्युनिस्टों को केवल विधायकों की संख्या से ही आंका जा सकता है? हमारे पास अधिक सीटों की मांग करने का नैतिक अधिकार है और हम ऐसा करेंगे।" पार्टी की राज्य समिति शीघ्र बैठक कर सीटों के बंटवारे की संभावनाओं पर चर्चा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय समिति की बैठक के बाद ही लिया जाएगा।

सीपीआइ के सम्मेलन में ग्यारह प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें पंचमी भूमि की वापसी, दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, ऑनर किलिंग की रोकथाम और शैक्षणिक संस्थानों में अत्याचार रोकने के लिए विशेष कानून बनाने जैसे मुद्दे शामिल थे। वीरापांडियन ने मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन से तस्माक कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप की भी अपील की। उन्होंने सेवा नियमित करने, समय-मान वेतन और पेंशन लाभ जैसी मांगों को पूरा करने पर जोर दिया। राज्य में अन्नाद्रमुक और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। जिसमें पट्टाली मक्कल कच्ची और तमिल मनीला कांग्रेस समेत अन्य दल शामिल हैं।

विश्व कैंसर दिवस पर विशेष | मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 4572 शामिल, राजस्थान के 2678, यूपी के 1094, बिहार के 288 पहुंचे

जीसीआरआइ: एक वर्ष में कैंसर के 27000 नए मरीज, 9000 अन्य राज्यों के

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जीसीआरआइ

जीसीआरआइ के आंकड़े (वर्ष 2025)

26810 नए मरीजों का रजिस्ट्रेशन	50130 कीमोथेरापी
9,140 अन्य राज्यों से आए मरीज	6333 पेट-सीटी स्कैन
2.59 लाख ओपीडी विजिट्स	50000 से अधिक मरीजों की नो-कोस्ट स्क्रीनिंग
17800 से अधिक सर्जरी	118 मामलों की शुरुआती पहचान
50 बोनमैरो ट्रांसप्लांट	

अहमदाबाद. शहर के सिविल मेडिसिटी कैंपस स्थित गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीसीआरआइ) में एक वर्ष में कैंसर के 26810 नए मरीज पहुंचे। इनमें नौ हजार से अधिक (9140) गुजरात के बाहर से आए। विश्व कैंसर दिवस 2026 के अवसर पर जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में गुजरात के बाहर से आने वालों में सबसे अधिक मरीजों में मध्य प्रदेश के 4572 शामिल हैं।

इसके बाद राजस्थान के 2678, उत्तर प्रदेश के 1094, महाराष्ट्र के 279 और बिहार के 288 पहुंचे। ये आंकड़े बताते हैं कि जीसीआरआइ अब नेशनल रेफरल सेंटर के रूप में स्थापित हो चुका है, जहां देश के लगभग सभी राज्यों से कैंसर मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

6 महीनों में 50 रोबोटिक सर्जरी : जीसीआरआइ ने कैंसर उपचार में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर नया मानक स्थापित किया है। केवल छह महीनों में 50 रोबोटिक असिस्टेड कैंसर सर्जरी हुई। गत तीन वर्षों में 40 हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरापी (एचआइपीईसी) प्रक्रियाएं भी हुई। एचआइपीईसी पेट में फैले कैंसर के लिए अत्यंत जटिल लेकिन प्रभावी उपचार है।

पेट-सीटी स्कैन जांच में उल्लेखनीय वृद्धि : 2021 में 1813 पेट-सीटी स्कैन जांच हुई थी, जो 2025 में बढ़कर 6333 तक पहुंच गई। यह तकनीक शरीर के भीतर कैंसर की सटीक पहचान और उपचार योजना बनाने में मदद करती है।

ढाई लाख से अधिक ओपीडी केस : 2025 में संस्थान में 2.59 लाख से अधिक ओपीडी विजिट दर्ज हुई। इस दौरान 17800 से अधिक सर्जरी, 50 बोनमैरो ट्रांसप्लांट और 50130 से अधिक कीमोथेरेपी की गई। साथ ही 5852 रेडिएशन ट्रीटमेंट और 24.6 लाख से अधिक लैब जांच भी की गई।

समय रहते कैंसर की पहचान जरूर

संस्थान का लक्ष्य केवल इलाज करना नहीं बल्कि समय रहते पहचान और रोकथाम को भी प्राथमिकता देना है। यही कारण है कि जीसीआरआइ आज देशभर के मरीजों के लिए विश्वसनीय केंद्र बन चुका है। संस्थान ने कैंसर उपचार में तकनीकी और मानवीय दोनों स्तरों पर नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।

डॉ. शशांक पंड्या, निदेशक, जीसीआरआइ

नो-कोस्ट स्क्रीनिंग और सामुदायिक कैंप : अक्टूबर 2021 से शुरू हुए नो-कोस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ओपीडी में अब तक 50000 से अधिक लोगों की जांच हुई, जिनमें 118 मामलों की पहचान शुरुआती चरण में ही हो गई। 2025 में पूरे गुजरात में 110 सामुदायिक कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 12000 से अधिक लोग शामिल हुए।

आज 500 कैंसर सर्वाइवर्स का सम्मान : विश्व कैंसर दिवस 2026 के अवसर पर बुधवार को जीसीआरआइ में 10 वर्ष से अधिक समय से कैंसर-मुक्त 500 सर्वाइवर्स के लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे यह सशक्त संदेश देगा कि समय पर और सही इलाज से कैंसर पर विजय संभव है।

ऑरेंज इकोनॉमी को महत्व

इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने ऑरेंज इकोनॉमी को जिस तरह महत्व दिया है, वह उसके उभार को देखते हुए स्वाभाविक है. ऑरेंज इकोनॉमी दरअसल क्रिएटिव इकोनॉमी है. नारंगी रंग को रचनात्मकता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है. जब कला, संस्कृति, तकनीक, रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा मिलकर पैसा और रोजगार पैदा करते हैं, तो उसे ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं. फिल्म बनाना, संगीत, फैशन डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, आर्किटेक्चर और पेंटिंग जैसी चीजें इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं. लंबे समय तक इन्हें हॉबी या शौक माना जाता था. लेकिन बजट में वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि यह रचनात्मकता अब भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा इंजन बनने वाली है. सरकार का लक्ष्य भारत को केवल तकनीकी दिग्गज नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिव हब बनाना भी है. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो स्वीकार किया ही कि देश का एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उन्होंने इसे समर्थन देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना भी बजट में पेश की. सरकार मुंबई स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (आइआइसीटी) के साथ मिलकर एक बड़ी परियोजना की शुरुआत करने जा रही है. इसके तहत देश के 15,000 माध्यमिक स्कूलों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स तैयार की जायेंगी. इसके अलावा, 500 कॉलेजों में भी ऐसी एडवांस्ड लैब्स बनायी जायेंगी. इससे बचपन से ही छात्र-छात्राओं को एनिमेशन, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे कौशल सीखने का अवसर मिलेगा. सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस क्षेत्र में 20 लाख पेशेवर तैयार करना है. देश में डिजाइनिंग उद्योग के विस्तार को देखते हुए वित्त मंत्री ने पूर्वी भारत में नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन की स्थापना करने का भी प्रस्ताव रखा है. इसका उद्देश्य डिजाइन से जुड़ी प्रतिभाओं को निखारना है. अपने देश में प्रतिभाएं तो बहुत हैं, लेकिन सही प्रशिक्षण और ढांचागत सुविधाओं का अभाव है. जबकि आज डिजिटल कंटेंट की मांग बहुत तेज हो गयी है. ओटीटी प्लेटफॉर्म, मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया ने कंटेंट को एक बड़ा उद्योग बना दिया है. सरकार का लक्ष्य यह है कि भारतीय क्रिएटर्स मौलिक कहानियां तथा किरदार गढ़ें, ताकि उनका कंटेंट और कॉपीराइट भारत के पास रहे और उससे मोटी कमाई हो सके. सरकार की यह पहल देश की रचनात्मक प्रतिभाओं को वैश्विक पहचान दिलाने और युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर खोलने की दिशा में बड़ा कदम है.

रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों-कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा बजट में की गयी है. यह पहल देश की रचनात्मक प्रतिभाओं को वैश्विक पहचान की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी.

इयू से रक्षा समझौते का लाभ समुद्री सुरक्षा में

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
anandkmrai@gmail.com

भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए व्यापार समझौते में रक्षा समझौते पर कम बात हुई है. इस समझौते में समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाइब्रिड खतरों, अंतरिक्ष सुरक्षा, रक्षा उद्योग सहयोग और क्षमता निर्माण जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं. हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक गतिविधियां दिखाती हैं कि यह साझेदारी केवल कागजी नहीं है, बल्कि व्यावहारिक और संचालन आधारित सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग समकालीन भू-राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण, किंतु अपेक्षाकृत कम चर्चित, परिवर्तनों में से एक है. हाल ही में नयी दिल्ली में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में अधिकांश ध्यान व्यापार समझौते और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित रहा, लेकिन इसी दौरान एक और उतना ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया. यह था भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर. यह समझौता न केवल दोनों पक्षों के बीच बढ़ते भरोसे को दर्शाता है, बल्कि उस अस्थिर और अनिश्चित वैश्विक सुरक्षा वातावरण के प्रति साझा प्रतिक्रिया भी है, जिसमें पारंपरिक व्यवस्थाएं और स्थापित नियम लगातार कमजोर पड़ रहे हैं.

वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था इन दिनों गहरे दबाव में है. क्षेत्रीय संघर्षों के साथ-साथ बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा और बदलती प्राथमिकताओं ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर बना दिया है. अमेरिकी रवैये के कारण यूरोप की सुरक्षा चिंताएं फिर उभरकर सामने आयी हैं. नाटो सहयोगियों पर लगातार बढ़ता अमेरिकी दबाव, कि वे अपनी रक्षा जिम्मेदारियां स्वयं उठायें, और वाशिंगटन की अप्रत्याशित विदेश नीति ने यूरोप को अपनी रणनीतिक निर्भरता पर पुनर्विचार के लिए मजबूर किया है. ऐसे समय में, भारत एक ऐसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में उभरता है, जो न तो किसी सैन्य गुट का हिस्सा है और न ही जिसकी रणनीतिक सोच किसी एक शक्ति पर निर्भर है. भारत के लिए यह साझेदारी यूरोपीय संघ द्वारा उसकी बदलती वैश्विक भूमिका की औपचारिक स्वीकृति है. लंबे समय तक भारत-यूरोपीय संघ संबंध मुख्यतः व्यापार और आर्थिक सहयोग तक सीमित रहे. राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग अपेक्षाकृत हाशिये पर रहा. नयी रक्षा साझेदारी इस प्रवृत्ति से स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है. शांति, सुरक्षा और रक्षा को द्विपक्षीय संबंधों का केंद्रीय स्तंभ बनाकर दोनों पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि आज उनके हित समुद्री सुरक्षा, वैश्विक साझा संसाधनों की रक्षा, आतंकवाद से मुकाबले और उभरती प्रौद्योगिकियों के नियमन जैसे क्षेत्रों में तेजी से एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं. इसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाइब्रिड खतरों, अंतरिक्ष सुरक्षा, रक्षा उद्योग सहयोग और क्षमता निर्माण जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं.

हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक गतिविधियां दिखाती हैं कि यह साझेदारी व्यावहारिक और संचालन आधारित सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है. भारत और यूरोपीय संघ ने नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र केंद्रित बहुपक्षीय प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है. जब एकतरफा रवैया, दबाव की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून की चयनात्मक व्याख्या बढ़ रही है, तब यह साझा दृष्टिकोण विशेष महत्व रखता है. यद्यपि भारत और यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण सभी मुद्दों पर पूरी तरह समान नहीं हैं, फिर भी संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और संस्थागत वैधता को लेकर दोनों की रणनीतिक सोच में स्पष्ट सामंजस्य है. रक्षा औद्योगिक सहयोग इस समझौते का शायद सबसे परिवर्तनकारी पहलू है. यूरोप की पुनःसशस्त्रीकरण की प्रक्रिया और रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की उसकी जरूरत ने भारतीय रक्षा उद्योग के लिए नये अवसर खोल दिये हैं. भारत-यूरोपीय संघ रक्षा उद्योग मंच की स्थापना का निर्णय, जिसमें सरकारें पर्यवेक्षक की भूमिका में होंगी, एक व्यावहारिक और भविष्यदर्शी कदम है. इससे रक्षा कंपनियों के बीच प्रत्यक्ष साझेदारी, संयुक्त उत्पादन और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा. भारत के लिए यह केवल बाजार तक पहुंच का प्रश्न नहीं है, बल्कि वैश्विक रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर भी है. भारतीय रक्षा उद्योग, जो हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है, यूरोपीय रक्षा आवश्यकताएं पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इससे न केवल 'मेक इन इंडिया' और रक्षा निर्यात रणनीति को बल मिलेगा, यूरोपीय संघ को भी सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. यह साझेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परस्पर लाभ पर आधारित है और किसी एक पक्ष को दूसरे पर हावी नहीं होने देती.

वार्षिक भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा संवाद की स्थापना से यह सुनिश्चित होगा कि सहयोग केवल घोषणाओं तक सीमित न रहे. नियमित समीक्षा, विषयगत परामर्श और संवाद के माध्यम से इस साझेदारी को वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप ढाला जा सकेगा. अतीत में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों की एक बड़ी कमजोरी क्रियान्वयन की रही है, यह नया ढांचा वह कमी दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती सुरक्षा गतिशीलता के संदर्भ में यह साझेदारी और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है. यूरोपीय संघ की इस क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी और इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में शामिल होना भारत की दृष्टि के अनुरूप है. भारत के लिए यूरोपीय उपस्थिति किसी एक शक्ति पर निर्भरता कम करती है, जबकि यूरोपीय संघ के लिए भारत एक ऐसा साझेदार है, जो क्षेत्रीय वास्तविकताओं को गहराई से समझता है. यह साझेदारी वैश्विक साझेदारियों के पुनर्संतुलन को भी दर्शाती है. भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और यूरोप भी ट्रांस-अटलांटिक संबंधों से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों ही अब अधिक रणनीतिक स्वतंत्रता चाहते हैं. भारत-यूरोपीय संघ रक्षा साझेदारी किसी मौजूदा गठबंधन के विरुद्ध नहीं है, बल्कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में विकल्प और लचीलापन प्रदान करती है.

कुल मिलाकर, भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा और रक्षा साझेदारी एक शांत लेकिन निर्णायक रणनीतिक परिवर्तन का संकेत है. यह रक्षा सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों के केंद्र में लाती है, वैश्विक अस्थिरता के दौर में रणनीतिक दृष्टियों का सामंजस्य स्थापित करती है और औद्योगिक सहयोग के नये द्वार खोलती है. जब पारंपरिक सुरक्षा गारंटी कम भरोसेमंद होती दिख रही है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था दबाव में है, तब भारत और यूरोपीय संघ ने सावधानी के बजाय साझेदारी का रास्ता चुना है. इसकी सफलता अंततः क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी, लेकिन इसकी दिशा और मंशा स्पष्ट है- एक अधिक संतुलित, स्थिर और बहुध्रुवीय सुरक्षा व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बीस साबित हुई भाजपा

उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार
uchaturvedi8@gmail.com

रणनीतिक लिहाज से देखें, तो महाराष्ट्र में बीजेपी सभी दलों पर एक बार फिर बीस पड़ती नजर आ रही है. उसने सुनेत्रा पवार को अपने खेमे में लाकर एक तीर से दो निशाने साध लिये हैं. एनसीपी की ओर से निश्चिंतता हासिल कर ली है, शरद पवार को एक बार फिर किनारे रखने में सफल हुई है और अपने लिए खतरा बनने की शरद की आशंकाओं को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है.

राजनीति जज्बात से नहीं, हालात के हिसाब से चलती है. महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण इसका उदाहरण है. सुनेत्रा के आंसू अभी सूखे भी नहीं, पति अजित पवार के निधन के शोक से उबरना तो दूर की बात है. फिर भी उन्होंने सियासी तकाजे को ही प्राथमिकता दी और महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया. पर प्रश्न यह है कि सुनेत्रा की ताजपोशी से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? आखिर क्या वजह रही कि सुनेत्रा ने आनन-फानन में शपथ ले ली. महाराष्ट्र के राजभवन में जनवरी महीने के आखिरी दिन जो राजनीतिक इतिहास रचा गया, उसकी कहानी किसने लिखी थी.

महाराष्ट्र में भले ही शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली हो, पर राज्य की राजनीति के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार ही हैं. यह बात छुपी हुई नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के बीच सुलह और एकीकरण की बात चल रही थी. पर अजित के न रहने से समीकरण बदल गये. अजित के साथ गये अहम नेताओं- प्रफुल्ल पटेल, आरआर पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं की आशंकाएं बढ़ गयीं. उन्हें डर था कि यदि विलय हुआ, तो शरद पवार का पार्टी पर नियंत्रण बढ़ जायेगा. इसके चलते सुप्रिया सुले की पार्टी पर पकड़ बढ़ जायेगी. सुप्रिया के नियंत्रण में इन नेताओं का काम करना असहज होता. प्रफुल्ल कभी शरद पवार के बेहद नजदीकी होते थे. अजित के साथ जाकर एक तरह से उन्होंने शरद पवार के साथ दगाबाजी ही की है. उन्हें ज्यादा आशंका थी कि विलय के बाद पार्टी पर पकड़ होने के चलते शरद के बहाने सुप्रिया का चाबुक उन पर चल सकता है. पर यदि पार्टी अलग रहती है और सुनेत्रा के हाथ कमान रहती है, तो इन नेताओं की सियासी सेहत बनी और बची रह सकती है. इसी कारण अजित के निधन के चलते हुए आधिकारिक शोक की मियाद खत्म होते ही प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नेता सक्रिय हो गये. विधायक दल की बैठक बुलायी गयी और सुनेत्रा को तत्काल उसका नेता चुनकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार कर लिया गया. शरद पवार भले ही इस सियासी पटकथा का लेखक सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को मानते हों, पर महाराष्ट्र के सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि असल में यह पटकथा राज्य की बीजेपी ने लिखी है. पटेल और तटकरे जैसे नेताओं ने सिर्फ इसे अमल में लाने में भूमिका निभायी है.

यदि सुनेत्रा शपथ नहीं लेतीं, तो क्या बीजेपी की सियासी सेहत गड़बड़ा सकती थी? क्योंकि राज्य में बीजेपी के 132 और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के 57 विधायक हैं. राज्य में बहुमत के लिए महज 145 सीटें चाहिए होती हैं. इस लिहाज से देखें, तो बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को कोई खतरा नहीं होने जा रहा था. अजित समेत एनसीपी के 41 विधायक पिछले चुनाव में चुने गये हैं. पर बीजेपी की चिंता दूसरी है. शरद पवार की राजनीतिक स्थिति भले ही ठीक न हो, पर जैसे ही दोनों एनसीपी का विलय होता, शरद ताकतवर हो जाते और बीजेपी के लिए नयी सिरदर्दी खड़ी हो जाती. वे शिवसेना के गुटों को भी एक करने की कोशिश कर सकते थे. भले ही यह सोच कल्पना लग रही हो, पर एकबार स्वीकार कर लें कि ऐसा होता, तो महाराष्ट्र की राजनीति कैसी होती. महाराष्ट्र में जिला परिषदों के चुनाव हो रहे हैं. पहले विधानसभा और बाद में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी को सफलता नहीं मिली. अजित पवार के न रहने के चलते कांग्रेस को सक्रिय होना चाहिए था. अजित बेशक सत्ता में थे, लेकिन उन्हें विपक्षी खेमे के लिए अब भी हसरत भरी निगाह से ताकतवर नेता के रूप में देखा जा रहा था. अजित के न रहने से विपक्षी नेतृत्व के लिए आसमान खुल गया है. शरद के बाहर जाने के बाद से ही कांग्रेस राज्य में कमजोर हुई है. सुप्रिया सुले का नेतृत्व ऐसा नहीं है कि वह राज्यव्यापी प्रभाव हासिल कर पायें. ऐसे माहौल में कांग्रेस को अपने ताकतवर नेतृत्व को स्थानीय स्तर पर आगे लाना चाहिए था. पर वह ऐसा करती नहीं दिख रही.

रणनीतिक लिहाज से देखें, तो महाराष्ट्र में बीजेपी सभी दलों पर एक बार फिर बीस पड़ती नजर आ रही है. उसने सुनेत्रा पवार को अपने खेमे में लाकर एक तीर से दो निशाने साध लिये हैं. एनसीपी की ओर से निश्चिंतता हासिल कर ली है, शरद पवार को एक बार फिर किनारे रखने में सफल हुई है और अपने लिए खतरा बनने की शरद की आशंकाओं को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है. मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी है. इसी कारण केंद्रीय सत्ता के बाद सबसे प्रभावशाली महाराष्ट्र की सत्ता मानी जाती है. महाराष्ट्र की सत्ता पर पकड़ देश की आर्थिक ताकतों की नब्ज पर पकड़ बनाती है. बीजेपी अपनी इस पकड़ को कमजोर होते नहीं देखना चाहती. इसलिए उसने सुनेत्रा को साधने में देर नहीं लगायी. सुनेत्रा के साथ से एकनाथ शिंदे के लिए महायुति से बाहर निकलने की सोचना या बीजेपी पर दबाव बढ़ाने का मौका खत्म हो जाता है. कुछ ऐसी ही स्थिति शिंदे के साथ के चलते सुनेत्रा की भी रहेगी. बीजेपी सुनेत्रा के जरिये शिंदे को संतुलित करेगी, तो शिंदे के जरिये सुनेत्रा को काबू में रखेगी.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

शेख हसीना के बाद बांग्लादेश नया पाकिस्तान बनने की राह पर

शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद से भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, और कई द्विपक्षीय मामलों में दोनों देशों के बीच जैसे को तैसा रवैया देखने को मिल रहा है. यह सब दोनों देशों द्वारा संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों के बावजूद हो रहा है. शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बयानबाजी चरम पर पहुंच गयी है. न केवल दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे को संदेश भेजने के लिए उच्चायुक्तों को तलब किया गया, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए वीजा केंद्रों को भी बंद किया जा रहा है. हसीना सरकार के पतन के बाद ढाका स्थित भारतीय वीजा केंद्र और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र पर भीड़ ने हमला किया था. हादी की हत्या के बाद ढाका में भारतीय उच्चायोग तक लोगों का एक समूह मार्च करता हुआ पहुंचा, चटगांव में भारत के सहायक उच्चायोग पर हमला हुआ, वहीं दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने दीपू दास की लिंचिंग के विरोध में एक छोटा प्रदर्शन हुआ. असल में बांग्लादेश के इस्लामी चरमपंथी हमेशा से पाकिस्तान के प्रति अपनी निकटता दिखाते और भारत को बांग्लादेश के लिए खतरा बताते रहे हैं. अवामी लीग के खिलाफ भड़के गुस्से को सुनियोजित तरीके से भारत की तरफ मोड़ा जा रहा है. बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल में इस तरह की तेजी पहली बार नहीं देखी गयी है. मुजीब के शासन के अंतिम समय में भी भारत विरोधी भावना को पाकिस्तान समर्थक तत्वों के साथ-साथ उन लोगों ने भी हवा दी थी जो मुजीब के शासन को भारत समर्थक मानते थे. मुजीब की हत्या के बाद सैन्य सरकार को मजबूत करने के लिए इस भावना को और बढ़ावा दिया गया. गौरतलब है कि अगस्त, 2024 में अंतरिम सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सभी तौर-तरीकों को अपना लिया है, जिनमें शत्रुतापूर्ण, बयानबाजी से भरा और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाला रवैया शामिल है.

THE KATHMANDU POST
WITHOUT FEAR OR FAVOUR

-स्मृति एस पट्टनायक

बोधि वृक्ष

सांस की सरल लय

जैसे-जैसे हमारी जागरूकता में तीव्रता और पैनापन आने लगता है, एक बात जिसके बारे में हम स्वाभाविक रूप से सबसे पहले जागरूक होते हैं, वह है सांस. यह आश्चर्यजनक है कि कैसे अधिकतर लोग इसके बारे में जागरूक हुए बिना ही जीते रहते हैं. एक बार जब आप सांस के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो यह एक अद्भुत प्रक्रिया बन जाती है. यदि आप थोड़े ज्यादा सचेत हो जाते हैं, तो आपकी सांस स्वाभाविक रूप से आपकी जागरूकता में आ जायेगी. आप सांस की सरल लय को अनदेखा नहीं कर सकते, जो बिना रुके चलती रहती है. अधिकतर लोगों का ध्यान अपनी सांस की ओर तभी जाता है जब उनकी श्वास नलियों में ऐंठन आ जाती है, या सांस ज्यादा तेजी से चलती है. वे अपनी सामान्य सांस को अनदेखा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें ध्यान देने की कमी एक गंभीर समस्या है. सांस पर ध्यान देना वैसे तो एक जबरन प्रयास है. परंतु यह आपको सचेत करने का एक तरीका भी है. महत्वपूर्ण चीज अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि अपनी जागरूकता के स्तर को इतना ऊंचा उठाना है कि आप स्वाभाविक रूप से अपनी सांस के प्रति सचेत हो जायें. सांस लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया है. मूल रूप से देखें तो जब भी आप सांस लेते या छोड़ते हैं, तब आपके शरीर में स्पंदन होता है. जब तक आप अपने मनोवैज्ञानिक ढांचे में पूरी तरह मगन हैं, तभी तक आप का ध्यान सांस पर नहीं होता. यदि आप अपनी भावनाओं या विचारों में पूरी तरह नहीं खोये हैं, और बस शांति से बैठे हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप का ध्यान अपनी सांस की प्रक्रिया पर न जाये. किसी चीज को अपनी जागरूकता में लाना कोई काम नहीं है. इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता. वास्तव में, सांस बहुत बड़ी चीज है, यह बात आपको तब तक पता नहीं चलती जब तक आप इसे खो नहीं देते. अगर आप आराम से बैठें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी सांस के प्रति सचेत न हों. आप यदि अपनी सांस के साथ रहें, तो यह आपको एक बड़ी संभावना की ओर ले जा सकती है.

-सद्गुरु जग्गी वासुदेव

विश्व कैंसर दिवस विशेष

पर्यावरण प्रदूषण भी है कैंसर की वजह

कैंसर केवल एक बीमारी नहीं है, यह समाज, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है. भारत जैसे विशाल और युवा देश में इसका बढ़ता प्रभाव चिंताजनक है, क्योंकि यहां कैंसर के मामले हर वर्ष नये रिकॉर्ड बना रहे हैं. वर्ष 2022 में देश में लगभग 14 लाख, 61 हजार नये कैंसर मामले सामने आये. विशेषज्ञों का आकलन है कि इस साल तक यह संख्या 15 लाख से भी अधिक हो सकती है. राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर नौ में से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने का खतरा है. कैंसर से होने वाली मौतों का आंकड़ा और भी भयावह तस्वीर पेश करता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में लगभग नौ लाख, 16 हजार लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई. बीते एक दशक में यह संख्या तेजी से बढ़ी है.

भारत में कैंसर का बोझ सभी जगह एक समान नहीं है. कुछ राज्यों में स्थिति कहीं अधिक गंभीर है. कैंसर के मामलों के हिसाब से, प्रति एक लाख की आबादी पर, केरल, मिजोरम और आंध्र प्रदेश शीर्ष पर हैं. शहरी क्षेत्रों में जहां जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां प्रमुख कारण हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में देर से जांच, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं और जागरूकता की कमी स्थिति को और जटिल बना रही है. कैंसर के प्रकारों पर नजर डालें, तो महिलाओं में स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सबसे अधिक पाये जाते हैं, जबकि पुरुषों में फेफड़ों, मुंह और ग्रासनली के कैंसर प्रमुख हैं. बच्चों में रक्त से जुड़े कैंसर के मामले चिंताजनक रूप से सामने आ रहे हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि इन रोगों के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं, जिनमें तंबाकू का सेवन सबसे बड़ा जोखिम कारक है. भारत में लगभग 27 प्रतिशत कैंसर मामलों का सीधा संबंध तंबाकू से है. इसके अतिरिक्त, असंतुलित खानपान, शारीरिक गतिविधियों में कमी, बढ़ता मोटापा और शराब-धूम्रपान का सेवन भी कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं. पर्यावरण प्रदूषण एक और बड़ा कारण बनकर उभरा है.

देवेंद्रराज सुथार
टिप्पणीकार
devendrakavi1@gmail.com

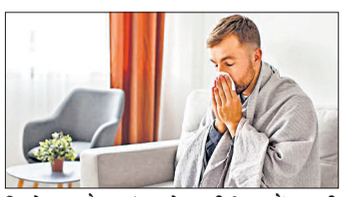

यह गौरतलब है कि कैंसर का प्रभाव केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आर्थिक भी होता है. इलाज की लागत अक्सर लाखों रुपये तक पहुंच जाती है, जिससे मध्यम और गरीब परिवारों पर भारी बोझ पड़ता है. यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब रोग की पहचान देर से होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग आधे कैंसर के मामलों को रोका जा सकता है, यदि लोग समय रहते जीवनशैली में बदलाव करें. तंबाकू और शराब से दूरी, संतुलित और पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जैसे सरल कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं. समय पर जांच और स्क्रीनिंग भी अत्यंत आवश्यक है.

आपके पत्र

नहीं सुधर रहा पाकिस्तान का रवैया

भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया कभी भी ठीक नहीं रहा है. धर्म के नाम पर राजनीति करनेवाला पाक भारत में आतंकियों की घुसपैठ करा कर हमेशा अशांत करने का प्रयास करता रहा है. हालांकि, भारत ने पिछले साल इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था. लेकिन, पाक अब भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि वह आतंकियों को पनाह देता है. इतना ही नहीं पाकिस्तान के अंदर ट्रैनिंग कैंप भी चलाये जाते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को बेनकाब करने में काफी हद तक सफलता पायी है. लेकिन, अमेरिका की शह पर वह हवा में है.

संजय कुमार, समस्तीपुर

महंगाई रोकने के लिए कुछ नहीं हुआ

आम बजट 2026-27 से आम लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई से राहत मिलेगी. साथ ही बेहतर टैक्स स्लैब और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की भी उम्मीद थी. लेकिन इस बार के आम बजट में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस बात नहीं की गयी. वहीं, टैक्स देनेवालों के लिए भी कुछ नहीं था. हालांकि, एक्सप्रेस वे, उद्योग व इन्फ्रास्टक्चर के लिए इस बजट में कई घोषणाएं की गयी हैं. इससे विकसित भारत के निर्माण में मदद मिलेगी. हालांकि, किसानों के लिए खास नहीं हुआ है.

कुमार गौरव, मधुबनी

> यह बजट समृद्ध बिहार के संकल्प को जमीन पर उतारने वाला है. इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृषि, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार व महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गयी है.
> -लेशी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री

23701.18 करोड़ का होगा ग्रामीण विकास विभाग का बजट. ग्रामीण क्षेत्रों में दोगुना रोजगार, दोगुनी आय सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 2026-27 में कई योजनाओं का संचालन किया जायेगा.

छूटे घरों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

ग्रामीण वार्डों में सर्वे के बाद छूटे हुए टोलों के लिए स्वीकृत 27,693 जलापूर्ति योजनाओं में से 4,010 नयी योजनाओं में काम प्रारंभ किया जायेगा और 18,432 निर्माणाधीन योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा.

जल संसाधन विभाग

नवादा और बिहारशरीफ को पीने के लिए मिलेगा गंगा का पानी

राज्य में जल-जीवन-हरियाली अभियान में पेयजल के लिए नवादा और बिहारशरीफ शहर को गंगा जल का पानी मिलेगा. इसके लिए 1,110.27 करोड़ रुपये से मधुबन जलाशय का निर्माण हो रहा है. वहीं औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम शहरों को सोन नदी का पानी पीने के लिए मिलेगा. इसके लिए 1,347.32 करोड़ रुपये की लागत से काम हो रहा है.

- 198.58 करोड़ रुपये की लागत से भभुआ और मोहनिया शहरों के लिए दुर्गावती जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने का काम प्रगति में है.
- 2026-27 के लिए जल संसाधन विभाग का बजट 7127.35 करोड़ रुपये है.
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 6,282.32 करोड़ से कोशी-मेची लिंक काम काम शुरू हुआ
- बांका और मुंगेर जिला में बाढ़ के दौरान में गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ और खड़गपुर जलाशय में भेजा जायेगा.

लघु जल संसाधन

लघु जल संसाधन विभाग में जल-जीवन-हरियाली अभियान में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 163 योजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी दी गयी है. इस पर काम होने से ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार हो रहा है. आहर-पइनों और तालाबों, पोखरों के मेढ़ पर वृक्षारोपण से हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है. यह जानकारी बजट में दी गयी है.

निजी नलकूप योजना

- मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप कुल 35,000 अनुदान के तहत निजी नलकूप लगाये गये.
- 1,75,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है.
- 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक सात योजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी दी गयी है.
- इन योजनाओं से कुल 3730 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा बेहतर होगी. साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर होगा.

योजना व गैर योजना का बजट

डेयरी, मत्स्य एवं पशु विभाग

पशुपालन से जुड़े कार्यों पर खर्च होंगे 1915.97 करोड़ रुपये

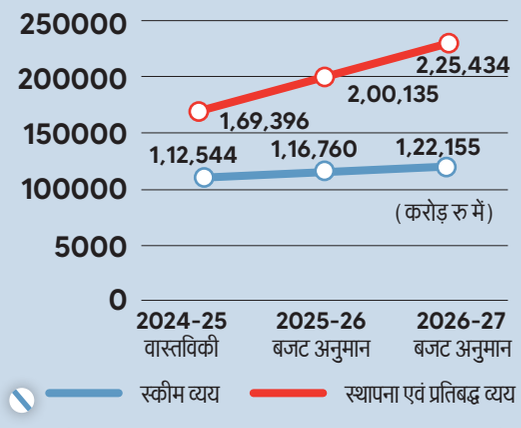

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट 1915.97 करोड़ रुपये होगा. इसमें से 1250 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं पर खर्च किये जायेंगे, जबकि 665.97 करोड़ रुपये वेतन और विभाग की अन्य जरूरतों पर खर्च होंगे. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जायेगा. हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति बनायी जायेगी और प्रत्येक पंचायत में सुधा दूध का बिक्री केंद्र खोला जायेगा.

बकरी फेडरेशन का गठन

बकरी विकास योजना के तहत बकरी प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बकरी सीमेन स्टेशन तथा बकरी फेडरेशन का गठन किया जायेगा. वहीं सूकर प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी.

5 खेती किसानी बड़ी बातें

1. खेती किसानी-पर 3446.45 करोड़ खर्च होंगे. कुल बजट का 0.99 फीसदी राशि कृषि कार्यों पर खर्च होगी
2. राज्य में जीआइ टैग उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए बिहार कृषि एक्सीलेरेशन मिशन का होगा गठन
3. एआइ युक्त यांत्रिकी कृषि मिशनका किया जायेगा गठन. किसानों को एआइ युक्त कृषि यंत्र दिये जायेंगे
4. बिहार में फलों का उत्पादन 483.91 लाख से बढाक़र 679.19 लाख मीट्रिक टन किया जायेगा
5. 34 बाजार प्रांगण इ-नाम से जुड़ेंगे. किसान अपने उत्पादों को ऑनलाइन बाजार भाव में अब बेच सकेंगे

किसानों के लिए खुला पिटारा

संवाददाता, पटना

खेती-किसानी को हाइटेक बनाने का बजट में प्रावधान किया गया है. कृषि उत्पादन से आगे बढ़ा कर प्रोसेसिंग और देश तथा विदेशों निर्यात करने की योजना पर फोकस किया गया है.वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू की जायेगी. इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष तीन हजार रुपये अतिरिक्त राशि दी जायेगी. वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत राज्य में 73 लाख 37 हजार 217 किसानों को साल में छह हजार रुपये तीन किस्तों में दिये जा रहे हैं. अब तीन हजार रुपये जोड़कर किसानों को साल में अब नौ हजार रुपये मिलेंगे.

73 लाख किसानों को हर साल मिलेंगे तीन हजार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू होगी

80 फीसदी तक का मिल रहा अनुदान

कृषि यंत्रों को हाइटेक करने के लिए एआइ युक्त कृषि यंत्र देने का बजट में प्रावधान किया गया है. इसके लिए एआइ युक्त यांत्रिकी कृषि मिशन का गठन किया जायेगा. राज्य में अभी 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80 फीसदी तक का अनुदान दिया जा रहा है.

एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक लाख करोड़ का होगा निवेश

बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन किया जायेगा. इसमें एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. इसके तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज बनाये जायेंगे. छंटाई, ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चैंबर्स, प्रोसेसिंग सेंटर खोले जायेंगे. जीआइ टैग उत्पादों की मार्केटिंग के लिए बिहार कृषि एक्सीलेरेशन मिशन का गठन किया जायेगा. इसके तहत जीआइ टैग उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जायेगा.

उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य

सात निश्चय-3 के तहत पांच वर्षों में दलहनी फसलों का उत्पादन 3.93 लाख एमटी से बढ़ाकर 11.27 लाख एमटी, तेलहनी का 1.4 लाख से 4.81, मक्का का उत्पादन 66 लाख एमटी से बढ़ाकर 133.05 लाख एमटी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. फलों का उत्पादन, 2.58 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 3.60 लाख हेक्टेयर करने तथा उत्पादन 483.91 लाख से बढाक़र 679.19 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही सब्जियों का उत्पादन 180 लाख एमटी से बढ़ाकर 360 लाख एमटी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

कृषि कार्यों पर खर्च का ब्योरा

कार्य	राशि लाख में
उद्यान विकास पर	17000
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम अनुदान	34836-90
बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, सबौर	28870-00
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	28246-00
बीज गुणन फार्मों के विस्तार पर खर्च	18800-00
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन	17632-00
औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	15775-05
राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	14178-00
कृषि बाजार के विकास	10000-00
सभी तरह की सिंचाई योजनाओं पर	31191

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू होगी
- कृषि एक्सीलेरेशन मिशन से जीआइ टैग उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जायेगा.

स्ट्रॉबेरी का भी निर्यात करेगा बिहार

बजट में सोनाचूर, मोकरी कतरनी, मर्चा का उत्पादन, श्री अन्न के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. स्ट्रॉबेरी एवं ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जायेगा. प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जायेगी. 34 बाजार प्रांगणों को इ-नाम से जोड़ा जायेगा.

महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए विकसित किये जायेंगे हाट-बाजार

संवाददाता, पटना

महिला रोजगार

बिहार बजट में महिलाओं एवं सामाजिक समूहों पर व्यापक फोकस किया गया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांवों से लेकर शहरों तक हाट-बाजार विकसित किये जायेंगे. इस योजना के तहत अबतक 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं को रोजगारपरक गतिविधियों संचालित करने के लिए प्रति महिला 10 हजार रुपये की राशि दी गयी है. वहीं, वर्तमान में बिहार में 31,71,000 जीविका दीदियों को लखपति दीदी योजना के तहत लखपति घोषित किया गया है.

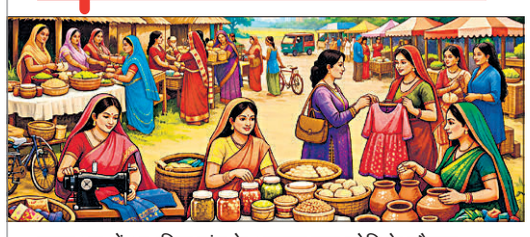

सभी जिलों में बनेंगे मेगा स्किल सेंटर

राज्य भर में आधुनिक मांग के अनुरूप उच्च कोटि के कौशल प्रशिक्षण के लिए हब एंड स्पोक माडल के आधार पर प्रथम चरण में सभी प्रमंडलों में एक-एक मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त कर प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए आधारभूत संरचना विकसित किया जा रहा है. दूसरे चरण में राज्य के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जायेगी.

22,329 आवेदकों सहित 41922 आवेदकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये नियोजन कैंप के माध्यम से

रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिये जायेंगे...

राज्य में 152 आइटीआइ में 114 सामान्य एवं 38 महिला आइटीआइ संचालित है. जिसमें 149 आइटीआइ संस्थानों को सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित कर आज के इंडस्टी 4.0 के अनुरुप नये-नये रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिये जाने की योजना है. पहले चरण में 60 आइटीआइ संस्थानों को विकसित कर अब तक कुल 7865 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है. 2025-26 में अब तक नियोजन मेला के माध्यम से 19593 आवेदकों एवं नियोजन कैंप के माध्यम से 22,329 आवेदकों सहित 41922 आवेदकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं. युवाओं को रोजगार सहायता देने के लिए एक एकीकृत इ-निबंधन एवं रोजगार पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है.

गांवों को चमकाने में कुल बजट की 6.82 फीसदी राशि की जायेगी खर्च

संवाददाता, पटना

ग्रामीण विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में दोगुना रोजगार, दोगुनी आय सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग 2026-27 में कार्य करेगा. इसके लिए ग्रामीण उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का ग्रामीण विकास विभाग काम करेगा. वर्ष 2026-27 में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण के तहत हाट विकसित किया जायेगा. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है. राज्यभर में खेल मैदान बनाये जा रहे हैं. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण में इस साल पांच लाख नये परिवारों को को शौचालय उपलब्ध कराया जायेगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास विभाग का बजट 23701.18 करोड़ रुपये का होगा. 22247.47 करोड़ रुपये योजनाओं और 1453.71 करोड़ रुपये सैलरी और विभाग के अन्य कार्यों पर खर्च किये जायेंगे. कुल बजट का 6.82 फीसदी राशि गांवों के विकास पर खर्च की जायेगी.

सहकारिता विभाग

दरभंगा व मधुबनी की चीनी मिल होगी शुरू, प्रखंडों में बनेंगे तरकारी आउटलेट्स

सहकारिता विभाग का वर्ष 2026-27 का बजट 1201.41 करोड़ रुपये का होगा. इसमें 922.74 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं और 278.67 करोड़ रुपये विभाग के अन्य कार्यों पर खर्च होंगे. मधुबनी के सकरी एवं दरभंगा के रैयाम में बंद चीनी मिलों की भूमि पर सहकारी चीनी मिल स्थापित की जायेगी.

राज्य में हल्दी प्रसंस्करण इकाई, डिहाइड्रेशन यूनिट की स्थापना, संरक्षित कृषि के लिए पॉली हाउस का निर्माण, निर्यात को बढ़ावा देने के के लिए मेगा फूड पार्क की स्थापना होगी.

1201.41 करोड़ रुपये का होगा सहकारिता विभाग का बजट

पैक्सों में बनेंगे कृषि संयंत्र बैंक

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत राज्य के सभी 8,463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किये जायेंगे. अब तक 2,972 पैक्सों का चयन किया गया है. मत्स्यपालन के क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी समितियों को बेहतर तकनीकी सहयोग एवं इनपुट उपलब्ध कराया जायेगा. इसे लेकर प्रमंडल, जिला और राज्य स्तर पर संघ का गठन होगा.

किसानों की आय व रोजगार बढ़ाने का प्रयास

एक्सपर्ट ने किया डिकोड

डॉ अविरल पांडेय
असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय

बिहार बजट 2026-27 राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं, राजनीतिक यथार्थ और विकास की मौजूदा दिशा को साफ तौर पर सामने रखता है. करीब 3.47 लाख करोड़ रुपये के कुल आकार वाला यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये अधिक है. यह बजट किसी बड़े प्रयोग या नीतिगत छलांग के बजाय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और मानव पूंजी निर्माण पर भरोसा जताता है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की वास्तविक जीएसडीपी वृद्धि दर करीब 8.6 प्रतिशत रही है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, जबकि वर्तमान कीमतों पर राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच चुकी है.

बजट की सबसे बड़ी विशेषता राजकोषीय अनुशासन है. सरकार ने राजकोषीय घाटे को लगभग तीन प्रतिशत के आसपास सीमित रखा है. शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया गया है. करीब 60,200 करोड़ रुपये, यानी कुल बजट का लगभग 17.3 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जायेगा. यह संकेत देता है कि सरकार दीर्घकालीन विकास के लिए मानव पूंजी को सबसे अहम मान रही है. वहीं पेंशन पर 35,170 करोड़ रुपये और ब्याज भुगतान पर 25,364 करोड़ रुपये का भारी बोझ यह भी दिखाता है कि वेतन, पेंशन और कर्ज से जुड़े प्रतिबद्ध खर्च बजट की बड़ी सीमा बने हुए हैं. किसानों की आय बढ़ाने का अच्छा प्रयास किया गया है. हालांकि, युवाओं के लिए कोई बड़ा रोजगार-उन्मुख कार्यक्रम सामने नहीं आता. कुल मिलाकर यह बजट युवाओं को नौकरी देने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति अपनाता है. कुल मिलाकर बिहार बजट 2026-27 सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और प्रशासनिक स्थिरता व खेती-किसानी को प्राथमिकता देने वाला बजट है. यह गरीब, बुजुर्ग और ग्रामीण आबादी को सुरक्षा प्रदान करता है और मानव पूंजी में निवेश पर भरोसा जताया है. हालांकि रोजगार सृजन, कृषि परिवर्तन, महिला आर्थिक सशक्तिकरण और निजी निवेश के मोर्चे पर यह बजट सतर्क और सीमित नजर आता है. यह एक कल्याण-प्रधान और आर्थिक रूप से सावधान बजट है.

महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पर जोर

महिलाओं के लिए बजट सामाजिक सुरक्षा और भागीदारी दोनों पर केंद्रित दिखता है. स्वास्थ्य पर 21,270 करोड़ रुपये और सामाजिक कल्याण पर 8,470 करोड़ रुपये का प्रावधान महिला स्वास्थ्य, पोषण और स्वयं सहायता समूहों को सहारा देता है. ग्रामीण विकास और पंचायती राज में महिला भागीदारी को बजटीय समर्थन मिलता है. यह बजट महिलाओं के लिए सुरक्षा तो सुनिश्चित करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की जरूरत है.

प्रभात खबर
पटना, बुधवार, 04.02.2026 11

बिहार बजट 2026-2027

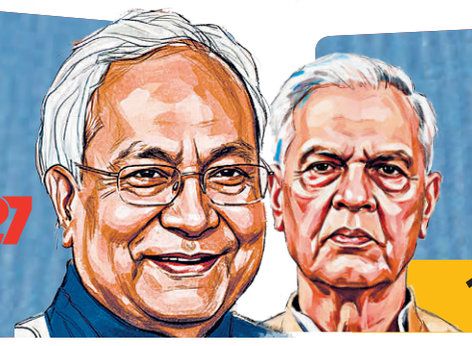

बजट छात्र, युवा, महिला, किसान व मजदूर विरोधी है. सरकार ने राज्य की जनता को दिगभ्रमित किया है. राज्य के योजना के अकार में मामूली बढ़ोतरी की गयी, जबकि प्रतिबद्ध व्यय बढ़कर 2,25,434 करोड़ रुपये हो गया है.
– रामनरेश पांडेय, राज्य सचिव, भाकपा

13.09 लाख करोड़ रुपये कुल जीडीपी आकार | **2.99%** जीडीपी का (39,111 करोड़) राजकोषीय घाटा | **1,143** करोड़ रुपये हुई राजस्व बचत | **39377** करोड़ रुपये हुई पूंजीगत खर्च

बजट में कई बड़े प्रावधान

बिहार बजट 2026-27 में सरकार ने सड़क, पुल, बिजली और शहरी सुविधाओं पर खास फोकस किया है. बुनियादी ढांचे को मजबूत कर राज्य की तस्वीर बदलने को लेकर कई बड़े प्रावधान किये गये हैं.

5 आधारभूत संरचना बड़ी बातें

1. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत हजारों किलोमीटर नयी सड़कें बनेंगी और पुरानी सड़कों को अपग्रेड कर ग्रामीण संपर्क सुधारा जायेगा.
2. गंगा, कोसी, गंडक व सोन नदियों पर नये पुल और फ्लाईओवर बनाने पर बड़ा फोकस है, जिसमें आरओबी और बाइपास परियोजनाएं शामिल हैं.
3. शहरी विकास के लिए 19 नगर निगमों, 89 नगर परिषदों और 156 नगर पंचायतों में नागरिक सुविधाओं का राष्ट्रीय मानकों पर विकास होगा.
4. पटना मेट्रो का काम तेजी जारी है, पहले कॉरिडोर पर 2025 से संचालन का लक्ष्य दोहराया गया है.261 नगर निकायों में आधुनिक कचरा प्रबंधन होगा.
5. ग्रामीण और शहरी सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण व बेहतर रखरखाव के लिए बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है.

नगर विकास एवं आवास विभाग

राज्य सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के जरिये शहरों के विकास पर रिकॉर्ड स्तर का खर्च करने जा रही है. शहरी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुल 15,237 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. यह राशि राज्य के कुल बजट का 4.38 प्रतिशत है. इसके तहत राज्य के 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 156 नगर पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर सीधा निवेश किया जायेगा.

» **आवास, स्वच्छता, परिवहन, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में शहरों की तस्वीर बदलने की तैयारी.**

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार इस समय देश में सबसे अधिक सड़क घनत्व वाले राज्यों में शामिल हो गया है. राज्य में 10 वर्ष के दौरान ग्रामीण सड़कों की लंबाई में 54 हजार 795 किमी की बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2015-16 में यह लंबाई 64 हजार 205 किमी थी अब वर्ष 2025-26 में बढ़कर एक लाख 19 हजार किमी हो गयी है. यह जानकारी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में वित्त मंत्री बिजेंद्र कुमार यादव ने मंगलवार को विधानमंडल में दी.

» **वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना में कुल तीन हजार लंबाई के ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है.**

परिवहन विभाग

बिहार में अगले पांच वर्षों में लोगों को गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति मिल जायेगी. बजट में 100 प्रतिशत डीजल से चलने वाली बसों को सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने की योजना है. राज्य में 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप की शुरुआत होगी. 2000 से भी अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनेंगे. सभी प्रखंडों - ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले सीएनजी स्टेशन व सभी प्रखंडों में एचएमवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जायेगा है. 1000 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र खोला जायेगा. साथ ही, प्रत्येक अनुमंडल में एक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.

12 साल में 14 गुणा हुआ आकार

बजट आकार (आंकड़े हजार करोड़ में)

वर्ष	राशि					
2004-05	23.88	2011-12	65.32	2019-20	200.50
2005-06	26.32	2012-13	78.68	2020-21	211.76
2006-07	29.22	2013-14	92.08	2021-22	218.30
2007-08	33.25	2014-15	116.88	2022-23	237.69
2008-09	38.57	2015-16	120.68	2023-24	261.88
2009-10	47.44	2016-17	144.69	2024-25	278.72
2010-11	53.75	2018-19	176.99	2026-27	347.589

समाज कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा. इस योजना का लाभ उन्हीं लाभुकों विभागीय बजट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह के समय पांच हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है.

» **अब तक 2025-26 में 1,538.70 लाख रुपये की राशि से लगभग 31 हजार लाभुकों को लाभ पहुंचाया गया है.**

श्रम संसाधन

बिहार में श्रमिकों को निबंधित कर श्रम योजनाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल वाहन जायेगा. कार्यस्थल पर श्रमिकों के निबंधन, नवीकरण व योजनाओं के आनलाइन आवेदन तथा प्रचार-प्रसार होना है. गंभीर रोगों से पीड़ित श्रमिकों का इलाज आसानी से बेहतर हास्पिटल में हो, इसके लिए सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के साथ समन्वय कर निजी और विशिष्ट अस्पतालों के साथ एग्रीमेंट करने की प्रक्रिया और सुलभ बनेगी.

38.732.54 करोड़ रुपये की कुल 266 सड़क और पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गयी है

05 साल में 05 नये एक्सप्रेसवे

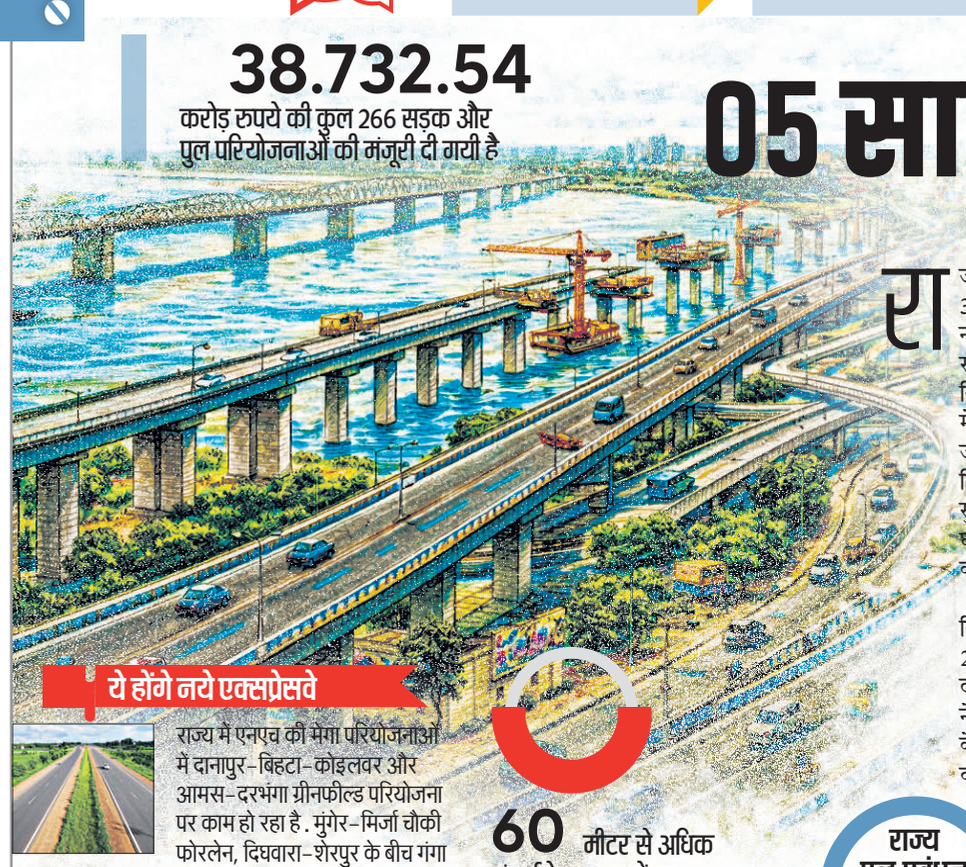

संवाददाता, पटना

राज्य में सात निश्चय-3 में वर्ष 2025-30 में सुलभ संपर्कता के लिए पांच नये एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा. साथ ही पथ निर्माण विभाग की सभी सिंगल लेन सड़कों को आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से दो लेन बनाया जा रहा है. इसका मकसद औद्योगिक विकास सहित राज्य के लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों से राजधानी पटना चार घंटे में पहुंचने की सुविधा उपलब्ध करवाना है.

यह जानकारी मंगलवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दी. इस बजट में पथ निर्माण विभाग के लिए 7404.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.

266 सड़क व पुल परियोजनाओं को मिली मंजूरी

पिछले एक साल में लगभग 38.732.54 करोड़ रुपये की कुल 266 सड़क और पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गयी है. इसमें कुल 23,974.97 करोड़ रुपये की 137 परियोजनाएं प्रगति यात्रा के तहत और 14,757.57 करोड़ रुपये की कुल 129 अन्य परियोजनाएं शामिल हैं. इन स्वीकृत योजनाओं में 35.65 किमी लंबाई में दीघा-बिहटा कोइलवर, 42 किमी लंबाई में मुंगेर (सफियाबाद)-बरियारपुर-घोरघट-सुल्तानगंज और 40.80 किमी लंबाई में सुल्तानगंज-भागलपुर-सबौर गंगा पथ परियोजना शामिल हैं.

इन परियोजनाओं पर हो रहा काम

» **मीठापुर से सिपारा एलिवेटेड पथ और सिपारा में रोड ओवरब्रिज**

» **जेपी गंगा पथ से पटना घाट संपर्कता (पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक)**

» **बख्तियारपुर-ताजपुर के बीच गंगा नदी पर पहुंच पथ के साथ फोरलेन पुल 51 किमी लंबाई**

» **कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन गंगा पुल परियोजना में हाजीपुर-महनार पथ (एनएच-122बी) से चकसिकंदर (एनएच-322) और 'रायोपुर दियारा, वैशाली से हाजीपुर-महनार पथ'**

ये होंगे नये एक्सप्रेसवे

राज्य में एनएच की मेगा परियोजनाओं में दानापुर-बिहटा-कोइलवर और आमस-दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना पर काम हो रहा है. मुंगेर-मिर्जा चौकी फोरलेन, दिघवारा-शेरपुर के बीच गंगा नदी पर सिक्स लेन पुल, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर फोरलेन पुल सहित जेपी सेतु के समानांतरर गंगा नदी पर सिक्सलेन पुल बन रहा है.

60 मीटर से अधिक लंबाई के 624 पुलों का मेंटेनेंस बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा

राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति लागू

राज्य में पुल निर्माण के साथ बने पुलों के रख-रखाव और बेहतर प्रबंधन के लिए बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 लागू की गयी है. 60 मीटर से अधिक लंबाई के 624 पुलों का मेंटेनेंस बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जायेगा. इस नयी नीति का क्रियान्वयन ब्रिज मेंटेनेंस बिडिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से कराया जायेगा. इस नीति में वर्तमान में 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 पुलों के स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट का काम आइआइटी दिल्ली और आइआइटी पटना से कराने के लिए करार किया गया है.

किस विभाग को कितनी राशि

2026-27 का बिहार का बजट राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता को दर्शाता है. कुल बजट में से बड़ी राशि विकास कार्यों और पूंजीगत खर्च के लिए रखी गयी है. इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार पर एक साथ काम किया जायेगा.

क्रम	विभाग	आवंटित राशि
1	शिक्षा विभाग	60,204
2	ग्रामीण विकास	23,701
3	स्वास्थ्य विभाग	21,270
4	गृह विभाग	20,132
5	ऊर्जा विभाग	18,737
6	नगर विकास एवं आवास	15,237
7	ग्रामीण कार्य विभाग	11,312
8	पंचायती राज विभाग	10,995
9	समाज कल्याण विभाग	8,470
10	उच्च शिक्षा विभाग	8,012
11	जल संसाधन विभाग	7,127
12	पथ निर्माण विभाग	7,404
13	भवन निर्माण विभाग	6,153
14	वित्त विभाग	3,741
15	कृषि विभाग	3,446
16	उद्योग विभाग	3,337
17	योजना एवं विकास विभाग	2,596
18	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	2,469
19	राजस्व एवं भूमि सुधार	2,190
20	SC एवं ST कल्याण	2,086
21	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन	1,915
22	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,749
23	विधि विभाग	1,736
24	युवा, रोजगार एवं कौशल विकास	1,379
25	लघु जल संसाधन	1,351
26	सामान्य प्रशासन	1,272
27	सहकारिता	1,201
28	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,195
29	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	1,075
30	विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा	1,003
31	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	896
32	सिविल उड्डयन विभाग	698
33	पर्यटन विभाग	665
34	श्रम संसाधन विभाग	371
35	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	370
36	परिवहन विभाग	351
37	गन्ना उद्योग विभाग	340
38	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	290
39	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	280
40	वाणिज्यकर विभाग	276
41	खेल विभाग	240
42	कला एवं संस्कृति विभाग	187
43	खान एवं भूतत्व विभाग	78
44	संसदीय कार्य विभाग	9.88

(सभी आंकड़े करोड़ रुपये में.)

58 लाख गरीब परिवारों के घर लगेगा सोलर प्लांट, 100 % मिलेगी सब्सिडी

संवाददाता, पटना

बजट में आर्थिक रूप से कमजोर कुटीर ज्योति श्रेणी (बीपीएल) के 58 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इन उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर ऊर्जा संयंत्र 100 प्रतिशत सब्सिडी पर लगाया जायेगा. योजना के पहले चरण में 10 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इससे गरीब परिवारों को स्थायी और सस्ती बिजली उपलब्ध होगी और बिजली बिल का बोझ भी खत्म होगा. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय भवनों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने को एक किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, दो किलोवाट के लिए 60,000 रुपये तथा तीन किलोवाट एवं अधिक क्षमता के लिए 78,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है.

बिजली विभाग

बिजली की मांग में हुई वृद्धि

राज्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ बिजली की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है. वर्तमान में राज्य में 23 से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है. वर्ष 2025-26 में बिजली की अधिकतम मांग 23 जुलाई, 2025 को बढ़कर 8,752 मेगावाट तक पहुंच गयी. वहीं, वर्ष 2026-27 में राज्य की अधिकतम मांग 9,600 मेगावाट से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है.

खास बातें

» **मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी पंचायतों में 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगी.**

» **पीरपैंती, भागलपुर में ताप विद्युत संयंत्र 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य.**

» **मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत 8.55 लाख कृषि पंप सेटों को सितंबर 2026 तक बिजली कनेक्शन.**

» **राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 220 लाख से अधिक, 83 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर.**

» **विद्युत वितरण कंपनियों का 215 करोड़ से बढ़कर 2,004 करोड़ रुपये तक पहुंचा.**

डिफेंस कॉरिडोर के साथ विकसित की जायेगी न्यू एज इकोनॉमी

संवाददाता, पटना

राज्य के कुल बजट में बेशक उद्योग विभाग की हिस्सेदारी मात्र एक (0.96%) फीसदी है. इसके बाद भी बजट में प्रस्तुत प्रावधान औद्योगिक कायाकल्प करने वाले हैं. सबसे खास ये है कि बिहार डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जायेगा. बजट में घोषणा की गयी कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाया जायेगा. साथ ही वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि राज्य में रोजगार पैदा करने के लिए न्यू एज इकॉनमी विकसित की जायेगी. इसमें आर्थिक बेहतरी के लिए पारंपरिक उद्योगों से परे खास इकॉनॉमी विकसित की जायेगी. न्यू एज इकॉनमी में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ), सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, व फिन टेक सिटी की स्थापना की जायेगी.

उद्योग विभाग

नये दौर के रोजगार

साथ ही स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जायेगा. उद्योग के लिए निर्धारित बजट में 3200 करोड़ से अधिक राशि विभिन्न औद्योगिक योजनाओं पर खर्च की जायेगी. बजट में साफ किया गया है कि बिहार सरकार का फोकस ऐसे उद्योगों को विकसित करने पर है, जो नये दौर के रोजगार सृजन करेंगे.

खास बातें

» **राज्य में वैश्विक बैंकिंग हब व आधुनिक ग्लोबल वर्कप्लेस स्थापित कर निवेश, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर**

» **औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जिलों में 20,767 एकड़ भूमि अधिग्रहित होगी, 693 एकड़ हस्तांतरण शामिल**

» **अगले वित्तीय वर्ष अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर अंतर्गत गया में आइएमसी फेज-2 विकसित कर उद्योग विस्तार को बढ़ावा.**

» **फतुहा क्षेत्र में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तथा आधुनिक फिनटेक सिटी स्थापित कर व्यापार और डिजिटल सेवाएं मजबूत होंगी.**

विकास की गति को तेज करनेवाला बजट

एक्सपर्ट ने किया डिकोड

डॉ वाइएल दास
निदेशक, शोध, बिहार विद्यापीठ

आर्थिक सर्वेक्षण ने अर्थव्यवस्था की दशा दिखायी है, जबकि बजट भावी विकास की रूप रेखा प्रस्तुत कर रही है. बिहार का 2026-27 का प्रस्तावित बजट बिहार की विकास की तीव्र प्रगति की तस्वीर प्रस्तुत करती है. बजट से यह तथ्य प्रकट होता है कि बिहार का विकास काफी तेज रहा है.2024-25 में बिहार का विकास दर 13.1 प्रतिशत रही है जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है. इसे 2026-27 में 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है. एक ओर जहां राष्ट्रीय विकास दर (7.3 प्रतिशत) से काफी अधिक है, वहीं कई अन्य राज्यों की विकास दर की तुलना में भी अधिक है. बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो 2023-24 में 68,624 रुपये थी, वह बढ़कर 76,490/-रूपये हो गयी. सात निश्चय पार्ट 3 में अगले पांच साल में इसे दो गुना करने का लक्ष्य है. बजट में इसके लिए कई प्रावधान किये गये हैं. राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, प्रोसेसिंग, ऊर्जा आदि पर व्यय की दृष्टि से भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है. इसे और गतिमान करने के लिए 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है.कुल बजट आकार तीन लाख सैतालिस हजार पांच सौ नवासी करोड़ का है, जो चालू वर्ष की तुलना में 30 हजार करोड़ से अधिक का है. इस प्रकार बजट का आकार यह संकेत देता है कि विकास की गति को तीव्र करने की संकल्पना है. शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, इत्यादि बजट की मुख्य केंद्र बिंदु है. शिक्षा पर 68,216 करोड़, स्वास्थ्य पर 21,270 करोड़ और ग्रामीण विकास पर 23,701 करोड़ रुपये का प्रावधान है. यह इस बात का द्योतक है कि सर्वाधिक आवश्यकता और सर्वाधिक महत्व शिक्षा क्षेत्र को है. औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है. इस दृष्टि से उद्योग में 50 लाख करोड़ के निजी निवेश की उद्घोषणा भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है. पांच नये एक्सप्रेसवे का निर्माण, शहरी गरीबों को आवास देने का प्रावधान और किसानों को पहले से अधिक तीन हजार रुपये सालाना देने का संकल्प सराहनीय है.

उद्योगों में रोजगार सबसे बड़ी कसौटी बनेगी

बिहार सरकार तेज विकास के लिए गंभीर और संकल्पित दिखती है. बजट की असली सफलता योजनाओं के सही और समय पर क्रियान्वयन से तय होगी. सरकारी, निजी और औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन ही इसकी सबसे बड़ी कसौटी होगा. युवाओं को अवसर देना आवश्यक है. लगभग एक करोड़ रोजगार लक्ष्य पाने के लिए चीनी मिल, जूट मिल और सूत मिल जैसे बड़े उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता देना जरूरी है. जब योजनाएँ जमीन पर दिखेंगी और लोगों की आय बढ़ेगी.